चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 9 अगस्त–15 अगस्त 2010

आख़िर कब तक मरते रहेंगे सच के सिपाही

पेज 3

कश्मीर : कैसे रुके अंतहीन हिंसा का सिलसिला?

पेज 4

कंपनी हारी जनता जीती

पेज 5

माओवादियों के ख़िलाफ़ लालगढ़ की महिलाएं

पेज 6

भाजपा और संघ की दुःख भरी कहानी

संघ ने भाजपा का अध्यक्ष नितिन गडकरी को बनवा तो दिया, लेकिन अब उसके सामने साफ़ हो गया है कि दिल्ली में बैठे अनंत कुमार, सुषमा स्वराज, वेंकैय्या नायडू, जेटली, राजनाथ सिंह और आख़िर में आडवाणी उन्हें सफल नहीं होने देंगे. इन सब में गडकरी की उम्र राजनीति में छोटी है, लेकिन संघ गडकरी को सफल होते देखना चाहता है. गडकरी ने संघ को बताया है कि जब भी वह कुछ नया करना चाहते हैं तो ये लोग उनका विरोध करते हैं. संघ और गडकरी के सामने सवाल है कि वे इस स्थिति से कैसे निकलें.

संतोष भारतीय

यह कहानी न भारतीय जनता पार्टी की है और न उसे अपना राजनैतिक चेहरा मानने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की है. यह कहानी उस दर्द की है, जिसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सच्चा स्वयं सेवक और भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता पिछले पंद्रह सालों से भोग रहा है. वह आपस में बात करता है, अफसोस ज़ाहिर करता है, आंसू गिराता है और फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि कब घड़ा भरेगा और भाजपा फिर से एक बार संघ के विचारों के आधार पर चलेगी. उसे लगता है कि मोहन भागवत की समझ शायद जगे और कुछ करिश्मा हो. संघ और भाजपा के साथ जीने–मरने के जज़्बे से जुड़े कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद भाजपा के शक्तिहीन होने की जो कहानी सामने आई है, उसकी शुरुआत लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा से होती है.

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को लगा कि वी पी सिंह की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय समाज खंड–खंड बंट गया है, इसलिए कुछ ऐसा हो कि समाज जुड़े. संघ की इस इच्छा को अटल बिहारी वाजपेयी नहीं पहचान पाए, पहचाना लालकृष्ण आडवाणी ने और उन्होंने सर संघ चालक सहित संघ के प्रमुख लोगों के सामने प्रस्ताव रखा कि वह राम को लेकर, राम मंदिर बनाने के लक्ष्य की घोषणा कर देश भर में यात्रा करेंगे. उनका कहना था कि राम ने शबरी के बेर खाए, आम आदमी के प्रतीक वानर–भालुओं को लेकर, जो उस समय के आदिवासी थे, आतंक के प्रतीक रावण पर हमला किया. राम का प्रभाव लंका, इंडोनेशिया, नेपाल मलेशिया सहित कई देशों में पाया जाता है. संघ को लगा कि इससे भारतीय समाज जुड़ेगा और उसने रथयात्रा की न केवल अनुमति दी, बल्कि उसकी पूरी तैयारी भी की.

लालकृष्ण आडवाणी का उद्देश्य शायद कुछ और था और घोषित उद्देश्य के विपरीत यात्रा कुछ ही दिनों में मुसलमानों के विरुद्ध जिहाद में बदल गई. सारे देश में ऐसा माहौल बनाया जाने लगा कि बाबरी मस्जिद गिराई भी जाएगी और मुसलमानों को सबक भी सिखाया जाएगा. इस रथयात्रा ने 1947 के बाद दूसरी बार देश में भयानक सांप्रदायिक बंटवारे की कोशिश की. वी पी सिंह की सरकार गिरी, चंद्रशेखर की सरकार बनी. सात महीने के बाद वह भी गिरी और चुनाव हुए. राजीव गांधी की हत्या हुई. चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और नरसिंहाराव प्रधानमंत्री बने. भाजपा ने चुनाव राम मंदिर बनाने के नाम पर लड़ा था, लेकिन उसे जनता ने नहीं चुना. नरसिंहाराव के कार्यकाल में भी भाजपा कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के नाम पर राम मंदिर बनाने का अभियान गांव–गांव चलाता रहा. आख़िर में अयोध्या में कारसेवा की घोषणा की गई. इस बीच विधानसभाओं के चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी. नरसिंहाराव ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, अदालत में हलफनामा देने के बावजूद कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद के ध्वंस में पूरी भूमिका निभाई. जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हो गई, तब नरसिंहाराव नींद से जागे और उन्होंने भाजपा की चार राज्य सरकारों को बर्ख़ास्त करा दिया. इसके बाद भी लोकसभा चुनावों में भाजपा को जनता ने नहीं जिताया, बल्कि पहले देवेगौड़ा और फिर गुजराल के प्रधानमंत्रित्व में सरकार बनी.

भाजपा व संघ का कार्यकर्ता निराश नहीं हुआ, बल्कि अगले चुनावों की प्रतीक्षा करने लगा. फिर आम चुनाव हुए और भाजपा ने सरकार बनाई. एक बार सरकार तेरह दिन चली और दूसरी बार तेरह महीने चली. इसके बाद चार साल के लगभग चली. शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ चुनाव में उतरी भाजपा ख़ुद अपनी चमक खो बैठी. अब यहां से आपको असली कहानी बताते हैं. भाजपा का सार्वजनिक और लोकप्रिय चेहरा हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी रहे. उनकी बात पार्टी के नेता और संघ के लोग कम मानते थे, लेकिन जनता सिर्फ़ अटल बिहारी वाजपेयी को ही पहले जनसंघ और बाद में भाजपा का चेहरा मानती रही. बलराज मधोक को पार्टी से निकालने के बाद दीन दयाल उपाध्याय अध्यक्ष बने. उनकी रहस्यमय हत्या या मृत्यु के बाद पार्टी को नया जीवनदान देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, इसीलिए क्योंकि जनता में उनकी साख बहुत थी.

पार्टी का तो हाल सिर्फ़ इस वाकये से जाना जा सकता है कि सन् 89 में उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी से निकालने की मांग कर डाली थी. कारण सिर्फ़ इतना था कि अटल बिहारी वाजपेयी कट्टर रुख़ नहीं अपना रहे थे. अटल बिहारी वाजपेयी का कद बढ़ाने में गुजरात की उस घटना ने योगदान किया, जिसमें शंकर सिंह बाघेला ने भाजपा से पहला विद्रोह किया था. शंकर सिंह बाघेला भाजपा के व्यवहार से दुःखी थे, विशेषकर नरेंद्र मोदी से. वह गांधीनगर से दूर एक गांव में अपने समर्थकों के साथ चले गए और भाजपा तोड़ने की योजना बनाने लगे. अटल बिहारी वाजपेयी गांधीनगर गए और वीवीआईपी गेस्ट हाउस में ठहरे. उन्होंने भैरो सिंह शेखावत को शंकर सिंह बाघेला से मिलने भेजा. शेखावत जी ने शंकर सिंह बाघेला से जाकर मुलाक़ात की और उन्हें वाजपेयी जी से मिलने के लिए तैयार किया. बाघेला गांधीनगर आए और अटल जी से मिले. उन्होंने अन्य तकलीफों के साथ अटल जी से कहा कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली ले जाइए, भाजपा में कलह और गुटबाज़ी इन्हीं की वजह से है. अटल जी ने बाघेला से पार्टी में बने रहने के लिए कहा, जिसे शंकर सिंह बाघेला ने मान लिया. गेस्ट हाउस से हवाई अड्डा जाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की कार को घेरा गया, हमले की कोशिश हुई और नारे लगे कि 7 करोड़ में अटल की धोती बिकी. ये सारे लोग नरेंद्र मोदी और विश्व हिंदू परिषद के थे. शंकर सिंह बाघेला की बग़ावत को रोकना अटल जी का पहली बार बड़ा कद दिखाया गया.

जब भाजपा ने एनडीए का निर्माण किया और लगा कि सरकार बन सकती है, तो सवाल आया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा. जार्ज फर्नांडिस जैसे लोगों का मूड भांप आडवाणी जी ने बयान दिया कि अटल जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे. आडवाणी भी चाहते थे और पार्टी के नेता भी चाहते थे कि आडवाणी प्रधानमंत्री बनें, पर उनका चेहरा कट्टरपंथी का चेहरा था, जिसे भाजपा के अलावा एनडीए में शामिल दूसरे दल किसी क़ीमत पर स्वीकार नहीं करने वाले थे. आडवाणी के हाथ से प्रधानमंत्री पद फिसल कर अटल जी के पास चला गया, क्योंकि वह चेहरा न केवल सार्वजनिक था, बल्कि लोकप्रिय भी था. अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ उन्हें ब्रजेश मिश्र, प्रमोद महाजन और रंजन भट्टाचार्य ने घेर लिया. शायद यह आडवाणी जी को अच्छा नहीं लगा. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बहुत से विश्वसनीय कार्यकर्ता मानते हैं कि यही वह समय था, जब आडवाणी जी ने अटल जी और पार्टी के साथ संघ से भी बदला लेने की जाने या अनजाने कोशिश शुरू कर दी. अटल जी यदि सरकार आडवाणी जी को चलाने देते तो शायद यह न होता, पर सरकार तो ब्रजेश मिश्र, प्रमोद महाजन और रंजन भट्टाचार्य के क़ब्ज़े में चली गई थी.

संघ के समर्पित नेताओं का कहना है कि आडवाणी जी ने गृहमंत्री रहते हुए एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को स्वीकार किया और पार्टी का प्रोग्राम छोड़ दिया. सालों से राम मंदिर बनाने की घोषणा करने वाली पार्टी का आडवाणी जैसा नेता कहने लगा कि जब भाजपा का बहुमत अकेले दम पर होगा, तभी मंदिर बनाया जा सकता है. संघ के लोगों का कहना है कि आडवाणी घुट रहे थे, उन्हें लगता था कि सब बनाया उन्होंने है और उन्हें ही मौक़ा नहीं मिला. इसीलिए किसी दूसरे दल ने अपने दल का एजेंडा नहीं छोड़ा, लेकिन भाजपा ने छोड़ दिया, जिसके पीछे केवल आडवाणी का दिमाग़ था. इसमें उन्हें प्रमोद महाजन का साथ मिला. संघ के लोगों का कहना है कि आडवाणी चाहते तो अटल जी लालकिले से घोषणा कर सकते थे कि मैं गठबंधन का प्रधानमंत्री हूं, पर पार्टी अलग है. इससे पार्टी पर लोगों का विश्वास नहीं टूटता और न कार्यकर्ता नाराज़ होता कि भाजपा ने मंदिर मुद्दा तो छोड़ ही दिया है.

आडवाणी जी ने अपनी नई टीम बनाई, जिसके लेफ्टिनेंट अरुण जेटली, अनंत कुमार, वेंकैय्या नायडू, सुषमा स्वराज, यशवंत सिन्हा और नरेंद्र मोदी थे. अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी रणनीति बनाने लगे और पार्टी के भीतर का सत्ता और वैचारिक समीकरण बदलने लगा. संघ के लोगों का

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

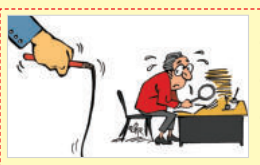

विभागीय जांच संबंधी कार्रवाइयों में रोड़े अटकाने वाले बाबुओं पर लगाम कसने की शुरुआत कर दी है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

निशाने पर सेवानिवृत्त अधिकारी

यह बात लंबे समय से महसूस की जा रही है कि सूचना आयोग में सेवानिवृत्त बाबुओं की उपस्थिति से सूचना अधिकार क़ानून के क्रियान्वयन में बाधा ज़्यादा होती है. मुंबई के कृष्णराज राव और कई आरटीआई कार्यकर्ताओं के एक अध्ययन के मुताबिक़, 20 राज्यों के सूचना आयोगों के सदस्यों में क़रीब 52 प्रतिशत प्रशासनिक एवं सरकारी महकमों से जुड़े रहे हैं. इनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं. राव कहते हैं कि अगर सूचना आयोग के सदस्यों की चयन प्रक्रिया ही नौकरशाहों के पक्ष में होगी तो आयोग के कामकाज में निष्पक्षता और पारदर्शिता की उम्मीद कैसे की जा सकती है. हालांकि अब यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग समेत सूचना आयोगों में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की जगह ऐसे लोगों को शामिल किया जाए, जो नौकरशाह न रहे हों. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह अभियान मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह की सोच को प्रभावित करने में कामयाब हो पाता है या नहीं.

दूरसंचार विभाग की मुश्किलें

दूरसंचार विभाग की उलझनें दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही हैं. हाल में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर दूरसंचार निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की ख़राब हालत को सुधारने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था, लेकिन दूरसंचार विभाग के बाबू इस समिति की सलाहों को लेकर ज़्यादा उत्साहित नज़र नहीं आ रहे हैं. दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष एवं दूरसंचार सचिव पी जे थॉमस ने अब पित्रोदा कमेटी की सिफ़ारिशों पर विचार करने के लिए एक अंतरिम कमेटी बनाने का निर्णय किया है. आश्चर्यजनक बात यह है कि ख़ुद थॉमस भी पित्रोदा पैनल के सदस्य थे और अब उन्हें अपनी ही सिफ़ारिशों पर निर्णय लेना है. पित्रोदा ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के शीर्ष पदों को भरने के लिए निजी क्षेत्र की ओर रुख़ करने की सिफ़ारिश की है. दूरसंचार विभाग ने सेवानिवृत्त हो रहे मौजूदा बीएसएनएल प्रमुख कुलदीप गोयल का उत्तराधिकारी तलाश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और विभागीय अधिकारियों का यह मानना है कि इस प्रक्रिया में पुरानी परंपरा का ही निर्वाह किया जाना चाहिए. पता नहीं आगे क्या होगा? उम्मीद है, आप भी मेरी तरह अनुमान ही लगा रहे होंगे.

अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे

वैश्विक निवेशकों की बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी के बाद यह अति उत्साह हो सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्नाटक सरकार का मनोबल अभी भी चौथे आसमान पर है. राज्य के मुख्य सचिव एस वी रंगनाथ की मानें तो नौकरशाहों को अपनी कार्यप्रणाली में काफी सुधार की ज़रूरत है. इसी उद्देश्य से उन्होंने विभागीय जांच संबंधी कार्रवाइयों में रोड़े अटकाने वाले बाबुओं पर लगाम कसने की शुरुआत कर दी है. यह निर्णय रंगनाथ द्वारा नियुक्त कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है, जिसके अध्यक्ष कर्मचारी एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) के सचिव के आर श्रीनिवास थे. पैनल ने अपनी रिपोर्ट में जांच प्रक्रिया में देरी के लिए नौकरशाहों की अक्षमता को दोषी ठहराया है. कई ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें अधिकारियों पर जांच प्रक्रिया से दूर भागने और शुभचिंतक बाबुओं द्वारा आरोपों को निरस्त करवाने के आरोप लग चुके हैं. तमतमाए रंगनाथ ने अब आदेश दिया है कि सभी अटकी हुई जांच कार्रवाइयों को 9 महीने के भीतर पूरा किया जाए. अब यह देखना रोचक होगा कि इससे बाबुओं पर क्या असर पड़ता है.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

कौन होगा एनएचएआई का चेयरमैन?

एनएचएआई के नए चेयरमैन की नियुक्ति पर अब तक पर्दा गिरा ही हुआ है. एनएचएआई के वर्तमान चेयरमैन बृजेश्वर सिंह अगले महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इस पद के लिए दो आईएएस और एक आईपीएस यानी तीन अधिकारियों का इंटरव्यू भी हुआ है, जिनके नाम हैं ब्रह्मदत्त, एम वी कृष्णा और दिनेश राय. अब इन नामों में किसका चयन होता है, इसका ख़ुलासा जल्द ही हो सकता है. एनएचएआई के नए चेयरमैन का कार्यकाल पांच साल या 65 साल की उम्र तक का होगा.

सान्याल अतिरिक्त सचिव

आईएएस अधिकारी नीलांजन सान्याल उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम रहे हैं. नीलांजन अब अतिरिक्त सचिव की सूची में शामिल किए गए हैं. वह 1979 बैच और उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं.

नई चुनाव आयुक्त महिला होगी!

मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला के सेवानिवृत्त होने के बाद अब इस बात की सबसे ज़्यादा संभावना बन रही है कि एक महिला आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त के पद पर बैठाया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक़, महिला आईएएस अधिकारी सुषमा नाथ इस पद के लिए मजबूत दावेदार हैं. सुषमा 1974 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी हैं. गौरतलब है कि महिला चुनाव आयुक्त बनाने की योजना यूपीए सरकार की महिला सशक्तिकरण नीति से भी मेल खाती है. ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई महिला अधिकारी चुनाव आयुक्त के पद तक पहुंचेगी. इससे पहले वी एस रामादेवी भी मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाल चुकी हैं. हालांकि उनका कार्यकाल महज 6 नवंबर से 11 दिसंबर 1990 तक ही रहा.

शादी और तबादला

आजकल युवा अधिकारियों के लिए शादी का मौसम चल रहा है. इसी बहाने और इसी आधार पर उक्त अधिकारी मनपसंद जगह पर तबादला भी करा रहे हैं. आईएएस अधिकारी पूनम टी गुहा का शादी की दलील पर उड़ीसा स्थानांतरण हो गया है, जबकि आईएएस अधिकारी नंद कुमारुम भी इसी आधार पर मध्य प्रदेश कैडर में तबादला पा चुके हैं.

भाजपा और संघ की दुःख भरी कहानी

पृष्ठ 1 का शेष

गुस्सा अरुण जेटली पर है, जिनके बारे में वे कहते हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा पार्टी का अहित किया है. उदाहरण के रूप में इन समर्पित लोगों का कहना है कि अरुण जेटली ने अयोध्या में अविवादित भूमि को विवादित भूमि से जोड़ दिया, जहां मंदिर बन सकता था. अरुण जेटली के लड़े बहुत से मुक़दमों को भी संघ को लोग घृणा से देखते हैं. यहां भी एक उदाहरण दिया जाता है, स्टेनली मोर्गन का, जिसे जेटली ने बचाया. वह जानते थे कि इससे देश को नुक़सान है, फिर भी उन्होंने मोर्गन का मुक़दमा लड़ा. जेटली ने एक बार कहा कि वह उनका प्रोफेशन है, इसलिए उसका विचार से कोई संबंध नहीं है. आज संघ के लोग कहते हैं कि पार्टी की दुर्दशा का मुख्य कारण अरुण जेटली हैं, जो विचार को जीवन से अलग मानते हैं. संघ के लोगों को अफसोस है कि एक ओर दीनदयाल उपाध्याय जैसा व्यक्ति उनकी पार्टी बना रहा था, जिसका आचार, विचार और व्यवहार एक था, आज अरुण जेटली पार्टी बना रहे हैं, जिनके आचार, विचार और व्यवहार में कोई समानता नहीं है.

संघ में अपना जीवन देने वाले स्वयं सेवकों का कहना है कि अरुण जेटली की रणनीति के परिणामस्वरूप विचारवान और संघ के प्रति निष्ठावान लोग पार्टी में हाशिये पर चले गए या पार्टी से बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए. वहीं पार्टी में जनाधार विहीन, एरिस्ट्रोकेट व पश्चिमी शैली में जीवन जीने वाले नेता स्थापित हो गए. ये ऐसे लोग हैं, जो ऐशोआराम में पल रहे हैं और विचारधारा से दूर हैं. आडवाणी, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली की वजह से जो लोग भाजपा के दृश्य से ग़ायब हो गए, उनमें पहला नाम हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का है, जिन्हें भारत के सर्वाधिक ईमानदार मुख्यमंत्रियों में माना जाता है. जम्मू कश्मीर में चमन लाल गुप्त हाशिये पर चले गए हैं. उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी और लालजी टंडन ख़ामोश हो गए हैं. झारखंड में बाबूलाल मरांडी ने पार्टी छोड़ दी और करिया मुंडा ने पार्टी मामलों में रुचि लेनी बंद कर दी है. मध्य प्रदेश में पहले उमा भारती के ज़रिए सुंदरलाल पटवा को किनारे कराया, फिर उमा भारती को ही पार्टी से निकाल दिया. अब शिवराज सिंह चौहान उनके अपने आदमी हैं. महाराष्ट्र में तो सारे ग्रासरूट नेता प्रमोद महाजन के लिए हाशिये पर फेंक दिए गए, केवल गोपीनाथ मुंडे बच गए, क्योंकि वह प्रमोद महाजन के रिश्तेदार थे. गुजरात में पहले शंकर सिंह बाघेला को निकालने के लिए स्थितियां बनाईं. बाद में हीरेन पंड्या का नंबर आया. राजस्थान में भैरो सिंह शेखावत को दिल्ली लाकर वसुंधरा राजे के लिए मैदान खुला छोड़ दिया गया. आंध्र प्रदेश में वेंकैय्या नायडू के लिए पूरी पार्टी की बलि चढ़ा दी गई. आज वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, वेंकैय्या नायडू, अनंत कुमार इन तीनों के मुख्य हथियार बने हुए हैं.

भाजपा में लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली का डेडली काम्बीनेशन है. लालकृष्ण आडवाणी का मानना था कि यदि उन्हें प्रधानमंत्री घोषित कर चुनाव लड़ा जाएगा तो देश भाजपा को वोट देगा. इस विचार को अरुण जेटली ने अपने तर्कों से पुष्ट कर आडवाणी के मन की आख़िरी हिच दूर कर दी. लेकिन जनता ने आडवाणी के चेहरे को अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे से बेहतर नहीं माना. नरेंद्र मोदी के बारे में संघ के निष्ठावान लोगों का कहना है कि वह हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं. बदला चुकाने की उनकी मानसिकता है, वह किसी का विरोध भूल नहीं पाते. उनके लिए सिर्फ़ साध्य महत्वपूर्ण है, साधन नहीं, किसी भी तरह से हो, उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए. बेहद प्रचार कर अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने एकमात्र उपाय के रूप में पेश करना तथा सबको साथ ले चलने की जगह अपनी इच्छा लादना उनकी आदत है. अपने लिए लॉबी बनवाना तथा अपने को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानना नरेंद्र मोदी का स्वभाव है. इस तिकड़ी के तीसरे व्यक्ति अरुण जेटली बड़े वकील हैं. वह विद्यार्थी परिषद में थे तथा छात्र राजनीति में उन्होंने बड़ी हैसियत पाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने वकालत की ज़िंदगी शुरू की, वह संघ के राष्ट्रहित और राष्ट्रप्रेम के बुनियादी सिद्धांत भूल गए. देश का नेता बनने के लिए जिस बुनियादी गुण को संघ प्रमुख मानता है, अरुण जेटली के लिए वह बेमानी है. संघ के लोगों के पास अरुण जेटली द्वारा लड़े गए मुक़दमों की लंबी सूची है. संघ के लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अरुण जेटली बड़े वकील तो बन गए, पर बड़े नेता बनने के सारे गुण भूल गए. आज अरुण जेटली अकेले हैं, जिनसे देश के पूंजीपतियों के संबंध हैं. नब्बे में जब आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जगह लेने के लिए अपने लोगों की टीम बनाई थी, तब इनका दर्जा लेफ्टिनेंट का था. आज जब आडवाणी बूढ़े हो गए हैं तो उनके सारे लेफ्टिनेंट जनरल हो गए हैं और आडवाणी उनकी बात कहने वाले नेता मात्र रह गए हैं. इस तिकड़ी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बीजेपी के रिश्ते की कड़ियों को भी प्रभावित किया है.

संघ के लोगों का कहना है कि भाजपा की असली ताक़त वे हैं तथा चुनाव के समय बूथ तक का मैनेजमेंट वे करते हैं. इसीलिए भाजपा की संरचना में संगठन मंत्री का बड़ा महत्व है, जो संघ द्वारा भेजा व्यक्ति होता है. इस पद पर सुंदर सिंह भंडारी, गोविंदाचार्य, नरेंद्र मोदी, संजय जोशी जैसे व्यक्ति रह चुके हैं और आज रामलाल संगठन मंत्री हैं. इस पद की हैसियत को बर्बाद करने की कहानी भी दिलचस्प है. आज तो संगठन मंत्री डरा हुआ है, क्योंकि वह अपने पहले के दो संगठन मंत्रियों का हश्र देख चुका है. भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में ढाई करोड़ रुपये की चोरी हुई. इसकी जांच की मांग न भाजपा में किसी ने की और न भाजपा के संगठन मंत्री रामलाल ने, जो बुनियादी तौर पर संघ के प्रतिनिधि हैं. ऐसा लगता है मानों पूरा तंत्र सड़ने लगा है.

गोविंदाचार्य को संघ ने अपना प्रतिनिधि बना भाजपा में संगठन मंत्री के तौर पर भेजा. गोविंदाचार्य के ऊपर संघ को पूरा भरोसा था कि वह भाजपा को भटकने नहीं देंगे. गोविंदाचार्य भाजपा को हमेशा संघ की विचारधारा पर चलने के लिए प्रेरित भी करते थे और दबाव भी डालते थे. मज़बूत होती तिकड़ी को गोविंदाचार्य का तरीक़ा पसंद नहीं आया और उन्होंने अटल जी का वैसे ही इस्तेमाल किया, जैसे बाद में उमा भारती का किया था. गोविंदाचार्य संघ के व्यक्ति थे, लेकिन भाजपा में रहते उनका चेहरा सार्वजनिक हो गया और वह कार्यकर्ताओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गए. गोविंदाचार्य को हटाने की रणनीति बनी और उन पर एक महिला राजनेता से नज़दीकी का आरोप लगाया गया. अचानक अख़बारों में गोविंदाचार्य और उस महिला राजनेता के संबंधों की खबरों की बाढ़ आ गई. गोविंदाचार्य इस घटिया राजनैतिक हमले से इतने आहत हो गए कि उन्होंने भाजपा से अपने को दूर कर लिया. यह घटना 1999 में हुई.

संघ ने नरेंद्र मोदी को भाजपा का संगठन मंत्री बनाकर भेजा. नरेंद्र मोदी का उद्देश्य गुजरात था और केशो भाई पटेल थे. वह हमेशा से गुजरात के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे. उन्होंने संघ को तैयार किया कि उन्हें गुजरात भेजा जाए. संघ इसके लिए मान गया और उसने नरेंद्र मोदी को वापस गुजरात और संजय जोशी को भाजपा का संगठन मंत्री बनाया, जो अब तक गुजरात संभाल रहे थे.

संजय जोशी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में ही वह संघ के संपर्क में आए. भाऊराव देवरस की सलाह पर उन्होंने इंजीनियरिंग की प्राध्यापकी से त्यागपत्र दे दिया और संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए. भाऊराव देवरस ने पाया कि संजय जोशी जल्दी फ़ैसला लेते हैं तथा ग्रासरूट वर्कर हैं. वह लो प्रोफाइल हैं तथा महत्वाकांक्षाविहीन हैं. अत: उन्होंने संजय जोशी को भाजपा का अहमदाबाद नगर का संगठन मंत्री बनवा दिया. पांच साल बाद उन्हें भाजपा की गुजरात इकाई का राज्य सचिव बना दिया गया. जब नरेंद्र मोदी गुजरात वापस गए तो संजय जोशी को 2001 में भाजपा का राष्ट्रीय संगठन मंत्री बना दिया गया. बस यहीं से नरेंद्र मोदी की जलन संजय जोशी से शुरू हो गई. वह यह हज़म नहीं कर पाए कि गुजरात का ही कोई व्यक्ति उनकी जगह कैसे उनसे ज़्यादा योग्य माना गया और संगठन मंत्री बना दिया गया.

संजय जोशी स्वभाव में बिलकुल नरेंद्र मोदी से उलट थे. वह लो प्रोफाइल, साधारण रहन–सहन में विश्वास करने वाले, जैसा प्रचारक करते हैं या समाजवादी और साम्यवादी रहते हैं, साध्य के साथ साधन को भी उतना ही महत्व देते हैं, प्रचार से दूर रहने वाले, सबसे मिलने वाले और सबकी सुनने वाले, लॉबी बनाने के ख़िलाफ़ तथा ग्रासरूट काम में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं. उन्होंने संगठन मंत्री रहते हुए भाजपा पर संघ के विचारों पर चलने के लिए हमेशा दबाव बनाए रखा. भाजपा कार्यकर्ता अध्यक्ष के यहां कम, संजय जोशी के यहां ज़्यादा जाता था. इसी बीच आडवाणी पाकिस्तान गए और उन्होंने लाहौर में जिन्ना को लेकर मशहूर लाइन लिखी. संघ ने जोशी से कहा कि वह आडवाणी से इस्तीफ़ा ले लें. संजय जोशी ने बिना हिचक आडवाणी से अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा ले लिया. संजय जोशी ने संघ की बात मान अपने लिए राजनैतिक क़ब्र खोद ली. अचानक भाजपा के मुंबई अधिवेशन में एक सीडी बंटी. इस सीडी में एक व्यक्ति एक महिला के साथ था तथा अफवाह फैली कि यह व्यक्ति भाजपा का संगठन मंत्री संजय जोशी है. संजय जोशी ने भी गोविंदाचार्य की तरह तत्काल अपना त्यागपत्र दे दिया. अब जाकर तथ्य सामने आ रहे हैं और सीडी की सच्चाई भी सामने आ रही है.

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की जांच जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई ने प्रारंभ की, तब अचानक उसे बालकृष्ण चौबे ने बताया कि संजय जोशी के ख़िलाफ़ तथाकथित सेक्स सीडी उसी ने अन्य अफसरों के साथ भाजपा अधिवेशन में बांटी थी. बालकृष्ण चौबे गुजरात एटीएस में इंस्पेक्टर थे. उन्होंने सीबीआई से कहा कि यह सीडी फ़र्ज़ी है, गुजरात में बनी है और इसे एटीएस के बड़े अधिकारी के कहने पर बनाया गया, जिसे बंटवाने में वह ख़ुद शामिल हैं. इसमें नरेंद्र मोदी का इशारा था या अमित शाह का, अभी यह खुलासा आना बाक़ी है, लेकिन संजय जोशी को बरबाद करने के तार इन्हीं दोनों से जुड़े हैं. संजय जोशी की मदद हरेन पंड्या और गोरधन झड़पिया करते थे. संघ के सुदर्शन से लेकर मोहन भागवत तक संजय जोशी की संगठन क्षमता के कायल और राजनैतिक दक्षता के प्रशंसक थे. लेकिन इस फ़र्ज़ी सीडी ने उन्हें विवादास्पद बना दिया. बाद में यह सीडी हैदराबाद की फोरेंसिक लैब में फ़र्ज़ी पाई गई और संजय का चेहरा किसी के धड़ पर लगा साबित हुआ.

एक नई बात भाजपा के कोनों से फैलाई जा रही है कि संजय जोशी की सीडी में दिख रही महिला सोहराबुद्दीन की पत्नी कौसर बी जैसी है. सीबीआई ख़ामोश है कि दो दिन तक कौसर बी गुजरात एटीएस के क़ब्ज़े में जिस बंगले में थी, वहां क्या हुआ. शायद सीबीआई के पास इसका जवाब है और हो सकता है, वह अदालत में इसका खुलासा करे. आज संघ के दिवंगत नेता और जीवित नेता शर्म से ख़ुद से आंखें चुरा रहे होंगे कि यह कैसा संगठन है, जिसके मुखिया अपने ही कार्यकर्ताओं को सेक्स के फ़र्ज़ी जाल में फंसा रहे हैं.

संघ के निष्ठावान लोग दु:खी हैं तथा वे अपने भोलेपन को अब अपनी मूर्खता मानते हैं. उनका कहना है कि हमारा संगठन साधु स्वभाव के लोगों का संगठन है तथा राष्ट्र के लिए प्राण देने का जज़्बा रखता है. उनके प्रमुखों को छद्म नहीं आता तथा यदि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति ने कुछ कहा, जिस पर वे विश्वास करते आए हैं, तो उसे मान लेते हैं. लालकृष्ण आडवाणी को संघ में लालजी के नाम से पुकारते हैं. लालजी ने ही सुषमा स्वराज, वेंकैय्या नायडू और अरुण जेटली को संघ की नज़र में सर्वश्रेष्ठ बनाया. अब जब संघ हक़ीक़त का सामना कर रहा है तो इस संकोच में है कि परिवार के मुखिया को दु:ख कैसे पहुंचाए. हालांकि संघ के सामने अब स्पष्ट हो गया है कि संघ से रिश्ता रखने वाले लोगों को कैसे भाजपा में हाशिये पर डाला गया. यहां तक कि संघ के लोगों को टिकट नहीं दिए गए तथा दिए गए तो वहां से, जहां वे हार जाएं.

संघ के सामने अब यह भी साफ हो गया है कि अरुण जेटली, वेंकैय्या नायडू, जसवंत सिंह, सुषमा स्वराज व यशवंत सिन्हा न कभी वैचारिक लड़ाई लड़ सकते हैं और न वैचारिक हमला या वैचारिक बचाव कर सकते हैं. और विडंबना यह है कि यही लोग आज भाजपा की पहचान हैं. इसीलिए संघ को लगता है कि भाजपा अपनी पहचान एक सार्थक विरोधी दल के रूप में खो चुकी है और कांग्रेस का दूसरा चेहरा बन गई है. आज भाजपा में आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी के अलावा कोई वोट खींचने वाला चेहरा नहीं बचा है. देश के लोग इन दोनों के अलावा गोविंदाचार्य और उमा भारती को जानते हैं. लेकिन जसवंत सिंह को लेने में जितनी जल्दी दिखाई जाती है, गोविंदाचार्य और उमा भारती का नाम तक भाजपा में नहीं लिया जाता है. संघ के सिद्धांतशास्त्री माने जाने वाले एम जी वैद्य ने अपने लेख में लिखा है कि जसवंत सिंह को लिया तो ठीक किया, न लेते तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन गोविंदाचार्य, उमा भारती और संजय जोशी को लेते तो पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा होता. भाजपा को चलाने वाला गुट इसे एम जी वैद्य की सनक कहता है.

संघ ने भाजपा का अध्यक्ष नितिन गडकरी को बनवा तो दिया, लेकिन अब उसके सामने साफ हो गया है कि दिल्ली में बैठे अनंत कुमार, सुषमा स्वराज, वेंकैय्या नायडू, जेटली, राजनाथ सिंह और आख़िर में आडवाणी उन्हें सफल नहीं होने देंगे. इन सब में गडकरी की उम्र राजनीति में छोटी है, लेकिन संघ गडकरी को सफल होते देखना चाहता है. गडकरी ने संघ को बताया है कि जब भी वह कुछ नया करना चाहते हैं तो ये लोग उनका विरोध करते हैं. संघ और गडकरी के सामने सवाल है कि वे इस स्थिति से कैसे निकलें. संघ के एक निष्ठावान ने तो कहा कि गडकरी अगर ज़्यादा कुछ करना चाहेंगे तो एक सीडी उनके ख़िलाफ़ भी आ जाएगी.

दूसरी ओर संघ का रिश्ता गोविंदाचार्य और संजय जोशी से वैसे ही बना हुआ है, जैसे पहले था. संघ के सात बड़े हैं, मोहन भागवत, भैय्या जी जोशी, दत्तात्रेय होशबोले, एम जी वैद्य, सुरेश सोनी, मदनदास देवी और इंद्रेश जी. इन सबसे गोविंदाचार्य और संजय जोशी का हर दूसरे दिन का मेलमिलाप चल रहा है. मोहन भागवत, भैय्या जी जोशी और मदनदास देवी गोविंदाचार्य के ख़ास संपर्क में हैं. इन दिनों संघ की ओर से सुरेश सोनी भाजपा को देख रहे हैं, लेकिन मदनदास देवी भाजपा का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं. संघ के लोगों का कहना है कि अकेले मदनदास देवी हैं, जो अरुण जेटली को संरक्षण दे रहे हैं. हालांकि बाक़ी लोग अरुण जेटली और उनके साथियों की वजह से हुई भाजपा की हालत से दु:खी और चिंतित हैं.

सब भाजपा को साख वाले विपक्षी दल के रूप में देखना चाहते हैं. संघ के लोग दु:खी हैं कि उनकी इज़्ज़त केवल बची हुई है, साख समाप्त हो रही है. इसका असर संघ पर भी पड़ा है. अब प्रचारक सिर्फ़ अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तथा भाजपा में जाने और चुनाव लड़ने का रास्ता इसे मानते हैं. जो प्रचारक सीधे राजनीति में नहीं जा पाते, वे गॉड फादर का रोल तलाशने लगते हैं. भाजपा के द्वारा आए इस रोग से संघ के लोग परेशान हैं. संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता ही नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में काम करने वाले लोग भी खुलेआम इस स्थिति से चिंतित हैं तथा बिना डर के कहते हैं कि गोविंदाचार्य, संजय जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और बाबूलाल मरांडी जैसे लोगों को तत्काल भाजपा में वापस बुलाना चाहिए. इनका मानना है कि किसी को निकालने या सज़ा देने की जगह अगर ये वापस आते हैं तो भाजपा की अगले आम चुनाव में लड़ाई में वापसी हो जाएगी. संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता मोहन भागवत और भैय्या जी जोशी की तरफ़ देख रहे हैं कि कब उनकी नींद टूटती है और ज़ुबान खुलती है. संघ के साथ जीवन गुजार रहे एक कार्यकर्ता का कहना है कि अरुण जेटली, मोदी और आडवाणी के बारे में पता नहीं, लेकिन गोविंदाचार्य और संजय जोशी की लाशें झंडेवालान ज़रूर जाएंगी.

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 22
दिल्ली, 9 अगस्त–15 अगस्त 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9899815169
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

यूपीए सरकार जिस सूचना क़ानून को अपनी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताती है, उसका क्या हश्र हो रहा है, इस पर भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह को ध्यान देना होगा.

सात माह, आठ क़त्ल

आख़िर कब तक मरते रहेंगे सच के सिपाही

आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है यानी सूचना का अधिकार. लेकिन आप सिर्फ़ वैसे ही सवाल पूछ सकते हैं, जिनसे शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को परेशानी न हो. अगर परेशानी बढ़ी तो पहले आपको चुप कराने की कोशिश की जाएगी. फिर भी न माने तो आपकी हत्या करा दी जाएगी, क्योंकि हत्यारों को मालूम है कि नेता, अफसर और पुलिस इस भ्रष्ट व्यवस्था के संचालक हैं, भागीदार हैं, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा.

शशिशेखर

सात महीने में आठ कत्ल, क्योंकि इन लोगों ने एक सवाल पूछा था. इनके सवालों ने अवैध खनन करने वालों की पोलपट्टी खोल दी थी. भूमि घोटाले का पर्दाफाश भी इन्हीं सवालों के ज़रिए हुआ था. ये ऐसे सवाल थे, जिनसे भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई थी. सच और सूचना के ये सिपाही भ्रष्टाचारियों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन गए थे. नतीजतन, पिछले सात महीनों में आठ आरटीआई कार्यकर्ता अपनी जान गवां चुके हैं. बीती 20 जुलाई को ही अहमदाबाद में आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. सूचना के अधिकार क़ानून के तहत सतीश शेट्टी ने महाराष्ट्र में कई जमीन घोटालों और मुंबई–पुणे एक्सप्रेस–वे में घोटाले को उजागर किया था. इसी वजह से सतीश भू–माफ़ियाओं के निशाने पर आ गए थे. आरटीआई की सहायता से सतीश ने अवैध बंगले के निर्माण और मिट्टी के तेल एवं राशन की कालाबाज़ारी के विरोध में भी आवाज़ उठाई थी.

मई, 2010 में महाराष्ट्र के ही दत्ता पाटिल, जो अन्ना हजारे के क़रीबी सहयोगी भी थे, की हत्या कर दी गई. पाटिल आरटीआई के ज़रिए भ्रष्टाचार के कई मामले सामने लाए थे, जिसकी वजह से एक पुलिस उपाधीक्षक और एक वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर को नौकरी से हटा दिया गया था. नगर निगम के अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी शुरू हो गई थी. पाटिल ने एक बिल्डर के ख़िलाफ़ भी कई मामले पुलिस में दर्ज कराए थे. सच और ईमानदारी से काम करने वाले पाटिल को इन सबकी क़ीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी. अप्रैल, 2010 में महाराष्ट्र के विट्ठल गीते की हत्या भी इसलिए कर दी गई, क्योंकि उन्होंने आरटीआई के इस्तेमाल से गांव के एक स्कूल में चल रही धांधली का पर्दाफाश किया. बाद में एजूकेशनल सोसायटी चलाने वाले एक दबंग आदमी के बेटे ने गीते पर हमला कर दिया. इन सारी घटनाओं में जो समानता दिखती है, वह यह है कि सभी मामलों के आरोपी ताक़तवर लोग हैं. अप्रैल, 2010 में ही आंध्र प्रदेश के सोला रंगाराव को सवाल पूछने की क़ीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. राव ने अपने गांव में नाला निर्माण के लिए जारी किए गए फंड के बारे में सवाल पूछे थे. राव के परिवारवालों का आरोप है कि राव की हत्या में वही लोग शामिल हैं, जिन्होंने नाला निर्माण के फंड से पैसे चुराए हैं. फरवरी, 2010 में बिहार के बेगूसराय निवासी शशिधर मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. उन्हें लोग खबरी लाल के नाम से जानते थे, क्योंकि उन्होंने कई घोटालों का भंडाफोड़ किया था. ज़ाहिर है, कुछ लोगों को यह सब पसंद नहीं आया होगा. नतीजा यह निकला कि शशिधर मिश्रा के सिर में गोली मार दी गई. यानी सच का एक और सिपाही मारा गया.

कौन कब हुआ शहीद

1. 13 जनवरी, 2010	सतीश शेट्टी, महाराष्ट्र.
2. 11 फरवरी, 2010	विश्राम लक्ष्मण डोदिया, गुजरात.
3. 14 फरवरी, 2010	शशिधर मिश्रा, बिहार.
4. 26 फरवरी, 2010	अरुण सावंत, महाराष्ट्र.
5. 11 अप्रैल, 2010	सोला रंगाराव, आंध्र प्रदेश.
6. 21 अप्रैल, 2010	विट्ठल गीते, महाराष्ट्र.
7. 26 मई, 2010	दत्ता पाटिल, महाराष्ट्र.
8. 20 जुलाई, 2010	अमित जेठवा, गुजरात.

यहीं हुई थी शेट्टी की हत्या. सतीश शेट्टी, आरटीआई कार्यकर्ता.

कोर्ट परिसर में पड़ी जेठवा की लाश. अमित जेठवा, आरटीआई कार्यकर्ता.

जेठवा ने गीर के जंगलों में अवैध खनन के मामले का पर्दाफाश किया था. पुलिस उनकी हत्या के पीछे खनन माफ़िया का हाथ होने की बात कह रही है, लेकिन जेठवा के पिता भीखू भाई अपने बेटे की हत्या के पीछे भाजपा नेता एवं सांसद दीनू भाई सोलंकी का हाथ होने की बात कह रहे हैं. वैसे इस आरोप में दम भी है, क्योंकि जेठवा ने भाजपा सांसद दीनू भाई सोलंकी के ख़िलाफ़ भी अवैध खनन की शिक़ायत की थी और इसी वजह से सोलंकी पर एक बार 40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा था. जेठवा सोलंकी के ख़िलाफ़ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे. कुछ समय पहले भी अमित जेठवा पर कातिलाना हमला हो चुका था. जेठवा के आरटीआई आवेदनों के कारण अवैध खनन से जुड़े कई मामले सामने आए थे. साथ ही एक सीमेंट कंपनी को भी जेठवा के आवेदनों से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था. जेठवा के पिता भीखू भाई अपने बेटे की हत्या की जांच सीबीआई से कराना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि चूंकि मामला भाजपा के सांसद से जुड़ा है, इसलिए राज्य की भाजपा सरकार और उसकी पुलिस निष्पक्ष होकर जांच नहीं कर पाएगी.

भीखू भाई की यह आशंका बहुत हद तक सही भी है. सवाल है कि जिस व्यवस्था के ख़िलाफ़ कोई नागरिक एक सूचना निकालता है और उसे सार्वजनिक करता है, वही व्यवस्था क्यों और कितनी सुरक्षा उस नागरिक को देना चाहेगी. निष्पक्ष जांच की बात तो बहुत दूर की है. यह सच्चाई कौन नहीं जानता कि किसी भी बड़े घोटाले में कौन–कौन से और किस तरह के लोग शामिल होते हैं. भारत में जितने भी बड़े घोटाले सामने आए हैं, उनमें किसी नेता या अफसर की संलिप्तता ज़रूर होती है. ऐसे में अगर कोई आम आदमी किसी घोटाले का पर्दाफाश करता है तो सोचिए क्या होगा. पुणे के सतीश शेट्टी के साथ क्या हुआ? भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सतीश शेट्टी की भी हत्या कर दी गई. सुबह–सुबह जब वह घर से बाहर निकले तो उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया. 38 वर्षीय सतीश पुणे से 40 किलोमीटर दूर तालेगांव में रहते थे. सूचना के अधिकार के तहत सतीश कई मामलों का पर्दाफाश कर चुके थे. सतीश पुणे की भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के संयोजक भी थे. आरटीआई का इस्तेमाल कर

शैलेष गांधी
केंद्रीय सूचना आयुक्त

कोई क़ानून इसका समाधान नहीं है

इस तरह की हिंसा का मुख्य कारण है अराजकता. जैसे ही कोई आदमी पावरफुल लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो ऐसी हिंसा होती है. आरटीआई अराजकता को दूर करने का एक साधन बन रहा है, इसलिए हिंसा हो रही है. हर नागरिक की सुरक्षा के लिए साधन हो तब तो कुछ होगा. लेकिन यह संभव नहीं है. ऐसी हिंसा के लिए एक पूर्ण समाधान की ज़रूरत है, लेकिन मुझे इसके लिए कोई जादुई चिराग नज़र नहीं आता. हां, जब कभी ऐसी हिंसा होती है तो चार आरटीआई कार्यकर्ताओं को चाहिए कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके मुद्दे को वो अपना ले. तब वो लोग कितनों की हत्या कर पाएंगे. लोकायुक्त या इस तरह की संस्था से क्या होगा? मुझे इससे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है. और इस तरह की संस्था बना कर हम क्यों और ख़र्च बढ़ाएं?

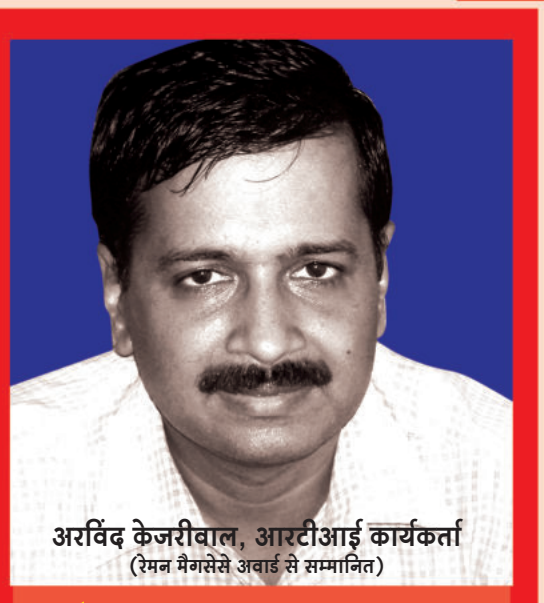

अरविंद केजरीवाल, आरटीआई कार्यकर्ता
(रेमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित)

इसका समाधान लोकपाल विधेयक है

सात महीने में आठ कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई. सारे भ्रष्ट लोग इकट्ठा हो गए हैं. नेता, नौकरशाह, पुलिस और माफिया सब इकट्ठे हैं. जो आवाज़ उठाएगा, उसे ये लोग छोड़ेंगे नहीं. जो भी सूचना निकलती है, वह एंटी करप्शन एजेंसी, पुलिस एवं नेताओं के ख़िलाफ़ ही होती है. ऐसे में हम किससे सुरक्षा मांगने जाएं. सबसे ज़रूरी है एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन, जो ऐसे मामलों की जांच कर सके, जैसे लोकपाल का पद. सरकार को जल्द से जल्द लोकपाल विधेयक लाना होगा. राज्यों में लोकायुक्त के पद को और प्रभावी बनाने की ज़रूरत है. लोकपाल और लोकायुक्त को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने होंगे, संसाधन देने होंगे, ताकि अगर कोई लोकपाल या लोकायुक्त के पास इस तरह की कोई शिक़ायत लेकर जाए तो वह उसकी निष्पक्ष जांच कर सके. जांच के लिए लोकपाल या लोकायुक्त को किसी भी एजेंसी से अनुमति लेने की ज़रूरत न पड़े.

हिंसा की उक्त सभी घटनाएं इसी साल की हैं, लेकिन दो साल पहले भी झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता ललित मेहता की हत्या इसीलिए हुई थी कि उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम का सोशल ऑडिट कराने का प्रयास किया था. वह इस योजना के तहत किए गए ख़र्च को आधिकारिक तौर और धरातल पर जांचना चाहते थे, लेकिन सोशल ऑडिट से एक दिन पहले ही उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता बने ललित मेहता की किसी से दुश्मनी नहीं थी. वह तो पलामू जिले में भोजन के अधिकार अभियान के प्रमुख सदस्य थे. पुलिस ने उनके शव का जल्दबाज़ी में पोस्टमार्टम कराया और घटनास्थल से 25 किलोमीटर दूर ले जाकर दफना दिया. ललित मेहता की हत्या के 12 दिनों बाद सोशल ऑडिट हुआ. ऑडिट से पता चला कि जिले में योजना के तहत खर्च किए गए 73 करोड़ रुपये का एक बड़ा हिस्सा ठेकेदारों, अधिकारियों और विकास माफ़ियाओं की जेब में चला गया.

इन सभी घटनाओं को देखने–सुनने के बाद सबसे अहम सवाल सूचना के ऐसे सिपाहियों की सुरक्षा को लेकर उठता है. जब वर्तमान व्यवस्था ऐसी हिंसा को रोक पाने में असफल हो रही हो, तो आख़िर क्या उपाय बचता है? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में बीती 26 जुलाई की शाम सैकड़ों आरटीआई कार्यकर्ता, पत्रकार एवं आम नागरिक एकत्र हुए. गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुलूस की शक्ल में सारे लोग समता स्थल पहुंचे. समता स्थल पर करीब घंटे भर चले विचार–विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकला कि सरकार को जल्द से जल्द लोकपाल विधेयक पारित करना चाहिए. लोकायुक्त को और अधिक शक्ति दी जानी चाहिए. इन संस्थाओं को इतना मज़बूत बनाया जाए, जिससे वे इस तरह के मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर सकें. इसके अलावा एक और अहम समाधान का ज़िक्र अरविंद केजरीवाल ने किया. यह समाधान था कि जब कभी किसी आरटीआई कार्यकर्ता को आवेदन देने के चलते धमकी मिले तो पचास–सौ लोग उसी मुद्दे पर अपने–अपने नाम से आवेदन डालें. ऐसे में धमकी देने वाला कितने लोगों को धमकी दे पाएगा. निश्चित तौर पर यह एक व्यवहारिक समाधान था, लेकिन यह तो नागरिक पहल की बात है. सरकार का इस मामले में ध्यान देना भी ज़रूरी है. यूपीए सरकार जिस सूचना क़ानून को अपनी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताती है, उसका क्या हश्र हो रहा है, इस पर भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह को ध्यान देना होगा.

shashishekhar@chauthiduniya.com

कश्मीर समस्या का एक संवैधानिक पहलू भी है. हमारे संविधान ने कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की है और इस संवैधानिक प्रावधान को नेहरू-अब्दुल्ला समझौते ने भी वैधता प्रदान की.

कश्मीर : कैसे रुके अंतहीन हिंसा का सिलसिला?

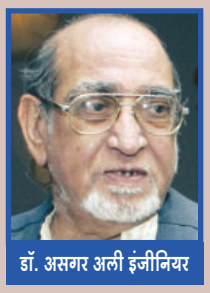

डॉ. असगर अली इंजीनियर

कश्मीर में जारी विवाद का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है. हमारे सशस्त्र बल, विशेषकर सीआरपीएफ समस्या को बढ़ा रहे हैं. दुर्भाग्यवश, कश्मीर समस्या को आज भी केवल क़ानून और व्यवस्था की समस्या माना जा रहा है. आम लोगों की महत्वाकांक्षाओं, उनके सपनों और उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. हमारे सशस्त्र बल लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं. उन्हें सिर्फ़ लोगों को मारना आता है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो समस्या को सुलझाना तो दूर, हम कश्मीर को एक विशाल कब्रिस्तान बना देंगे. वहां लगभग रोजाना नौजवान विरोध प्रदर्शनकारी मर रहे हैं, परंतु रोजाना उनका स्थान नए प्रदर्शनकारी ले रहे हैं. मौत का डर भी इन युवाओं को नहीं रोक पा रहा है. ऐसा नहीं है कि कश्मीर के लोग भारत विरोधी हैं या वे पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं. अभी हाल में ब्रिटेन के एक थिंक टैंक द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से यह नतीजा सामने आया है कि पाकिस्तानी बनने की इच्छा मात्र 4 प्रतिशत कश्मीरियों की है, परंतु उनकी समस्याएं एवं महत्वाकांक्षाएं हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए. इसकी जगह उन्हें गोलियां मिल रही हैं. अभी हाल में हुई सर्वदलीय बैठक में यह तय किया गया कि अब विरोध प्रदर्शनों पर जान लेने वाली गोलियों की बजाय पैपर गन इस्तेमाल की जाएगी. इन बंदूकों से निकलने वाली गोली जानलेवा नहीं होती, परंतु जिसे वह लगती है, उसे ऐसा भान होता है, मानो उस पर असली गोली चलाई गई हो.

क्या यह निर्णय लेने में देरी नहीं की गई? क्या कारण है कि यह निर्णय घाटी में 15 युवाओं की मौत और सरकार के विरुद्ध आक्रोश भड़कने के बाद लिया गया? कश्मीर में आक्रोश जनित हिंसा ने सीआरपीएफ को भी भारी नुक़सान पहुंचाया है. लगभग 270 जवान पिछले एक माह में ही घायल हुए हैं और पिछले एक वर्ष में घायल जवानों की संख्या 1900 से अधिक है. क्या यही निर्णय पहले नहीं लिया जा सकता था, ताकि युवाओं की जान न जाती और जवान सुरक्षित रहते? क्या पैपर गन का आविष्कार सर्वदलीय बैठक के ठीक पहले हुआ था? क्या हम उपयुक्त तकनीक का इस्तेमाल तभी करेंगे, जब हमारे कुछ नागरिक अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे? अगर यही निर्णय पहले ले लिया जाता तो न सिर्फ़ कई जानें बचतीं, बल्कि घाटी में संकट की स्थिति भी निर्मित नहीं होती. मैं जून, 2010 में शांति व विवादों के निपटारे विषय पर आयोजित कार्यशाला के सिलसिले में कश्मीर घाटी में था. वहां मैंने समाज के सभी वर्गों के सदस्यों से यह जानने की चेष्टा की कि वे कश्मीर समस्या के हल के बारे में क्या सोचते हैं. इन लोगों में बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता तो शामिल थे ही, बाज़ारों में ख़रीददारी करने निकले सामान्यजन भी शामिल थे. इन सभी के जवाबों में जो बात समान थी, वह यह थी कि उमर अब्दुल्ला एक असफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं. वहीं आमजन मुफ्ती मोहम्मद सईद के ज़बरदस्त प्रशंसक हैं.

मुफ्ती के बारे में यह माना जा रहा है कि वह एक परिपक्व नेता हैं, जो केंद्र सरकार से खुलकर संवाद कर सकते हैं और कश्मीर समस्या का संतोषप्रद हल निकाल सकते हैं. जनमत यह है कि उमर अब्दुल्ला राज्य की परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने में असफल सिद्ध हुए हैं और वह केंद्र सरकार से खुलकर संवाद करने में हिचकिचाते हैं. यह मान्यता उन सभी लोगों की थी, जिनसे मैंने चर्चा की. इस चर्चा से यह तथ्य भी उभर कर सामने आया कि अलगाववादी तत्व इतने शक्तिशाली नहीं हैं, जितना उन्हें माना या समझा जाता है. आमजन तो कश्मीर की बर्बादी से चिंतित और परेशान हैं. कश्मीर का युवा वर्ग रोज़गार एवं राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार चाहता है. जिन भी युवाओं से मैंने चर्चा की, वे सब घाटी में रोज़गार एवं आर्थिक प्रगति के अवसरों के अभाव से परेशान दिखे. उनका कहना था कि उच्च शिक्षित युवाओं को भी घाटी में काम नहीं मिलता. वे या तो बेरोज़गार रहते हैं या उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं मिलती. इससे उत्पन्न गुस्से और कुंठा का लाभ अलगाववादी उठाते हैं. दुर्भाग्यवश न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे रही है. दोनों सरकारें केवल अलगाववादियों पर दोषारोपण करती रहती हैं.

कश्मीर समस्या का एक संवैधानिक पहलू भी है. हमारे संविधान ने कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की है और इस संवैधानिक प्रावधान को नेहरू-अब्दुल्ला समझौते ने भी वैधता प्रदान की, परंतु दक्षिणपंथी राजनीतिक शक्तियों के दवाब के चलते कश्मीर को पूर्ण स्वायत्तता देने के वायदे को पूरा नहीं किया गया. कश्मीर में 1980 एवं 1990 के दशक में चले उग्रवादी आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने फारुक अब्दुल्ला को यह आश्वासन दिया था कि कश्मीर को स्वायत्तता दी जाएगी. फारुक अब्दुल्ला ने तब मुझे स्वयं बताया था कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री से जानना चाहा कि कश्मीर को कितनी स्वायत्तता प्रदान की जाएगी तो प्रधानमंत्री का जवाब था कि स्वायत्तता की कोई सीमा नहीं होगी. ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं. असल में जो हुआ, वह यह था कि नरसिम्हा राव के बाद भाजपा सत्ता में आ गई. कश्मीर को स्वायत्तता देना तो दूर की बात रही, भाजपा सरकार तो संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने पर आमादा थी. इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता के बाद कश्मीर में हुए किसी भी चुनाव की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता पर वहां की जनता को भरोसा नहीं हुआ. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर में उग्रवाद की शुरुआत 1988 के चुनावों के बाद हुई. इस चुनाव में भारी गड़बड़ियां हुईं और कश्मीर के एक स्कूल शिक्षक सलाहुद्दीन को पराजित घोषित किया गया, जबकि कश्मीर की आम जनता यह मानती थी कि वह विजयी हुए थे. सलाहुद्दीन अब पाक अधिकृत कश्मीर में रहता है और हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख है.

2004 में पहली बार कश्मीर में साफ-सुथरे चुनाव हुए. इस दौर में मेरी कश्मीर यात्रा के दौरान मुझसे कई लोगों ने कहा कि अगर आगे भी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव होते रहे तो यहां के हालात बदलेंगे और कश्मीर एक बार फिर भारत से भावनात्मक स्तर पर जुड़ जाएगा. इन चुनावों के बाद मैंने कश्मीरियों में एक नए आत्मविश्वास की झलक देखी. 2009 के चुनाव भी काफी हद तक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र थे, परंतु दुर्भाग्यवश उमर अब्दुल्ला हालात पर काबू पाने में नाकामयाब साबित हुए हैं. दशकों से चल रही हिंसा और अतिवादी आंदोलनों के बाद कश्मीर निवासी एक बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हिंसा से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, केवल शांतिपूर्ण रास्ते से ही कश्मीर समस्या सुलझ सकती है. मैं यह बात बड़ी संख्या में कश्मीरियों से अपनी बातचीत के आधार पर कह रहा हूं, परंतु वे ऐसा शांतिपूर्ण हल चाहते हैं, जिसमें उनका सम्मान एवं गरिमा सुरक्षित रहे और उनकी समस्याओं का हल निकले. वे कश्मीरियत की वापसी चाहते हैं, क्षेत्रीय स्वायत्तता चाहते हैं और अपनी विशिष्ट संस्कृति अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं. कश्मीर में पाकिस्तान हमारे लिए समस्याएं पैदा कर रहा है. हम कश्मीर समस्या के समाधान में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहते. हम कश्मीर में रायशुमारी नहीं चाहते. यह सब तो ठीक है, परंतु कश्मीरियों का दिल जीतने से हमें कौन रोक रहा है? हमारे सुरक्षाबल जिस तरह कश्मीर में फ़र्ज़ी मुठभेड़ें और मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं, उससे हम कश्मीरियों का दिल कभी नहीं जीत सकेंगे, बल्कि उनमें अलगाव का भाव ही पैदा करेंगे.

अगस्त, 2006 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह कश्मीरी नेताओं के साथ गोलमेज सम्मेलन के लिए श्रीनगर गए थे और वहां उन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि आगे से कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा. उन्होंने इस संबंध में जीरो टालरेंस शब्द का प्रयोग किया था, परंतु प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के बाद भी घाटी में फर्जी मुठभेड़ें जारी रहीं. प्रधानमंत्री की यात्रा के कुछ ही समय बाद मैंने घाटी में एक शांति कार्यशाला का संचालन किया था. कुछ प्रतिभागियों ने फ़र्ज़ी मुठभेड़ों की ओर इंगित करते हुए व्यंग्य से कहा, तो यह है सरकार का जीरो टालरेंस! यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि कश्मीर घाटी में हालात सुधरने की बजाय दिनोंदिन बिगड़ते जा रहे हैं. मानवाधिकारों के हनन की घटनाएं बढ़ रही हैं. अभी कुछ महीने पहले दो युवा महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उनकी लाशें पानी से निकाली गईं. इस मामले में आज तक किसी को पकड़ा नहीं जा सका है. सीबीआई ने मामले की ठीक से जांच नहीं की. ऐसा संदेह है कि इस घटना में पुलिस एवं सैन्य अधिकारी शामिल थे.

मैं कश्मीरियों के साथ अपनी बातचीत के आधार पर दावे से कह सकता हूं कि घाटी की आबादी के एक बहुत छोटे से हिस्से को छोड़कर कोई कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता. यही निष्कर्ष ब्रिटिश थिंक टैंक का भी है. कश्मीरी केवल शांति और इज़्ज़त से जीना चाहते हैं. केंद्र एवं राज्य सरकार को कश्मीरियों की यह इच्छा पूरी करने के लिए हरसंभव क़दम उठाने चाहिए. आमजनों की मान्यता है कि मुफ्ती केंद्र सरकार से कई लाभ लेने में सफल हो गए थे. उमर अब्दुल्ला या तो अपनी अनुभवहीनता के कारण या साहस की कमी के चलते केंद्र सरकार तक अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे हैं. कारण जो भी हो, परंतु यह तय है कि जनमत मुफ्ती के पक्ष में झुक रहा है. उमर अब्दुल्ला की तुलना में तो गुलाम नबी आज़ाद को भी बेहतर मुख्यमंत्री बताया जा रहा है. अगर घाटी में ख़ूनखराबा रोकना है तो केंद्र सरकार को राजनीतिक साहस प्रदर्शित करते हुए कड़े क़दम उठाने होंगे. सेना को अनुशासित रखना होगा और सेना का मनोबल न टूटे, इस डर से अनुशासनहीनता एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन सहन करना बंद करना होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे आतंकियों के ही हाथ मज़बूत होंगे और हालात और ख़राब होते जाएंगे.

प्रजातंत्र में फ़र्ज़ी मुठभेड़ों के लिए कोई स्थान नहीं है. सेना या पुलिस के हाथों निर्दोष नागरिकों का मारा जाना सरकार की बड़ी असफलता है. ऐसा करने वाले अधिकारियों को कड़ा दंड मिलना चाहिए. निर्दोष नागरिकों का ख़ून बहाने से तो ऐसे क्षेत्रों में भी भारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जहां अलगाववादी या आतंकवादी तत्व सक्रिय नहीं हैं. कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाक़ की तो बात ही दूसरी है, जहां क्षेत्रीय संस्कृति और पहचान से जुड़े मुद्दों के कारण हालात पहले से ही नाज़ुक हैं. क्षेत्रीय स्वायत्तता का मुद्दा कई देशों में गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा है, चाहे उसमें किसी अन्य देश की भूमिका हो या न हो. स्पेन में बास्क राष्ट्रीयता के मुद्दे ने वहां की सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रखी है. हाल में अपनी मांगों के समर्थन में 25 लाख बास्क राष्ट्रवादियों ने जंगी प्रदर्शन किया. बास्क राष्ट्रवादियों ने भी काफी लंबे समय तक हिंसा का सहारा लिया और कई बम विस्फोट किए, परंतु अंततः उन्हें यह एहसास हो गया कि हिंसा के रास्ते पर चलकर वे कहीं नहीं पहुंचेंगे. हमें कश्मीर समस्या को दो स्तरों पर सुलझाना है. पहला आंतरिक स्तर और दूसरा पाकिस्तान का स्तर. मैं पाकिस्तान के मसले पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, परंतु अपने स्तर पर हमें घाटी में शांति कायम करनी होगी. मेरी राय में कश्मीर के लोग कश्मीर समस्या के किसी भी अहिंसक एवं गरिमापूर्ण हल के लिए तैयार हैं. इस मामले में विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है. युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनका दिल जीतना होगा. फैजल शेख का मामला इस संदर्भ में एक अच्छा उदाहरण है. सभी कश्मीरियों को इस बात पर गर्व है कि उनमें से एक ने आईएएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया. पूरे भारत के मुसलमानों को भी फैजल शेख पर गर्व है और देश भर में उनके सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं. इस तरह कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए जरूरी है कि बातचीत के माध्यम से कश्मीर को कुछ स्वायत्तता दी जाए और कश्मीरी युवक-युवतियों को कश्मीर और उसके बाहर भी अधिक संख्या में सरकारी नौकरियों में भर्ती किया जाए. यदि भारत सरकार की सेवाओं में उन्हें अधिक स्थान मिलेगा तो इससे उनका भारत से जुड़ाव बढ़ेगा. कश्मीर में रेल सुविधा का विस्तार होना चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाना भी जरूरी है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले कम से कम हों और सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर घाटी में अन्य स्थानों पर सुरक्षाबलों की संख्या में कमी की जाए. इन कदमों से घाटी में आंतरिक शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी.

(लेखक जाने-माने इस्लामिक विद्वान हैं)

feedback@chauthiduniya.com

प्रशासन ने भी कमर कस ली. शिलान्यास से पहले धारा 144 लागू कर दी गई और चेतावनी दे दी गई कि क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विरोध के किसी भी कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी गई है.

कंपनी हारी जनता जीती

आदियोग

विकास के नाम पर सरकारों की आंख मूंद कंपनीपरस्ती के इस दौर में अधिसंख्य आबादी के सामने ज़िंदा रहने का संकट सुरसा के मुंह की तरह फैलता जा रहा है. चंद कंपनियों के भले के लिए पहले से ग़रीब–वंचित जनता को और अधिक ग़रीबी और वंचना में डुबो देने की दु:खभरी कहानियां बढ़ती जा रही हैं. इसे रोकने के लिए पूरे देश में जनता जूझ रही है. जुलाई का महीना ज़रूर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जीत की अच्छी ख़बर देकर गुज़रा और इसने नाउम्मीदी के घने होते कुहासे के बीच तमाम जन आंदोलनों को हिम्मत और ताक़त देने का बड़ा काम किया. झूठ, दबाव, धमकियों और तिकड़मों का जाल था. फ़ौजफाटे के साथ तैनात सरकारी अमला कंपनी का मैनेजर कम बॉडीगार्ड जैसा और स्थानीय मीडिया कंपनी का पीआरओ ज़्यादा दिखता था. हालात आपातकाल जैसे थे, गोया किसी दुश्मन के हमले का अंदेशा हो. कंपनी की राह में रोड़ा बने लोगों पर लाठियां भांजी गईं, पुलिस फायरिंग हुई. ख़ून बहा, हाथ–पैर टूटे और फ़र्ज़ी मामले दर्ज़ हुए, लेकिन दुखियारी जनता पीछे नहीं लौटी. मीर साहब के हवाले से कहें तो उल्टी हो गईं सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया. हालात इतने बिगड़े कि मंदिर वहीं बनाएंगे की ज़िद छोड़ने और कंपनी को आगे का रास्ता दिखाने की मजबूरी पैदा हो गई. सच और इंसाफ़ का पलड़ा भारी पड़ा. आख़िरकार मसले की जड़ यानी कंपनी को दी गई हरी झंडी गुजरी 15 जुलाई को ख़ारिज कर दी गई और इस तरह लगभग छह माह लंबे आंदोलन की जीत हुई.

यह क़िस्सा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले में उड़ीसा से सटे सोनपट्टी मंड का है. नागार्जुन कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड नामक कंपनी यहां पावर प्लांट लगाना चाहती थी. स्थानीय वाशिंदों को इस पर आपत्ति थी, इसलिए कि पावर प्लांट से उन्हें इलाक़े के पारिस्थितिकी संतुलन के बिगड़ जाने और अपनी आजीविका छिन जाने का ख़तरा था. कंपनी के ख़िलाफ़ पूरा इलाक़ा एकजुट था. बावजूद इसके पिछले साल अगस्त में पावर प्लांट को लेकर जन सुनवाई का आयोजन कर दिया गया था. इसमें भी कंपनी की परियोजना का मुखर विरोध हुआ, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रभावित होने जा रहे लोगों की आवाज़ को अनसुना करते हुए कंपनी को क्लियरेंस थमा दिया. पावर प्लांट से 30 गांवों के मछुआरों और किसानों की आजीविका पर गाज गिरने जा रही थी और जिसके असर से सोनपेटा टाउन के लोग भी अछूते नहीं रहते. भविष्य का सवाल सबको मथने और चौतरफ़ा जलने लगा. मछुआरों के मंच मत्स्यकारा एक्य वेदिका और पर्यावरण परिरक्षण समिति के साझा बैनर के नीचे विशाल जनसमूह एकजुट हो गया. रैली–प्रदर्शनों और बैठकों का तांता लग गया. पावर प्लांट के ख़िलाफ़ क्रमिक उपवास शुरू हो गया. इस बीच पुलिस–प्रशासन का उन्हें डराने–धमकाने और फ़र्ज़ी मामलों में फंसाने का सिलसिला लगातार तेज़ होता गया. इसमें कंपनी के गुंडे भी हाथ बंटा रहे थे. तनाव बढ़ता गया और इसी बीच कंपनी ने पावर प्लांट संबंधी निर्माण का शिलान्यास किए जाने की तारीख़ भी तय कर दी–बीती 14 जुलाई. यह लोगों के लिए फ़ैसले की घड़ी थी. शिलान्यास की ख़बर ने आग में घी डालने का काम किया. आंदोलनकारियों ने अपने कड़े तेवरों से जता दिया कि वे किसी भी क़ीमत पर अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे और कंपनी को शिलान्यास का पत्थर नहीं रखने देंगे. ख़ास बात यह कि पूरे आंदोलन में महिलाएं सबसे आगे थीं और उसे हर तबके और पेशों से जुड़े लोगों का समर्थन हासिल था.

प्रशासन ने भी कमर कस ली. शिलान्यास से पहले धारा 144 लागू कर दी गई और चेतावनी दे दी गई कि क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विरोध के किसी भी कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी गई है. अपनी ही ज़मीन से लोगों को उजाड़ देने के लिए दहशत के साज़ोसामान के साथ दो हज़ार से अधिक वर्दीधारी तैनात कर दिए गए. आमने–सामने की जंग का मैदान सज गया. आख़िरकार शिलान्यास के दिन जो होना था, वही हुआ. लोगों को अपनी ज़मीनों से खदेड़ा जाने लगा और लोगों द्वारा हमलावरों को. वर्दीधारी हमलावरों की मदद के लिए कंपनी द्वारा भाड़े पर लाए गए एक हज़ार से ज़्यादा गुंडे भी साथ थे. आख़िरकार पुलिस फायरिंग हुई और तीन लोग मारे गए. कोई डेढ़ सौ लोग घायल हुए, जिनमें पुलिसवालों समेत मीडियाकर्मी भी थे. लाठीचार्ज और फायरिंग से लोगों का गुस्सा घायलों के अस्पताल पहुंचने पर भी फूट पड़ा. पुलिस–प्रशासन और कंपनी के ख़िलाफ़ नारे लगे और कुछ लोग नज़दीक बने कंपनी के दफ्तर पर टूट पड़े. उन्हें रोकने के लिए एक बार फ़िर फ़ायरिंग का दौर चला, लेकिन शुक्र कि इस बार केवल हवा में. उग्र होते कंपनी विरोध के बावजूद प्रशासन नहीं चेता. अमन क़ायम करने यानी जन असंतोष को दबाने के लिए डेढ़ हज़ार और पुलिसकर्मियों को तैनात किए जाने का फ़ैसला हो गया.

इस पूरे मामले को लेकर आंध्र प्रदेश विधानसभा में ख़ूब हंगामा मचा. माइक उखाड़े गए और मार्शल के ज़रिए टीडीपी के विधायकों को सदन से बाहर निकालना पड़ा. विपक्ष ने सोनपेटा का विधायक होने के नाते राजस्व मंत्री के इस्तीफ़े की मांग भी उठाई. राज्य सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई. मुख्यमंत्री रोसैया को यहां तक कहना पड़ा कि सोनपेटा में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती अचरज की बात थी. तो क्या मुख्यमंत्री को सचमुच इसका पता नहीं था? अगर हां, तो वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों हैं? 14 जुलाई को एक तरफ़ पुलिस जनता को आवाज़ उठाने का मज़ा चखा रही थी और दूसरी तरफ़ उसी दिन कंपनी को क्लियरेंस दिए जाने के मुद्दे पर नेशनल इंवायरमेंट एपेलेट अथॉरिटी (एनईएए) में मामले की सुनवाई चल रही थी. एनईएए पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर किसी उद्योग को दिए गए क्लियरेंस के ख़िलाफ़ अपील करने का निर्णायक निकाय है. फ़ोरम फॉर बेटर विशाखा समेत कई सामाजिक संगठनों की अपील पर हुई इस सुनवाई में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कंपनी को थमाए गए क्लियरेंस के पीछे के गड़बड़ घोटाले की पोलपट्टी खुल गई. अगले दिन एनईएए ने कंपनी को मिले क्लियरेंस को तीखे लफ्ज़ों में ग़लत फ़ैसला करार दिया और उसे रद्द कर दिया. कंपनी के लिए अधिग्रहीत की गई ज़मीन को बंजर और फ़ालतू दिखाया गया था, जबकि यह बेहद उपजाऊ है, दो फ़सली है और सैकड़ों परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है. सोनपेटा को दूसरा गोवा भी कहा जाता है. यह इलाक़ा पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में शामिल है और इससे न जाने कितने स्थानीय लोगों की रोजी–रोटी चलती है. यहां समंदर का ख़ूबसूरत किनारा है और प्रवासी पक्षियों का आश्रयस्थल भी. कंपनी का पावर प्लांट इसके नज़दीक ही बनाया जाना था. पावर प्लांट लगता तो पानी में ज़हर घोलता, सिंचाई के संसाधनों को निगल जाता, पर्यटन का सिर कुचलता, प्रवासी पक्षियों का बसेरा छीनता, लगभग डेढ़ लाख लोगों की आजीविका पर डंक मारता और सोनपेटा को दूसरा गोवा नहीं रहने देता.

लेकिन देश के दूसरे तमाम हिस्से इतने ख़ुशक़िस्मत नहीं हैं, जहां लोगों और क़ुदरत को विकास और औद्योगीकरण की बड़ी क़ीमत चुकाने पर मजबूर किया जा रहा है. क्या उलटबांसी है कि एक तरफ़ भोजन के अधिकार का क़ानून लाने की तैयारी है और दूसरी तरफ़ लोगों की खेती लायक़ ज़मीनें छीनकर उन्हें कंपनियों के हवाले या सेज़ के नाम कर देने का उतावलापन है. ग़ौर कीजिए कि भले ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच रस्साकशी हो, लेकिन इस मामले में अनूठा तालमेल है. राज्य सरकारों को कंपनियों के साथ करारनामों पर दस्तख़त करने में और केंद्र सरकार को उसे ओके कराने में देर नहीं लगती. क़ायदे से होना तो यह चाहिए कि जिसे ज़मीन चाहिए, वह सीधे उसके मालिक से बात करे और यह मालिक की मर्ज़ी कि वह अपनी ज़मीन बेचे या अपने पास रखे और बेचे तो किन शर्तों पर. यह मालिक कोई परिवार हो सकता है, कोई ग्राम पंचायत या कोई समुदाय. लेकिन लगता है कि करारनामा कंपनियों को किसी भी तरह उनकी मनपसंद ज़मीन दिलाने की सरकार को मिली सुपारी हो. अब लोकतांत्रिक और कल्याणकारी सरकार दाऊद इब्राहिम तो हो नहीं सकती. इसलिए जन सुनवाई का नाटक है. परियोजना स्थल से दूर और तगड़ी सुरक्षा के बीच उसका मंचन है, जिसमें सरकार और कंपनी के अधिकारी हैं और जुटाई गई भरोसेमंद जनता है, जिसका काम हाथ उठाकर परियोजना पर केवल अपनी रज़ामंदी देना है. इस तरह जन सुनवाई का कामयाब होना पहले से तय है, भले ही प्रभावित जनता बाहर शोर मचाए और ज़्यादा बवाल मचाए तो लाठी–गोली खाए, जेल जाए. छत्तीसगढ़ सरकार जन सुनवाई के इस खेल में सबसे आगे है और कंपनीपरस्ती की मिसाल क़ायम करने में जुटी है.

रायगढ़ के दर्रामुंडा के लोग नहीं चाहते थे कि कोई कंपनी उनके इलाक़े में डेरा डाले और उन्हें कहीं का न छोड़े, लेकिन सरकार तो यही चाहती थी. इसलिए बीती 17 मई को एस के एस स्टील एंड पावर लिमिटेड की परियोजना के लिए जन सुनवाई का आयोजन तय कर दिया गया. सरकारी बंदोबस्त चाक–दुरुस्त था, लेकिन जनता के तेवरों को देखते हुए कंपनी को जन सुनवाई की कामयाबी पर शक था. कंपनियां जानती हैं कि सरकार, प्रशासन और मीडिया को रिश्वत की डंडी से किस तरह हांका जा सकता है कि अदालतों में भी बिकाऊ ओहदेदार मिल जाते हैं. इसका अंदाज़ा ज़रूर नहीं था कि ग़रीब–वंचित जनता को रिश्वत के झुनझुने से बहलाया–फुसलाया नहीं जा सकता और कंपनी यहीं मात खा गई. घूस बांटने आए उसके अधिकारियों को लोगों ने धर दबोचा, उनका मुंह काला किया, कान पकड़ कर उनसे उठा–बैठक कराई और जूतों की माला पहना कर उनका जुलूस निकाला. उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस छोड़नी पड़ी. कोई पांच साल पहले झारखंड के पोटका प्रखंड के एक गांव में भूषण स्टील कंपनी के प्रतिनिधियों का भी स्वागत इसी अंदाज़ में किया गया था. वहां तीखे जन विरोध ने पहले जिंदल को भगाया और फ़िर भूषण को.

रायगढ़ के तमनार ब्लॉक में पांच कोयला खदानें हैं. इनमें तीन जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के नाम हैं. आठ मई को उसकी एक और कोयला खदान के लिए जन सुनवाई का आयोजन हुआ था, जिसमें गांववालों ने एक आवाज़ में उसका भारी विरोध किया था. जन सुनवाई खटाई में पड़ गई और उसका समापन लाठीचार्ज से हुआ, जिसमें सौ से ज़्यादा लोग घायल हुए. पहली जन सुनवाई भी इसी तरह फिस्स हो गई थी. रायगढ़ के रमेश अग्रवाल जनचेतना नामक सामाजिक संगठन के प्रमुख हैं. वह सरकार की ज़मीन हड़पो मुहिम, कंपनियों के कारण होने वाले विस्थापन और प्रदूषण के ख़िलाफ़ बरसों से लोगों को संगठित और उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम करते रहे हैं. तमाम फ़र्ज़ी जन सुनवाइयों के गवाह रहे हैं और उनकी कामयाबी के कपड़े उतारते रहे हैं. राजेश त्रिपाठी एवं हरिहर पटेल जैसे जुझारू नाम इस मुहिम में उनके हमक़दम रहे हैं. इसी का नतीज़ा था कि रायगढ़ में पावर प्लांट लगाने की जिंदल की परियोजना के पैर उखड़ गए. जिंदल की दबंगई का आलम यह था कि अभी क्लियरेंस हासिल करने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी कि दूसरी जगह पर पावर प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया. इसकी शिकायत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की जा चुकी थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल जांच पर जांच हुई और ख़तो–क़िताबत. आख़िरकार, रमेश अग्रवाल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश से गुहार लगाई. आरोप सही निकले और जो कि क्लियरेंस हासिल करने के लिए तय हुई शर्तों का खुला उल्लंघन थे. इस आधार पर उन शर्तों को ही रद्द कर दिया गया. आंदोलनकारियों के लिए यह जितनी बड़ी जीत थी, जिंदल के लिए उतना ही बड़ा झटका. इसके तुरंत बाद 23 जून को जिंदल ने रमेश अग्रवाल पर मुक़दमा ठोंक दिया कि उन्होंने आठ मई की जन सुनवाई में हंगामा न खड़ा करने के एवज में पांच करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को देर तक नहीं डांट सका. बढ़ते जन दबाव ने मौसम ऐसा बदला कि बीती सात जुलाई को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जिंदल के ख़िलाफ़ ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से परियोजना शुरू करने का मुक़दमा दायर करना पड़ा.

जिंदल उन कंपनियों में है, जो रायगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में लोगों और क़ुदरत की सेहत बिगाड़ने के लिए ज़िम्मेदार है. क्या विरोधाभास है कि रायगढ़ की उसकी एक परियोजना के लिए उसे पर्यावरण प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय सम्मान से नवाज़े जाने का फ़ैसला हो गया और वह भी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के सदस्य पी एन भगवती की अध्यक्षता में हुई बैठक में. मालूम हो कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के मालिक नवीन जिंदल राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद भी हैं. समझा जा सकता है कि उनकी कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने में इतनी देर क्यों हुई?

रमेश अग्रवाल

नागार्जुन कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड नामक कंपनी यहां पावर प्लांट लगाना चाहती थी. स्थानीय वाशिंदों को इस पर आपत्ति थी, इसलिए कि पावर प्लांट से उन्हें इलाक़े के पारिस्थितिकी संतुलन के बिगड़ जाने और अपनी आजीविका छिन जाने का ख़तरा था. कंपनी के ख़िलाफ़ पूरा इलाक़ा एकजुट था.

feedback@chauthiduniya.com

लालगढ़ में संयुक्त बलों को अपने अभियान में जो सफलता मिली है, उसमें स्थानीय लोगों का काफी योगदान रहा.

माओवादियों के ख़िलाफ़ लालगढ़ की महिलाएं

एक समय था, जब लालगढ़ के आदिवासी सिर्फ़ चार बातों से डरते थे–पुलिस, हाथी, माओवादी और माकपा की हर्मादवाहिनी. अब इनका पुलिस पर विश्वास थोड़ा बहाल हुआ है या यूं कहिए कि पुलिस अब भी दो नंबर की दुश्मन है, क्योंकि लोग माओवादियों की तलाशी के दौरान हुए जुल्मों को अभी भी नहीं भूल सके हैं. हाथी भला क्या हमला करेंगे, गोलियों की गूंज से वे ख़ुद सहमे हुए हैं. खेत भी खाली पड़े हैं, ऐसे में हाथी कुचलेंगे क्या? सुरक्षाबलों की कामयाबी से माओवादियों के पांव उखड़ रहे हैं और माकपा की हर्मादवाहिनी तृणमूल की सेना से जूझने में लगी है.

बिमल राय

जीत के लिए चल रही एक लंबी ख़ूनी लड़ाई से जूझ रहे लालगढ़ का एक नया चेहरा सामने आ रहा है. महीनों से चल रहे संयुक्त बलों के अभियान ने माओवादियों की कमर तो तोड़ ही दी है, अब आम जनता के सड़क पर उतरने से सुरक्षाबलों का हौसला और बुलंद हो गया है. एक साल से अधिक समय तक हिंसा, बंद एवं पथावरोध जैसे आंदोलनों से जूझने के बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि माओवादी उन्हें किन अंधी गलियों में जाने पर मजबूर कर रहे थे. माओवादियों ने छत्रधर महतो की अगुवाई में बने पुलिस अत्याचार के ख़िलाफ़ जनसाधारण कमेटी (पीसीपीए) को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, पर छत्रधर की गिरफ़्तारी, दूसरे दर्जे के नेतृत्व के न उभर पाने और सुरक्षाबलों के दबाव से पीसीपीए की ज़मीन दरक गई है. अर्थव्यवस्था चौपट है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और सबसे बड़ी बात कि दैनिक मजदूरी एवं छोटे-मोटे व्यवसाय करके अपना गुजारा करने वाले आदिवासियों को दो जून की रोटी के भी लाले पड़ने लगे हैं.

एक समय था, जब आदिवासियों पर अत्याचार रोकने की बात कहकर माओवादियों ने लालगढ़ और आसपास के इलाक़ों में पुलिस और प्रशासन को लाचार बना दिया था, पर पिछली 13 जुलाई को नज़दीक के राधानगर की महिलाओं की अगुवाई में लोगों ने एक संदेश दिया कि अब बहुत हो चुका. हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. लाठी, बल्लम व अन्य हथियार लेकर क़रीब आठ हज़ार महिलाएं एवं पुरुष सड़कों पर उतर आए और माओवादियों के साथ-साथ पीसीपीए के गुर्गों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करने लगे. अब वे पुलिस-प्रशासन की मदद मांग रहे थे. इन महिलाओं ने ग्राम बचाओ कमेटी भी बना ली है. इनकी मांग है कि जगह-जगह रास्तों को काटना, पेड़ गिराकर रास्ता बंद करना और बंद बुलाने जैसी गतिविधियां रोककर जनजीवन सामान्य किया जाए. महिलाओं ने आरोप लगाया कि जनसाधारण कमेटी के लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं. वे जबरन लोगों को संयुक्त अभियान के विरोध में आयोजित जुलूस में शामिल होने के लिए कहते हैं.

पिछले दो साल के भीतर माओवादी विरोधी आंदोलन में लोगों का इस तरह सड़कों पर आना नहीं देखा गया था. लोगों ने बताया कि माओवादी संयुक्त बलों की पोशाक पहन कर आते हैं और महिलाओं पर जुल्म करते हैं. यहां तक कि लूटपाट भी करते हैं. बीती 19 जुलाई से जनसाधारण कमेटी के कॉडरों ने झाड़ग्राम में बेमियादी बंद का ऐलान कर रखा है और वे लोगों को उसमें जबरन शामिल करना चाहते हैं. महिलाओं ने आरोप लगाया कि सैनिकों के वेश में माओवादी काडर कथित तौर पर तलाशी के बहाने महिलाओं से बलात्कार भी कर रहे हैं. जुलूस में नारी इज़्ज़त बचाओ कमेटी और छात्र समाज के बैनर भी देखे गए. उक्त संगठन हाल ही में बने हैं. मामले ने तब तूल पकड़ा, जब जनसाधारण कमेटी के कुछ लोग राधानगर में आकर लोगों से अपनी रैली में शिरकत करने के लिए कहने लगे. इंकार करने पर वे मारपीट पर उतर आए. एक गर्भवती महिला की पिटाई होते देख लोग ख़ुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने अपने पारंपरिक हथियारों के बूते उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया. जनता के आक्रोश के आगे उनकी एक न चली. लोगों में इस तरह का साहस पैदा होने के पीछे कई कारण हैं. राधानगर की घटना के एक दिन बाद ही 24 जुलाई को पश्चिम मिदनापुर के निछानिदा गांव में लोगों ने जुलूस में जबरन हिस्सा लेने के लिए धमका रहे पीसीपीए के एक कॉडर सुशील महतो को रात भर बंधक बनाकर रखा. उसके 14 साथी लोगों की नाराज़गी देखकर भाग खड़े हुए. सुबह जब पुलिस आई तो लोगों ने बंधकों को सौंपने की एवज में गांव में एक पुलिस शिविर लगाने की मांग की. पुलिस ने जब पक्का आश्वासन नहीं दिया तो लोगों ने बंधकों को आज़ाद कर दिया. मतलब यह कि अभी भी लोगों में माओवादियों का ख़ौफ़ बरक़रार है और उनका आक्रोश संक्रांति के दौर से गुजर रहा है.

पीसीपीए और माओवादी लोगों के इस बदले रुख़ से चिंतित हैं. बताया जाता है कि लोधासौली और झाड़ग्राम के बाहरी इलाक़ों में माओवादियों की दो बैठकों में लोगों के इस बदले रुख़ के कारणों पर चर्चा हुई. झाड़ग्राम के पास विध्वंसक कार्रवाई में 150 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने के बाद माओवादियों के ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है. लोगों ने यह भी देखा कि झाड़ग्राम के इंद्रबनी प्राथमिक विद्यालय में बीती 16 जुलाई को प्रधान शिक्षक रवींद्र नाथ महतो की माओवादियों ने किस तरह स्कूल के बच्चों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी. इसके अलावा धरमपुर के गौहमीभांगा स्कूल के 11 छात्रों को इसलिए पीटा गया कि वे पीसीपीए के जुलूस में शामिल नहीं हुए. इसके पहले भी पिछले साल 11 सितंबर को लालगढ़ प्रखंड के बड़जामदा प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के सामने ही माओवादियों ने कार्तिक महतो नामक एक शिक्षक की हत्या कर दी थी. उनका अपराध यही था कि वे माकपा के सदस्य थे. इसके पहले 2002 में सालबनी इलाक़े के एक स्कूल में जनयुद्ध गोष्ठी के कॉडरों ने (तब पीसीपीए का गठन नहीं हुआ था) अनिल महतो नामक एक शिक्षक की गोली मारकर जान ले ली थी. ज़ाहिर है, ऐसे माहौल में विकास के काम ठप्प होंगे ही. लालगढ़ के एक छोटे व्यवसायी गौतम मनीष ने बताया कि उनकी खाद की एक छोटी सी दुकान है, पर कोई ख़रीददार नहीं है. लोग भागे-भागे फिर रहे हैं तो खेत कौन जोते-बोए? सारे खेत परती पड़े हैं. मालूम हो कि बंगाल के नक्सल प्रभावित इलाक़ों में साल में एक फ़सल ही होती है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा नहीं है. उन्हें फ़िक्र है मानसून के सहारे घर में दिखने वाले अनाज के दाने की, साल भर तड़पाने वाली भूख की. जितमन घराई एवं उनकी पत्नी कल्पना बेमोन झाड़ू बनाकर अपना गुजारा करते हैं, पर परिवार नहीं चल पा रहा. कोई और भी काम करने की ज़रूरत है, पर इलाक़े में काम है कहां? गांव में बिजली नहीं है, बाज़ार में किरोसिन नहीं मिलता. जन वितरण प्रणाली अस्त-व्यस्त पड़ी है. आज तक इन्हें बीपीएल कार्ड नहीं मिला है. हिराकुली निवासी लक्ष्मी माल ने तो बीपीएल कार्ड के बारे में सुना तक नहीं. जंगलों में गोलीबारी के कारण तेंदू पत्ते का कारोबार भी ठप्प पड़ा है.

लालगढ़ में संयुक्त बलों को अपने अभियान में जो सफलता मिली है, उसमें स्थानीय लोगों का काफी योगदान रहा. कुछ माओवादियों के मारे जाने और कुछ के गिरफ़्तार होने से लोगों में थोड़ा साहस पैदा हुआ है, पुलिस का ख़ुफ़िया तंत्र भी मज़बूत हुआ है. हाल में ही सालबनी के जंगल में झारखंड के सांसद सुनील महतो की हत्या में शामिल अभियुक्त एवं माओवादी नेता किशन जी के क़रीबी राजेश मुंडा पकड़े गए. बीते 16 जून को सालबनी के पास जंगल में सुरक्षाबलों ने माओवादियों के शिविर पर धावा बोलकर चार को मौत के घाट उतार दिया. अभया और मधुपुर में भी चार माओवादी मारे गए, जो किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे. पता चला है कि अभी भी प्रभावित इलाक़ों में माओवादियों के चार दस्ते सक्रिय हैं. शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है. लालगढ़ के स्कूलों से सुरक्षाबलों को बाहर निकालने के लिए

पश्चिम मिदनापुर के चार प्रखंडों के स्कूल प्रबंधकों को कोलकाता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी. 24 नवंबर को हाईकोर्ट का फ़ैसला आया कि सुरक्षाबल 30 दिसंबर तक स्कूल खाली कर दें. अदालत के आदेश के बाद कुछ स्कूल खाली कराए गए, पर अभी भी कुछ स्कूल सुरक्षाबलों के शिविरों के रूप में काम कर रहे हैं. जो स्कूल खुले हैं, उनमें बच्चों की संख्या मामूली है. सुरक्षाबलों की भी मजबूरी है, क्योंकि बरसात के मौसम में अस्थायी शिविरों से काम नहीं चलने वाला और असुरक्षित स्थानों पर शिविर लगाना ख़तरे से खाली नहीं है. सिलदा शिविर पर हुए हमले को कैसे भुलाया जा सकता है? लालगढ़ में 40 से भी ज़्यादा कंपनियां ऑपरेशन में लगी हैं.

एक तरफ़ सुरक्षाबलों की कामयाबी से माओवादियों के पांव उखड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ़ माकपा की हर्मादवाहिनी तृणमूल की सेना से जूझ रही है. उन्हें थोड़ा डर है तो ममता दीदी से, जो माओवादियों के ख़िलाफ़ जारी संयुक्त कार्रवाई को हर हाल में रुकवाने में लगी हुई हैं और अपना संदेश लालगढ़ आकर भी देने वाली हैं. ख़ैर, आशंकाओं और राजनीतिक खेल के इस दौर में जनता के जज़्बे को सलाम कहना होगा!

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... सी.बी.आई. और नरेंद्र मोदी! ...धीर

अंडमान में क़रीब आठ महीने तक बरसात होती है. ऐसे में मौसम के मिजाज़ में उथल-पुथल मची रहती है.

अंडमान में खाद्य प्रसंस्करण की पहल

आईलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आत्मनिर्भरता का पर्याय बन सकता है. विडंबना है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद अंडमान में खाद्य प्रसंस्करण के विशेषज्ञों का अभाव है. यहां मंत्रालय का विभागीय कार्यालय भी नहीं है. इन्हीं विपरीत परिस्थितियों के बीच कुछ महिला स्वयं सहायता समूहों ने उम्मीद की एक किरण जगाई है.

उमाशंकर मिश्र

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में पर्यावरणीय संतुलन क़ायम रखने के लिए कुछ समय पूर्व न्यायालय ने वनों की कटाई पर रोक लगा दी थी. लंबे समय तक काष्ठ उत्पादों के निर्माण से जुड़े लोगों के सामने ऐसे में रोजी-रोटी का संकट आ खड़ा हुआ. इस स्थिति से उबरने के लिए स्व-रोज़गार ही लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता था, लेकिन अब तक के अनुभवों को देखा जाए तो अंडमान में इस तरह की उद्यमीय संस्कृति बहुत ही कम देखने को मिलती है. अंडमान-निकोबार में खाद्य प्रसंस्करण की अकूत संभावनाएं मौजूद हैं. आईलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आत्मनिर्भरता का पर्याय बन सकता है. कुछ समय पूर्व अंडमान के उत्तरी छोर पर स्थित दिगलीपुर में एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई भी स्थापित की गई थी, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के चलते और फूड टेक्नोलॉजिस्ट न होने से यह इकाई ठप्प हो गई. दूसरी ओर मुख्य भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान में ग़ैर सरकारी संगठनों की गतिविधियां भी बहुत अधिक नहीं थीं, जो खाद्य प्रसंस्करण के काम में गुणवत्ता एवं कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर स्थानीय लोगों को इस काम के लिए तैयार कर सकें. अंडमान-निकोबार में 1912 किलोमीटर लंबी तटरेखा होने के कारण मत्स्य उद्योग के फलने-फूलने की भरपूर क्षमता मौजूद है. अंडमान के सागर में 1100 से अधिक प्रजातियों की मछलियों की पहचान की गई है, जिनमें से 30 प्रजातियों का व्यवसायिक उपयोग किया जाता है. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 2.44 टन मत्स्य उत्पादन की क्षमता होने के बावजूद अभी पूरी तरह से इसका दोहन नहीं हो सका है. अभी तक अंडमान में मत्स्य उद्योग, प्रसंस्करण और इससे जुड़ी गतिविधियां बहुत सीमित मात्रा में रही हैं. इसी तरह नारियल एवं कटहल का उत्पादन भी अंडमान में ज़रूरत से ज़्यादा है और अदरक के उत्पादन एवं उसके प्रसंस्करण की भी पर्याप्त पर्यावरणीय परिस्थितियां यहां मौजूद हैं. कुल मिलाकर देखा जाए तो इन तमाम उत्पादों के प्रसंस्करण कार्य से अंडमान में आर्थिक आत्मनिर्भरता का सूत्रपात किया जा सकता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा.

प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सी मोहम्मद ग़ैर सरकारी संस्था उन्नति के संस्थापक हैं. अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान उन्होंने अंडमान में खाद्य प्रसंस्करण के बूते आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात काफी पहले महसूस कर ली थी, लेकिन पर्याप्त संसाधन न होने से उन्हें इस काम में काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ा. कई बार प्रशासन से मदद की गुहार लगाने के बाद जब सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी फाउंडेशन से संपर्क साधा और बताया कि अंडमान में मछली एवं नारियल उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा है. बड़ी मात्रा में मछलियों का उत्पादन होने के बावजूद यहां न तो उसके निर्यात की पर्याप्त व्यवस्था है और न ही मछलियों के प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्माण की कोई सुविधा अब तक उपलब्ध हो सकी है. अंडमान में धान के अलावा बहुत अधिक खेती नहीं होती. हॉर्टीकल्चर का यहां प्रचलन अधिक है. हॉर्टीकल्चर में मुख्य तौर पर नारियल, केले और सुपारी का उत्पादन होता है. इन कुछेक संसाधनों के अलावा अंडमानवासियों को अधिकतर वस्तुओं के लिए चेन्नई या फिर कोलकाता पर निर्भर रहना पड़ता है. उन्नति ने इस बात को समझ कर अंडमान की महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षित करने का मन बनाया तो इस काम में राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी उसे आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया. आर्थिक समस्या का समाधान हो जाने से सी मोहम्मद और उनकी संस्था को इस काम में आगे बढ़ने के लिए हौसला मिल गया. सिलसिला चल पड़ा और अब तक अंडमान के विभिन्न टापुओं पर बसे गांवों, कस्बों और यहां तक कि पोर्ट ब्लेयर की कुछ कामकाजी महिलाओं समेत 350 से अधिक लोगों को मछली एवं नारियल आधारित प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. शुरुआती दिनों में इस काम के लिए अंडमान में कुशल प्रशिक्षकों का मिलना लगभग नामुमकिन था. यहां तक कि विभागीय स्तर पर भी ऐसे लोगों की खासी कमी थी. केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद यहां खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की यूनिट नहीं है और उसके स्थान पर कृषि विभाग ही नोडल एजेंसी के तौर पर कार्यरत है. उन्नति को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए अंबाला से फूड टेक्नोलॉजिस्ट बुलाना पड़ा. मुख्य भूमि से भेजे गए प्रशिक्षकों ने केवल बेरोज़गार युवकों एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ही नहीं, बल्कि विभागीय अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया. सी मोहम्मद कहते हैं कि बाज़ार की मौजूदा प्रतिस्पर्धा में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए अच्छा प्रशिक्षण बेहद अहम होता है, लेकिन विडंबना यह है कि अंडमान में अब तक इस तरह के विशेषज्ञों का अभाव रहा है. ऐसे में मुख्य भूमि से विशेषज्ञों को मोटी रकम देकर बुलाना पड़ता है. इसके बावजूद अब तक दो दर्जन से भी अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं.

अंडमान में क़रीब 8 महीने तक बरसात होती है. ऐसे में मौसम के मिजाज़ में उथल-पुथल मची रहती है. ख़राब मौसम होने से मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में जाना आसान नहीं होता, इसलिए महिलाएं मछलियों को सुखा कर रख लेती हैं और उनका अचार बनाकर स्थानीय बाज़ार एवं एंपोरियम में बेचा जाता है. इसी तरह अंडमान के क़रीब 50 फ़ीसदी भू-भाग में नारियल की पैदावार होती है, लेकिन नारियल को सीधे कोलकाता या फिर चेन्नई भेज दिया जाता है. जबकि इसके प्रसंस्करण से स्थानीय लोगों को आय के साधन उपलब्ध हो सकते हैं. बकौल सी मोहम्मद, थोड़े कच्चे नारियल के दूध से स्वादिष्ट जैम बनाया जा सकता है. यह पूरी तरह से आर्गेनिक और अप्रदूषित है. पोर्ट ब्लेयर से क़रीब 10 किलोमीटर दूर स्थित डॉलीगंज की एस कृष्णा कुमारी भी उन सैकड़ों महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने खाद्य प्रसंस्करण के काम को अपनाया है. कृष्णा कुमारी बताती हैं कि वह डॉलीगंज में 12 लोगों के स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं. समूह के सभी सदस्य झींगों एवं मछली के अचार के अलावा नारियल जैम भी बनाते हैं. वह कहती हैं कि हम समय-समय पर आर्डर मिलने पर पेपर, रस्सी और मशरूम की भी आपूर्ति करते हैं. हालांकि अंडमान की भौगोलिक परिस्थितियों एवं अत्यधिक वर्षा के कारण मशरूम उत्पादन बहुत अधिक सफल नहीं रहा. जबकि नारियल जैम और मछली-झींगों के अचार को स्थानीय लोगों के अलावा राज्यपाल और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सराहा. बकौल कृष्णा कुमारी, अन्य काम करते हुए इससे समूह की महिलाओं को क़रीब चार-पांच हज़ार रुपये तक अतिरिक्त आमदनी हो जाती है, जिससे घर ख़र्च आसानी से चल जाता है. बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिलाई जा सकती है.

मुख्य भूमि से दूर होने के कारण अंडमान में अव्वल तो बहुत सी चीजें उपलब्ध ही नहीं हैं और अगर उपलब्ध हो भी जाएं तो उनकी मनमानी क़ीमत वसूली जाती है. इन परिस्थितियों का सामना प्रसंस्करण के काम से जुड़ी महिलाओं को भी करना पड़ता है.

मुख्य भूमि से दूर होने के कारण अंडमान में अव्वल तो बहुत सी चीजें उपलब्ध ही नहीं हैं और अगर उपलब्ध हो भी जाएं तो उनकी मनमानी क़ीमत वसूली जाती है. इन परिस्थितियों का सामना प्रसंस्करण के काम से जुड़ी महिलाओं को भी करना पड़ता है. कृष्णा बताती हैं कि मछली के प्रसंस्कृत उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक 28 तत्वों में से एक सोडियम बेंजॉयट अंडमान में नहीं मिलता. नारियल उत्पादों में उपयोग होने वाले 16 तत्वों में से साइट्रिक एसिड एवं पेक्टिन भी आसानी से नहीं मिलता, जिसके कारण खाद्य प्रसंस्करण के नियमित काम में बाधा पहुंचती है. को-ऑपरेटिव सोसायटियों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इस समस्या को लेकर राज्यपाल, मुख्य सचिव और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार मुलाकात की. काफी जद्दोज़हद के बाद प्रशासन ने इस बात का भरोसा दिलाया कि प्रसंस्करण में उपयोग होने वाले ज़रूरी तत्वों को मंगा कर सब्सिडी पर उत्पादकों को मुहैया कराया जाएगा. आत्मनिर्भरता की ओर क़दम बढ़ाने को आतुर अंडमान के लोगों के लिए यह निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, लेकिन यह समस्या ख़त्म हुई तो दूसरी तरफ़ एक और समस्या मुंह बाए खड़ी थी. अभी तक तो मेलों, प्रदर्शनियों और स्थानीय बाज़ार में इन प्रसंस्कृत उत्पादों को बेचा जा रहा था. उत्पादन बढ़ने के साथ एक ओर जहां विस्तृत बाज़ार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, वहीं लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क और गुणवत्ता के मानकों पर खरे उतरने की चुनौतियां भी सामने आने लगीं. फिलहाल उक्त चुनौतियां प्रसंस्करण के काम में जुटे स्वयं सहायता समूह एवं को-ऑपरेटिव सोसायटियों के सदस्यों के लिए मुसीबत बन चुकी हैं. अंडमान में इससे पहले न तो स्वयं सहायता समूहों को लेकर बहुत अधिक काम हुआ था, न को-ऑपरेटिव और न ही खाद्य प्रसंस्करण में हाथ आजमाया गया था. व्यवसायिक उद्यमों के बहुत सीमित होने से सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग और ट्रेडमार्क प्रदान करने वाली मशीनरी लगभग शिथिल अवस्था में है. लाइसेंसिंग अथॉरिटी का केंद्र अभी भी कोलकाता है. बहरहाल समूह की महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी और वे लगातार लाइसेंसिंग अथॉरिटी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश में जुटी रहती हैं. उन्नति संस्था के निदेशक सी मोहम्मद इस काम के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का सहयोग करते रहते हैं. कृष्णा बताती हैं कि कमर्शियल लाइसेंस न मिलने से हमारा काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है. जब भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के प्रमुख से मिलने की कोशिश की जाती है तो उनके सिपहसालार मिलने नहीं देते.

लंबे समय तक समूह के सदस्यों को अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कोई महफूज स्थान भी उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब खाद्य प्रसंस्करण की उपयोगिता को देखते हुए मत्स्य विभाग का एक भवन उपलब्ध करा दिया गया है. इससे उत्पादकों को मिलजुल कर काम करने में सहूलियत हो गई है. हालांकि प्रशासन की ओर से प्रसंस्कृत उत्पादों की मार्केटिंग का भी भरोसा दिलाया गया है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा.

feedback@chauthiduniya.com

इतिहास में झांकने से हमें पता लगेगा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से भारत सरकार का कोई लेना-देना नहीं था.

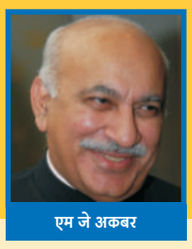

एम जे अकबर

प्रधानमंत्री काग़ज़ की नाव के कप्तान न बन जाएं

इस से मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा विरोधाभास कहिए या फिर उनकी सबसे बड़ी मजबूरी, लेकिन सच्चाई यही है कि उनकी गठबंधन सरकार की शक्ति उनकी कमज़ोरी में ही निहित है. गठबंधन इसी वजह से टिका है कि प्रधानमंत्री का अपने सहयोगियों पर कोई नियंत्रण नहीं है. एक मंत्री के हाथ टेलीकॉम घोटाले में सने मिलते हैं, लेकिन वह बेशर्मी से आरोपों से इंकार कर देता है. एक अन्य मंत्री के पास कैबिनेट की बैठकों के लिए भी समय नहीं है. एक मंत्री ऐसी हैं, जो रेलवे जैसे आम लोगों से सरोकार वाले मंत्रालय को भी कोई अहमियत नहीं देतीं, क्योंकि यह उनकी व्यक्तिगत पहचान को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करता. प्रधानमंत्री ज़बरदस्ती मुस्कराने के सिवा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह मुस्कराहट अब छोटी होती जा रही है. यूपीए के पहले कार्यकाल के मुक़ाबले इसके दूसरे कार्यकाल में एक बड़ा ही आधारभूत बदलाव आ चुका है. गठबंधन की पहली पारी में इसके छोटे साझेदारों को कांग्रेस की ज़रूरत थी, लेकिन दूसरी पारी में कांग्रेस सत्ता में इसीलिए बनी हुई है, क्योंकि तृणमूल, डीएमके और एनसीपी जैसे छोटे दल ऐसा ही चाहते हैं. कांग्रेस के वर्तमान और भविष्य के लिहाज़ से उसका सत्ता में बने रहना बेहद अहम है, इसलिए सभी दलों ने सरकारी कामकाज में शुचिता और उत्तरदायित्व की भावना को भुलाकर उसे स्थायित्व का लबादा पहना दिया है. लेकिन इसका सबसे बुरा असर सरकार की साख पर पड़ रहा है. यह पहले ही कमज़ोर पड़ती जा रही थी, लेकिन अब इसकी गति लगातार तेज होती जा रही है. सरकार की तुलना में ख़ुद मनमोहन सिंह की छवि अभी भी बेदाग है, लेकिन उन्होंने जल्द क़दम नहीं उठाए तो यह गति इतनी तेज हो जाएगी कि इस पर लगाम कसना असंभव हो जाएगा.

कमज़ोरी के साथ समस्या यह है कि यह संक्रामक होती है. यह शरीर के उन अंगों को भी शिथिल बना देती है, जो सामान्य ढंग से काम कर रहे होते हैं. कांग्रेस पार्टी के मंत्री पहले भी यह जानते थे कि उनके पद और सारे सुख- सुविधाएं पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के रहमोकरम पर हैं, लेकिन यूपीए के पहले कार्यकाल में फिर भी वे प्रधानमंत्री को आवश्यक तवज्जो देते रहे, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि मतदान के दिन जब मतदाता बूथ पर जाएगा तो प्रधानमंत्री की स्वच्छ छवि निर्णायक साबित हो सकती है और यह उनके निर्वाचन में मददगार हो सकता है. लेकिन अब यह सोच कमज़ोर पड़ चुकी है, क्योंकि किसी को यह उम्मीद नहीं कि अगले आम चुनावों में मनमोहन सिंह पार्टी का नेतृत्व करेंगे. अपनी एकमात्र प्रेस कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को अप्रत्यक्ष सहमति दे दी थी, जबकि इसका आयोजन प्रधानमंत्री की ताक़त बताने के लिए किया गया था. अपने चिर-परिचित अंदाज़ में उन्होंने मान लिया कि जैसे ही उन्हें कहा जाएगा, वह राहुल गांधी के लिए अपना पद छोड़ देंगे.

सत्ता बड़ी चंचला होती है, वह कभी स्थिर नहीं रहती. यह या तो नेता के इर्द-गिर्द मज़बूत होती रहती है या फिर कमज़ोर हो जाती है. ऐसे लोग, जो मनमोहन सिंह के बाद अपना भविष्य देख रहे हैं, वे सामूहिक हितों की क़ीमत पर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं. सरकार के सामने दो सबसे गंभीर समस्याओं में पहली है पाकिस्तान के साथ ख़राब रिश्ते, जिसका स्वरूप आतंकवाद के चलते और भी ज़्यादा विकृत हो चुका है. दूसरी समस्या है नक्सलवाद का बढ़ता ख़तरा, जिसकी जड़ में बढ़ती ग़रीबी और दशकों की सरकारी उपेक्षा है. इन दोनों ही मुद्दों पर सरकार एकमत नहीं है. गृह सचिव जी के पिल्लई ने जब विदेश मंत्री एस एम कृष्णा के पाकिस्तान दौरे के बीच में ही आईएसआई एवं पाकिस्तानी नौसेना द्वारा मुंबई हमले के गुनहगारों को मदद देने संबंधी डेविड हेडली के रहस्योद्घाटन को सार्वजनिक कर दिया तो कृष्णा के माथे पर पड़ी

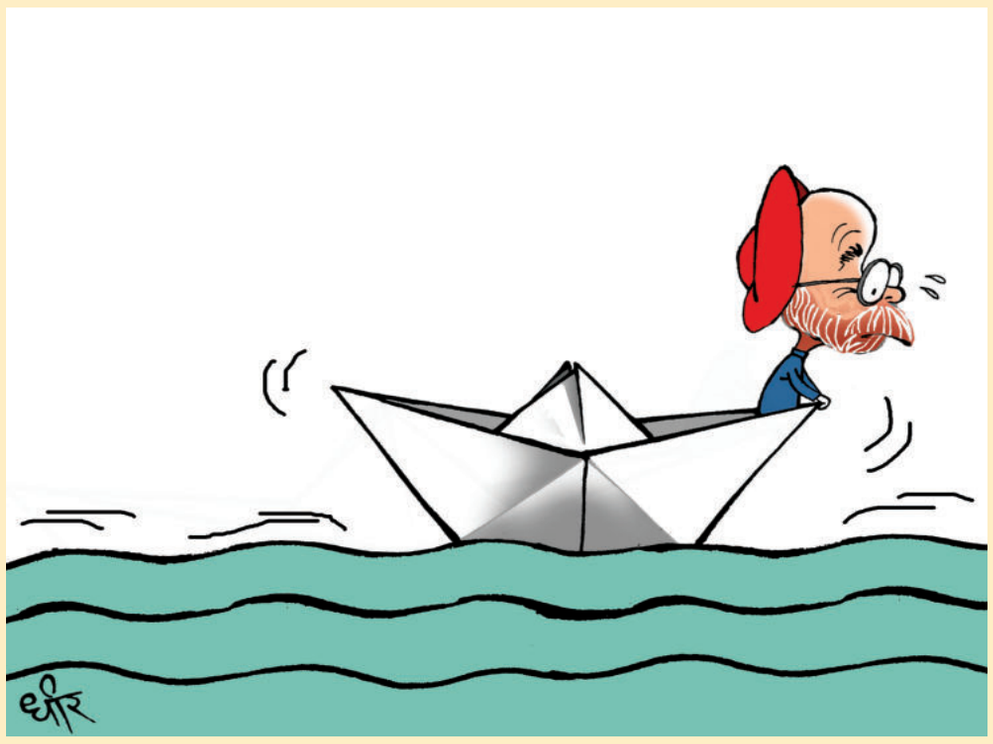

सलवटें और उनकी असहजता को स्पष्ट देखा जा सकता था. विदेश मंत्री पड़ोसी देश के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के इरादे से पाकिस्तान यात्रा पर गए थे, लेकिन पिल्लई को यह निर्देश गृहमंत्री पी चिदंबरम से मिला था और इसे न मानने की सूरत में उन्हें अपना पद भी छोड़ना पड़ सकता था. प्रधानमंत्री ने इस नाटक की अनदेखी करने में ही अपनी भलाई समझी. यदि आप सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यह तरीक़ा अच्छा है, लेकिन सरकार चलाने के लिहाज़ से यह ठीक नहीं है. मनमोहन सिंह की समस्या यह है कि उनके साथ एक ही विरोधाभास नहीं है. वह एक नहीं, बल्कि एक साथ दो गठबंधनों का नेतृत्व कर रहे हैं. अलग-अलग हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले गुटों में बंटी ख़ुद कांग्रेस पार्टी ही दूसरा गठबंधन है. सामान्य परिस्थितियों में भी इन गुटों के बीच आपसी खींचतान चलती रहती है और इनके बीच शक्ति संतुलन का ध्यान रखना मजबूरी है. व्यक्तित्व या अहं की लड़ाइयां तो केवल सतही बातें हैं, सच्चाई तो यह है कि नीतिगत मुद्दों पर भी मतभिन्नताएं काफी गहरी हैं. यह अच्छा भी है, लेकिन केवल एक सीमा तक. जब इस सीमा का अतिक्रमण होने लगे तो नेता सरकार के निर्णयों को लेकर एक समान प्रतिबद्धता की मांग कर सकता है. यदि उन्हें शीर्ष नेतृत्व की मूक सहमति नहीं होती तो दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ ने नक्सलवाद के मुद्दे पर चिदंबरम को बार-बार एक भ्रमित और अक्खड़ बुद्धिजीवी कहने का साहस न किया होता. सबसे भली चुप्पी, प्रधानमंत्री ने स्वयं को इसी कहावत के दायरे में बांध लिया है. लेकिन वह शायद यह भूल रहे हैं कि लोकतंत्र में चुप्पी और स्थिति निरपेक्षता के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती. एक कमज़ोर प्रधानमंत्री की सरकार भी कमज़ोर ही होती है. भटकाव, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, कभी जल्दबाज़ी में नहीं होता. कोई यह समझ पाए कि सरकार अपने रास्ते से भटक चुकी है, इससे पहले वह एक लंबा सफर तय कर चुकी होती है. भटकाव से सरकार के अस्तित्व को कोई ख़तरा पैदा नहीं होता, लेकिन यह आम लोगों के धैर्य को निचोड़ लेता है.

तीसरा विरोधाभास पहली नज़र में अविश्वसनीय भले लगे, लेकिन समझने में सबसे आसान है. किसी मज़बूत सरकार के मुक़ाबले एक कमज़ोर सरकार को चलाना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है. हर मज़बूत सरकार का एक स्पष्ट नेतृत्व होता है, घोषित लक्ष्य होते हैं और अनुशासन का एक नियम होता है. इन सब चीजों की मौजूदगी से मतदाताओं में विश्वास पैदा होता है. एक कमज़ोर सरकार अख़बारों के लिए अच्छी ख़बर हो सकती है, ख़बर को कहानी बनाने वाले न्यूज़ चैनलों के लिए अच्छा चारा हो सकती है, लेकिन उसकी इंटरटेनमेंट वैल्यू यहीं ख़त्म हो जाती है. अपने पहले कार्यकाल में मनमोहन सिंह इतने सक्षम थे कि आख़िरी बारह महीनों में तमाम झंझावातों के बावजूद वह सरकार की नैया पार लगाने में सफल रहे. 2009 के आम चुनावों में मिली जीत के बाद तो उनमें समुद्री तूफान के बीच से बड़े जहाज को सुरक्षित निकाल लेने का विश्वास पैदा हो जाना चाहिए था, लेकिन वह यदि इसी तरह कुछ न करने का मन बनाए बैठे रहे तो कहीं काग़ज़ की नाव के कैप्टन बनकर न रह जाएं.

feedback@chauthiduniya.com

अयोध्या राम और रहीम दोनों का घर

वर्ष 1992 का 6 दिसंबर भारत के लिए एक अत्यंत त्रासद दिन था. उस दिन 450 साल पुरानी ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को संघ परिवार (आरएसएस, भाजपा, विहिप, बजरंग दल आदि) ने ढहा दिया. मस्जिद के स्थान पर तुरत-फुरत एक कामचलाऊ मंदिर खड़ा कर दिया गया. तभी से संघ परिवार उस स्थान पर एक स्थायी मंदिर बनाने की मांग और कोशिशें करता आ रहा है. आरएसएस का दावा है कि राम मंदिर को गिराकर उस स्थल पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी. यद्यपि उसके इस दावे के समर्थन में कोई पुरातत्वीय या ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. संघ का तर्क है कि भगवान राम के जन्म स्थान का निर्धारण आस्था के आधार पर होगा और इस मामले में वह साधुओं और महंतों के मार्गदर्शन में चलेगा.

ज़मीन के उस टुकड़े, जिस पर बाबरी मस्जिद थी, का मालिक कौन है, इसे लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में कई सालों से चार मुक़दमे चल रहे हैं. इनमें से तीन मामलों में अंतिम तर्क हो चुके हैं. चौथे एवं आख़िरी मामले में अगले माह तक अंतिम तर्क समाप्त हो जाएंगे. जहां हम सब इन मुक़दमों के निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं संघ परिवार ने साफ कर दिया है कि फ़ैसला चाहे जो भी हो, वह तो राम मंदिर के निर्माण के लिए दबाव बनाएगा. विहिप आदि का कहना है कि विवादित स्थल पर मस्जिद का निर्माण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विहिप के अनुसार तो मस्जिद का निर्माण पूरे अयोध्या में ही नहीं हो सकता. मस्जिद केवल तुलसीदास के रामचरित मानस द्वारा निर्धारित अयोध्या की शास्त्रीय सीमा के बाहर ही बन सकती है. अर्थात विहिप का कहना है कि अयोध्या केवल हिंदुओं की है. इस बीच भाजपा एवं अन्य संगठनों को यह निर्देश दिया गया है कि वे ठीक उसी स्थान पर राम मंदिर बनाए जाने की मांग जोर-शोर से उठाएं, जिस स्थान पर उन्होंने 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहाया था.

अयोध्या (अ+युद्धया) का अर्थ ही है युद्ध-मुक्त क्षेत्र. अयोध्या केवल हिंदुओं का पवित्र नगर नहीं है. अयोध्या हिंदू धर्म के अलावा, बौद्ध एवं जैन धर्मों का भी प्रमुख केंद्र रही है. ईसा पूर्व पांचवीं सदी से लेकर सैकड़ों सालों तक अयोध्या मुख्यत: बौद्धों का नगर था. यद्यपि बौद्ध धर्म आगे चलकर कमज़ोर पड़ गया, तथापि अयोध्या में आज भी बौद्ध पवित्र स्थलों के अवशेष मौजूद हैं. जैन परंपरा के अनुसार, अयोध्या पहले एवं चौथे जैन तीर्थंकर का जन्म स्थल थी. हिंदू धर्म के संदर्भ में भी अयोध्या शुरू में शैव एवं वैष्णव पंथों की तीर्थस्थल थी. राम की पूजा तो वहां बहुत बाद में शुरू हुई. विष्णु के अवतार के तौर पर भी राम की मूर्तियों के अयोध्या में अस्तित्व के सबसे पहले प्रमाण छठवीं सदी ईस्वी में मिलते हैं. अवध के नवाब ने अयोध्या में पूरे अवध के सबसे बड़े मंदिर के निर्माण के लिए ज़मीन दान में दी थी और वहां राम का नहीं, वरन हनुमान का मंदिर बनाया गया था. वह मंदिर हनुमानगढ़ी कहलाता है और आज भी अयोध्या का सबसे बड़ा मंदिर है.

एक मांग यह भी की जा रही है कि विवादित भूमि सरकार को अधिग्रहीत कर लेनी चाहिए और वहां सोमनाथ की तरह राम मंदिर बनाना चाहिए. आडवाणी और कई अन्य नेता यह दावा कर रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराने का निर्णय नेहरू मंत्रिमंडल ने लिया था. चूंकि आमजन किसी भी बात को बहुत लंबे समय तक याद नहीं रखते, इसलिए बार-बार दोहराने से झूठ भी उन्हें सच लगने लगता है. हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबेल्स अपने नेता के अनुयायियों को यही सिखाते थे और आडवाणी भी संभवत: इसी नीति पर चलते हैं.

इतिहास में झांकने से हमें पता लगेगा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से भारत सरकार का कोई लेना-देना नहीं था. अपनी व्यक्तिगत हैसियत से सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से नेहरू मंत्रिमंडल के दो सदस्य जुड़े ज़रूर थे, परंतु यह कहना ग़लत है कि नेहरू सरकार ने सोमनाथ मंदिर बनवाया था या उसके निर्माण में कोई सहयोग किया था. जब सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाया तो गांधी जी ने तुरंत कहा था कि हिंदू अपना मंदिर बनाने में ख़ुद सक्षम हैं और उन्हें सरकार से न तो मदद की ज़रूरत है, न पैसे की और न ही सरकार को इस काम के लिए धन देना चाहिए.

सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू मंत्रिमंडल के दो सदस्यों के एम मुंशी और एन व्ही गाडगिल ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से पुनर्निर्माण के कार्य में भाग लिया था. इस संबंध में कोई प्रस्ताव कैबिनेट में न तो रखा गया और न ही पारित हुआ. जैसा कि सांप्रदायिक ताक़तों द्वारा दावा किया जा रहा है. मंदिर बन जाने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उसका उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया. उन्होंने नेहरू की इच्छा के विरुद्ध यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया. पंडित नेहरू की मान्यता थी कि उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को किसी धर्म या धर्मस्थल से सार्वजनिक रूप से नहीं जुड़ना चाहिए.

सांप्रदायिक ताक़तों द्वारा सोमनाथ मंदिर के बारे में झूठ जानबूझ कर फैलाया जा रहा है, ताकि अदालत का निर्णय चाहे जो हो, विवादित स्थल पर मंदिर के निर्माण के लिए दबाव बनाया जा सके. बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने की घटना को आज लगभग 18 साल बीत चुके हैं. इस अवधि में राम मंदिर आंदोलन ने हमारे देश को कितना नुक़सान पहुंचाया है और राजनीति को किस कदर प्रदूषित कर दिया है, यह हम सबके सामने है. हमें यह भी याद रखना होगा कि बाबरी मस्जिद के ढहाने जाने के तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हाराव ने यह ऐलान किया था कि

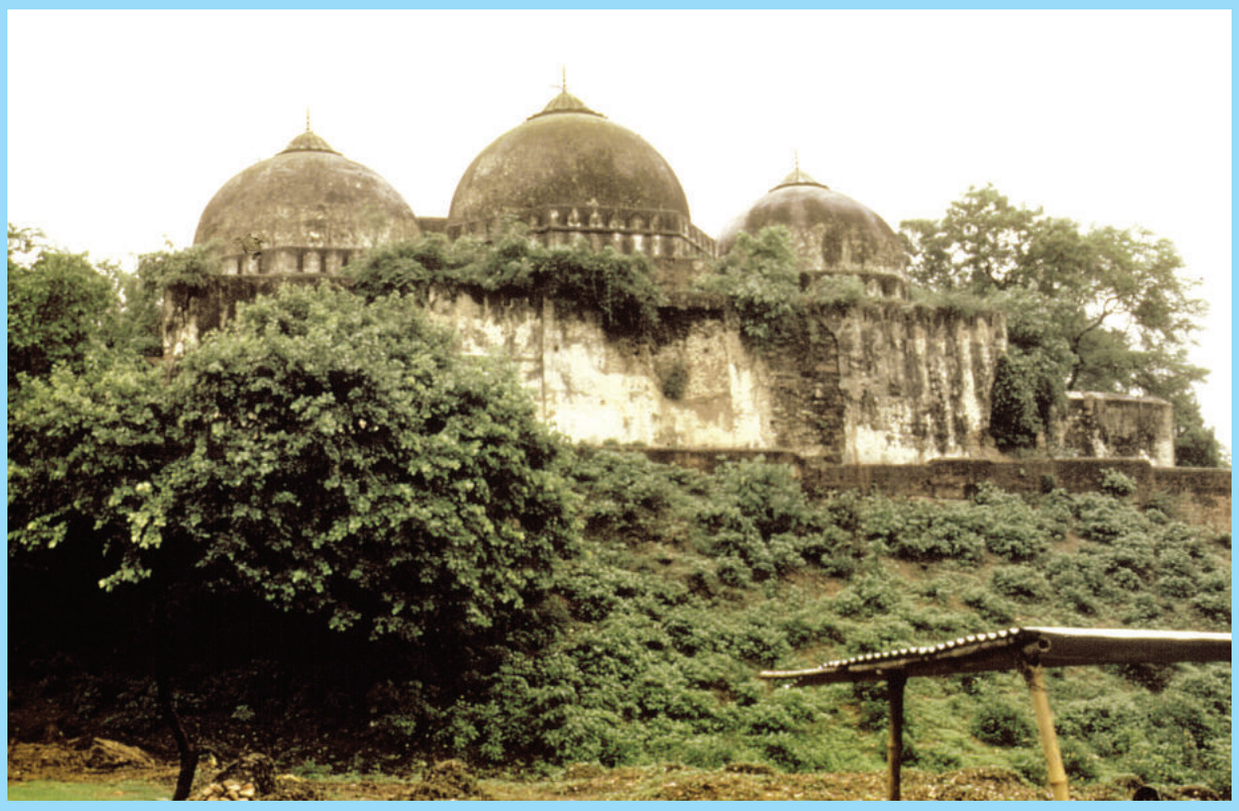

उसी स्थान पर दोबारा मस्जिद बनाई जाएगी. अगर उस स्थल पर मंदिर बनाया जाता है तो यह संघ परिवार द्वारा किए गए अपराध को वैधता प्रदान करना होगा. आखिर विवादित स्थल का क्या किया जाए? इस बारे में अलग-अलग राय है. अधिकांश मुस्लिम संगठनों का कहना है कि अदालत के निर्णय को स्वीकार किया जाना चाहिए. विहिप आदि इस बात पर आमादा हैं कि अदालत चाहे जिस नतीजे पर पहुंचे, वहां मंदिर ही बनाना चाहिए. मस्जिद ढहाने के पूर्व से ही हिंदू संगठन यह कहते रहे हैं कि उनकी नीति की निर्धारक आस्था होगी. किसी भी प्रजातंत्र में क़ानून का राज होना चाहिए. इस समय आवश्यकता इस बात की है कि क़ानून का सम्मान किया जाए और सांप्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ावा दिया जाए. बाबरी विध्वंस की घटना के बाद से देश में सांप्रदायिक सद्भाव को गहरी चोट पहुंची है. दोनों समुदाय एक दूसरे को संदेह की निगाह से देखने लगे हैं. सांप्रदायिकता की खाई और चौड़ी हो गई है और समाज के कमज़ोर वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है.

राजनीतिक दलों द्वारा झूठ पर आधारित भावनात्मक अभियान चलाना संविधान के मूल्यों के अनुरूप नहीं है. जनप्रतिनिधि भारतीय संविधान के अनुरूप आचरण करने के लिए बाध्य हैं. ज़रूरत इस बात की है कि हम सब एकमत से यह निर्णय लें कि हम भारत के संविधान में निहित स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों की रक्षा करेंगे.

(लेखक आईआईटी, मुंबई के पूर्व प्राध्यापक हैं)

राम पुनियानी
feedback@chauthiduniya.com

कार्रवाई ज़रूरी

मैं चौथी दुनिया अख़बार का नियमित पाठक हूं. वैसे तो हर बार ही आप देश के गंभीर मुद्दों को बड़े बेबाकी से उठाते हैं, लेकिन नक्सलवाद को लेकर आप जिस तरह सरकार के मुखौटे को सामने लाए हैं, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, कम है. मेरा मानना है कि जो कंपनियां, माफ़िया एवं बड़े-बड़े लोग नक्सलियों को फंड देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्र सरकार की चुप्पी का खुलकर विरोध होना चाहिए.

-राज सिंह, रांची, झारखंड.

गडकरी की भाषा

आख़िर नितिन गडकरी के स्कूल का हेडमास्टर कौन है, इसका पता लगाना चाहिए. गडकरी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा के अध्यक्ष हैं और अगर टीम के कप्तान की ही ज़ुबान बहकने लगे तो उसके शागिर्दों का क्या हाल होगा. आश्चर्य है कि आज ऐसे ही लोग देश को चलाने और सुधारने की बातें करते हैं.

-हेमलता सिन्हा, देहरादून, उत्तराखंड.

समाधान के लिए बात

बातचीत का यह कैसा तरीक़ा है, लेख पढ़ा. सच लिखा है आपने. देश के ख़िलाफ़ साज़िश कर रहे आतंकी भारत-पाक के बीच बातचीत के तरीक़ों से ख़ुश होते होंगे. दरअसल दोनों देशों के नेताओं को समाधान निकालने के मक़सद से ही बात करनी होगी, जो शायद पाक नहीं कर रहा है. ऐसे में ख़तरा केवल भारत को ही नहीं, पाक को भी है.

-ओमप्रकाश झा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल.

वादों का भ्रमजाल

बिहार में वैसे तो नीतीश कुमार की सरकार ने ढेरों वादे किए, लेकिन उनमें से कितने वादे हक़ीक़त में तब्दील हुए, यह सबको पता है. हिंदू हो चाहे मुसलमान, आज सभी वादों के भ्रमजाल में ही जी रहे हैं. एक बार फिर वक्त चुनाव का है, ऐसे में सबको जागना होगा और सरकार की लापरवाही का मुंह तोड़ जवाब देना होगा.

-संदीप आनंद, बेगूसराय, बिहार.

दोमुंही राजनीति

आपने भारत के मुस्लिम समाज की स्थिति के बारे में जो बताया, वह काफी चौंकाने वाला है कि कैसे मुस्लिम समाज भारत की जनतांत्रिक व्यवस्था में दोयम दर्जे का नागरिक होकर रह गया है. ख़ुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले नेता मुस्लिम समाज के वोटों के सहारे अपनी राजनीति तो चमकाते हैं, लेकिन उसे मुख्यधारा में लाने से डरते हैं.

-पंकज बाबू, ई-मेल से.

सरासर अन्याय

भारतीय सिनेमा, टीवी, इंटरनेट, समाचारपत्र-पत्रिकाएं सेक्स फ्लू फैलाने वाले विज्ञापनों से भरे पड़े हैं. साबुन-शैंपू से लेकर कार तक के विज्ञापन में औरतों के नंगेपन को दिखाया जा रहा है. सवाल यह है कि जब कोई गरीब औरत अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पैसे लेकर नंगी होती है तो उसे वेश्या कहा जाता है, लेकिन जब कोई औरत सिर्फ अपने ऐशोआराम के लिए पैसा लेकर टीवी और सिनेमा में नंगी होती है तो उसे कलाकार कहा जाता है. यह कहां का न्याय है?

-चंद्र वर्मा, ई-मेल से.

दिग्विजय सिंह और चौथी दुनिया

इस स्वार्थी एवं कुटिल दुनिया में अच्छे लोगों का भला क्या काम? परमात्मा अच्छे लोगों को दु:ख से मुक्त करने के लिए उन्हें अपने पास बुला लेते हैं. क्या यही दर्शन स्वर्गीय दिग्विजय सिंह पर लागू हो सकता है? अच्छा आलेख प्रस्तुत करने के लिए चौथी दुनिया का आभार. शुभकामनाएं.

-डॉ. पुरुषोत्तम मीणा निरंकुश, ई-मेल से.

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें.
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

यह पाकिस्तान की मजबूरी है

संतोष भारतीय

एक महीने पहले जब मैंने यह लिखा था कि पाकिस्तान में सेना दस्तक दे रही है तो कई लोगों ने आश्चर्य जताया. दरअसल सारे संकेत इस ओर इशारा कर रहे थे कि सितंबर महीने तक सेना सत्ता पर क़ाबिज़ हो जाएगी. इसी बीच प्रधानमंत्री गिलानी ने जल्दबाज़ी में आयोजित देश के नाम संबोधन में कयानी को तीन साल का सेवा विस्तार देने की घोषणा कर दी. दरअसल, गिलानी का यह क़दम देश की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार के लिए एक मजबूरी था और निश्चित लग रहे सैन्य तख्ता पलट को टालने का ज़रिया भी.

सेना में स्थिरता पाकिस्तान की ज़रूरत है. वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल के बीच में किसी दूसरे सेनाध्यक्ष पर भरोसा नहीं कर सकती. जनरल कयानी को नवंबर में रिटायर होना था. सरकार अगर किसी और को जनरल नियुक्त करती तो दो स्थितियां पैदा हो सकती थीं. जनरल कयानी या तो करामात की तरह बाइज़्ज़त कुर्सी छोड़ देते या फिर मुशर्रफ़ की तरह सर्वशक्तिमान बन जाते. अगर वह कुर्सी छोड़ देते तो नवंबर के बाद नया सेनाध्यक्ष क्या करता, यह कोई नहीं जानता. ऐसी परिस्थिति बन सकती थी, जो पाकिस्तान की सरकार के साथ-साथ अमेरिका के लिए भी मुश्किलें पैदा करती. इस मायने में यह फ़ैसला एक मास्टर स्ट्रोक है. इस फ़ैसले से पाकिस्तान की सरकार के साथ-साथ अमेरिका को भी फ़ायदा मिलेगा. जनरल कयानी के लिए अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की जनता उन्हें प्रजातंत्र के समर्थक के रूप में जानती है. उन्हें प्रजातंत्र के लिए ख़तरा नहीं मानती. यह फ़ैसला अमेरिका के लिए इसलिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जनरल कयानी ने जनरल मुशर्रफ से बेहतर तरीक़े से स्वात और दक्षिण वज़ीरिस्तान में आतंकवादियों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है.

घटना पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच हुई वार्ता की है. भारत के विदेश मंत्री एस एम कृष्णा का पाक प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी के साथ मिलने का कार्यक्रम तय था. इसी बीच सेना प्रमुख जनरल अशफाक कयानी गिलानी से मिलने पहुंचे और कृष्णा के साथ उनकी मीटिंग को टाल दिया गया. यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि पाकिस्तान में सत्ता का केंद्र कहां स्थित है. सच्चाई तो यह है कि कयानी को सेवा विस्तार न मिलता तो पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी. पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है, जब सेना प्रमुख को किसी चुनी हुई सरकार द्वारा सेवा विस्तार हासिल हुआ है. हालात इसी ओर इशारा करते हैं कि सरकार ने यह फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से नहीं लिया. गिलानी ने यह निर्णय अमेरिकी दबाव में लिया है.

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान और अलक़ायदा के ख़िलाफ़ जारी कार्रवाई में पाकिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण है और अमेरिका यह नहीं चाहता कि उसमें कोई खलल पड़े. पाकिस्तान में अगले आम चुनाव 2013 में संभावित हैं और अमेरिका की इच्छा यही है कि अगली सरकार ऐसी हो, जो उसके मुताबिक़ काम करे. इस लिहाज़ से कयानी की भूमिका काफी अहम है. पाकिस्तान की अंदरूनी हालत अच्छी नहीं है. देश भर में हो रही आतंकी वारदातों, फ़र्ज़ी डिग्री घोटाले और हत्या की साजिश में केंद्रीय मंत्री की संलिप्तता की ख़बरों के चलते आम जनता निराश है. देश के अधिकांश हिस्सों में क़ानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. जनता राजनीतिक नेतृत्व से निराश है, न्यायपालिका देश की हालत से ज़्यादा अपनी शक्तियों को लेकर फ़िक्रमंद है. कयानी ने इस मौक़े का भरपूर फ़ायदा उठाया. वह सामने नहीं थे, लेकिन सत्ता का सूत्र उन्हीं के हाथों में था. भारत के साथ संबंधों की बात हो या अफ़ग़ानिस्तान में जारी संघर्ष, पर्दे के पीछे सारे फ़ैसले सेना ही ले रही है. कयानी ने पहले तो गिलानी और ज़रदारी के बीच जंग को हवा दी और आज ऐसी हालत में हैं कि बिना किसी ज़िम्मेदारी के सत्ता के शीर्ष पर बने हुए हैं.

कयानी के सेवा विस्तार को केवल सैन्य मामलों से संबंधित एक प्रशासनिक निर्णय के रूप में देखना ग़लत होगा, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात और दूसरा ख़ुद कयानी का पिछला रिकॉर्ड इसकी गवाही नहीं देते. अपने पूरे करियर में कयानी हमेशा मुल्क के राजनीतिक नेतृत्व के साथ अपनी निकटता बनाए रखने में कामयाब रहे हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो. बदलते राजनीतिक माहौल के साथ अपनी प्रतिबद्धताएं बदलने में उनका कोई सानी नहीं. वह बेनजीर भुट्टो के प्रधानमंत्रित्व काल में डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी हुआ करते थे तो परवेज़ मुशर्रफ़ की सैन्यशाही के दौर में उनके निकटतम सहयोगियों में शामिल थे, जबकि भुट्टो परिवार के प्रति मुशर्रफ़ की नफ़रत किसी से छुपी नहीं है.

कयानी पाकिस्तानी सेना के उस धड़े से जुड़े हैं, जो आईएसआई के साथ मिलकर आतंकी संगठनों को बढ़ावा देता है. सैन्य तख्ता पलट की इस योजना में कयानी को पाक सेना के साथ आतंकी संगठनों, कट्टरवादी राजनीतिक पार्टियों और अमेरिका का भी समर्थन हासिल था. ऐसी हालत में गिलानी सरकार के सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा था और उसे कयानी को तीन साल का सेवा विस्तार देने के लिए मजबूर होना पड़ा.

सुप्रीमकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चौधरी की पुनर्बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे पीएमएल-एन के नेता नवाज़ शरीफ़ को इस्लामाबाद मार्च से रोकने में भी उनकी ही भूमिका सबसे अहम थी. पिछले तीन सालों के दरम्यान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रपति ज़रदारी और उनकी ही पार्टी के प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी के बीच जारी सत्ता संघर्ष को बढ़ावा देने में भी उन्होंने अपनी भूमिका बख़ूबी निभाई. इस बीच कयानी अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान के साथ भी अपनी नज़दीकियां बढ़ाने में कामयाब रहे और सेवा विस्तार के इस फ़ैसले के पीछे भी अमेरिकी दबाव की बात सभी मानते हैं. इसके अलावा यह भी एक सच्चाई है कि कयानी पाकिस्तानी सेना के उस धड़े से जुड़े हैं, जो आईएसआई के साथ मिलकर आतंकी संगठनों को बढ़ावा देता है. सैन्य तख्ता पलट की इस योजना में कयानी को पाक सेना के साथ आतंकी संगठनों, कट्टरवादी राजनीतिक पार्टियों और अमेरिका का भी समर्थन हासिल था. ऐसी हालत में गिलानी सरकार के सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा था और उसे कयानी को तीन साल का सेवा विस्तार देने के लिए मजबूर होना पड़ा.

इसमें कोई संदेह नहीं कि कयानी का सेवा विस्तार पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन इसके राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय पहलुओं की अनदेखी नहीं की जा सकती. ख़ासकर, भारत के परिप्रेक्ष्य में सेना प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है. वह जेहनी तौर पर भारत विरोधी रहे हैं. अफ़ग़ानिस्तान में पाकिस्तान समर्थित हक्कानी नेटवर्क द्वारा भारत के हितों को ठेस पहुंचाने की कोशिशें कयानी की सरपरस्ती में ही अंजाम दी जा रही हैं. वह लश्करे तैयबा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की राह में भी रोड़े अटकाते रहे हैं. पिछले दिनों पाकिस्तान में हुए संवैधानिक सुधारों के बाद यह धारणा बनने लगी थी कि मुल्क में सेना के मुक़ाबले सरकार की हालत मज़बूत हुई है. सार्क सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी के बीच हुई बातचीत में जब आतंकवाद के अलावा अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करने की सहमति बनी थी तो उसकी पृष्ठभूमि में भी यही धारणा थी. लेकिन पिछले महीने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई वार्ता जिस तरह से टांय-टांय फिस्स साबित हुई, उसे देखकर तो यही लगता है कि पाकिस्तानी सेना भारत के साथ बातचीत और मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है. कयानी की मौजूदगी के नजरिए से भारत इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता. सबसे ज़्यादा ख़तरा पाकिस्तान को है, क्योंकि अमेरिका के साथ जनरल कयानी की नज़दीकियां इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तानी सेना अब उत्तरी वज़ीरिस्तान में भी युद्ध शुरू करने वाली है.

संपादक

editor@chauthiduniya.com

संघ पर आख़िर निर्णायक कार्रवाई कब?

जाहिद खान

हिंदुस्तानी अवाम को बरसों से सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाने का दावा करने वाले संघ का असली चेहरा एक बार फिर सारे मुल्क के सामने उजागर हुआ है. अभी हाल ही में एक अंग्रेज़ी दैनिक के स्टिंग ऑपरेशन में संघ से मुताल्लिक जो सच्चाइयां निकल कर आई हैं, वे इतनी खतरनाक हैं कि हुकूमत के होश उड़ा दें. संघ से जुड़े चरमपंथी हिंदूवादी संगठन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हत्या की साजिश रच रहे थे, जो कि इत्तेफाक से परवान नहीं चढ़ पाई. हालांकि उन्होंने एक कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बंदोबस्त मजबूत होने के चलते वे कामयाब नहीं हो पाए. अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में एक और सनसनीखेज बात निकल कर सामने आई कि हैदराबाद की मक्का मस्ज़िद और अजमेर शरीफ़ दरगाह पर हुए बम विस्फोट की जानकारी आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत के नज़दीकी सहयोगी इंद्रेश कुमार को पहले से ही थी. इन दोनों बम विस्फोटों को अंजाम देने वाले समूह में इंद्रेश कुमार का एक खास शागिर्द सुनील जोशी शामिल था.

दरअसल यह कोई पहली बार नहीं है, जब संघ का नाम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उछल कर सामने आया है, बल्कि आज़ादी के पूर्व से लेकर आज तक सांप्रदायिक दंगे हों या आतंकी घटनाएं, कमोबेश सभी में उसकी संलिप्तता पाई गई है. आरएसएस और सांप्रदायिक हिंसा तो जैसे एक-दूसरे के पूरक हैं. 1927 में नागपुर से शुरू हुई संघ की सांप्रदायिक हिंसा आज तक जारी है.

स्टिंग ऑपरेशन में श्याम नामक एक शख्स ने बताया कि यह बात उसे और किसी ने नहीं, बल्कि खुद सुनील जोशी ने बताई थी, जिसकी विस्फोटों के राज खुलने के तुरंत बाद हत्या कर दी गई. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मालवांचल का निवासी सुनील जोशी देवास में संघ का प्रचारक था. स्टिंग ऑपरेशन के अलावा इसी तरह की मिली-जुली जानकारियां सीबीआई की जांच से संबंधित दस्तावेजों में भी निकली हैं. मालेगांव बम विस्फोट के मुख्य आरोपियों में से एक दयानंद पांडेय ने महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म दस्ते के सामने यह बात स्वीकार की थी कि उपराष्ट्रपति की हत्या की साजिश में मालेगांव विस्फोट के अहम आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित और दिल्ली के एक भाजपा नेता भी शामिल थे. जाहिर है, हालिया खुलासों से संघ के खौफनाक इरादों का पता चलता है. अपने राष्ट्रवादी चेहरे की आड़ में वह मुल्क में क्या-क्या गुल खिलाता रहता है.

दरअसल यह कोई पहली बार नहीं है, जब संघ का नाम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उछल कर सामने आया है, बल्कि आज़ादी के पूर्व से लेकर आज तक सांप्रदायिक दंगे हों या आतंकी घटनाएं, कमोबेश सभी में उसकी संलिप्तता पाई गई है. आरएसएस और सांप्रदायिक हिंसा तो जैसे एक-दूसरे के पूरक हैं. 1927 में नागपुर से शुरू हुई संघ की सांप्रदायिक हिंसा आज तक जारी है. कल तक वह सांप्रदायिक घृणा फैलाने का काम और छोटे-छोटे दंगे कराता था, लेकिन अब ये दंगे सामूहिक नरसंहार का रूप ले चुके हैं. साल 2002 का गुजरात इसकी एक छोटी सी मिसाल भर है. इसके बावजूद जब भी आरएसएस पर सांप्रदायिकता और आतंकवाद पोषित करने का इल्जाम लगता है तो वह संगठित होकर यह प्रचार करने लगता है कि यह इल्जाम राजनीति से प्रेरित है और एक भी जांच कमीशन ने अपनी तहकीकात में आरएसएस को गुनहगार साबित नहीं किया है. आरएसएस के रक्षक और प्रचारक यहां भी झूठ पर मुलम्मा लगाकर सच को दबाने की कोशिश करते हैं. जबकि इसके उलट सच्चाई कुछ और है. दंगों के तमाम जांच कमीशन यह साबित कर चुके हैं कि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने में अक्सर संघ का कसूर होता है. मदान कमीशन, जगमोहन रेड्डी कमीशन और व्याथ्याथिल कमीशन ने अपनी व्यापक रिपोर्टों में यह विस्तार से बताया है कि संघ सांप्रदायिक घृणा, हिंसा किस सुनियोजित तरीके से भड़काता है. साल 1970 में महाराष्ट्र के भिवंडी, जलगांव और महाड सांप्रदायिक दंगों पर गठित डी पी मदान कमीशन ने अपनी व्यापक रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकाला था, 4 दशक बाद भी सटीक बैठता है. मदान कमीशन रिपोर्ट की खास तौर से इन पंक्तियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है-सांप्रदायिक तनाव सहसा पैदा नहीं होता, इसमें समय लगता है. सांप्रदायिक प्रचार, सांप्रदायिक दंगों और अफवाहों से इसका पोषण होता है. और फिर परिणामस्वरूप लोगों के हृदय घृणा से भर जाते हैं और वे हिंसा पर उतारू हो जाते हैं.

आज़ाद हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगों के इतिहास पर यदि नज़र डालें तो मालूम चलता है कि संघ परिवार सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए हमेशा यही तरीके अपनाता रहा है. अनुशासित प्रदर्शन, परेड एवं शारीरिक व्यायाम को देखकर और भावनात्मक व्याख्यान सुनकर हर कोई मान लेता है कि आरएसएस एक निरीह संगठन है. इस पाखंडपूर्ण विनम्रता और अनुशासन से पढ़े-लिखे समझदार लोग भी धोखा खा जाते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि विनम्रतापूर्वक नमस्ते करने वाले हाथों को खुद से असहमत व्यक्तियों की पीठ में छुरा भोंकने की ट्रेनिंग भी मिली होती है. आठवें दशक में तेल्लिचेरी में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच करने वाले व्याथ्याथिल कमीशन ने दंगों में संघ की भूमिका का बड़ी अच्छी तरह से विश्लेषण किया है. संघ की कार्यपद्धति जानने के लिए इस विश्लेषण पर भी नज़र डालना लाजिमी होगा-यह प्रचार करना कि मुसलमान इस देश के प्रति वफादार नहीं हैं और इस प्रचार के द्वारा बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिक भावना उत्तेजित करना, बहुसंख्यक वर्ग में गहरा भय पैदा करना एवं इस भय ग्रंथि का इस्तेमाल करना, प्रशासन में घुसपैठ करके नागरिक, पुलिस एवं सेना सेवाओं के लोगों में सांप्रदायिक मनोवृत्ति पैदा करना, बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को कटार, तलवार व भाला जैसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना, सांप्रदायिक द्वेष की खाई को चौड़ा करने एवं किसी घटना या आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देने के लिए अफवाएं फैलाना.

जाहिर है, इन सारी रिपोर्टों की बिना पर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुल्क में अभी तक हुए सांप्रदायिक दंगों का ज़िम्मेदार दरअसल कौन है? संघ की इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का ही नतीजा है कि हिंदुस्तानी हुकूमत आजादी के बाद से संघ पर तीन मर्तबा पाबंदी लगा चुकी है. इस पर पहली पाबंदी 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या और सांप्रदायिक घृणा फैलाने के इल्जाम में लगी तो दूसरी इमरजेंसी में. साल 1992 में बाबरी मस्ज़िद विध्वंस के बाद एक बार फिर इस पर पाबंदी लगाई गई. इन पाबंदियों के बावजूद संघ बिल्कुल भी नहीं सुधरा और हर बार पाबंदी हटते ही दोबारा इन्हीं गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं. अब तो अपने खतरनाक मंसूबों को पूरा करने के लिए उसे आतंकवाद से भी कोई गुरेज नहीं है. मालेगांव बम विस्फोट के सिलसिले में महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते द्वारा जनवरी, 2009 में अदालत में पेश की गई चार्जशीट का गंभीरता से अध्ययन करने पर मालूम चलता है कि हिंदुत्ववादी आतंक अब उसकी कार्यपद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. इस प्रकरण में संघ परिवार से जुड़े साधु-साध्वियों से लेकर पूर्व एवं सेवारत सैन्य अफसरों तक का नामजद किया जाना इस पहलू की गंभीरता को उजागर कर देता है. कुल मिलाकर ताज़ा खुलासे और उसके जवाब में संघ के कारकुनों की उग्र, हिंसक प्रतिक्रिया ने एक बार फिर हमारे मुल्क के सामने आसन्न फासीवादी खतरों की ओर इशारा किया है. इन खतरों को लगातार नज़रअंदाज करना कहीं से भी हमारे मुल्क के हित में नहीं है. सांप्रदायिकता और आतंकवाद के खतरों से सख्ती से ही निपटा जा सकता है. संघ परिवार का काला अतीत और हालिया आतंकी घटनाओं में उसकी सक्रिय भूमिका यूपीए सरकार को यह मौक़ा प्रदान करती है कि वह उस पर निर्णायक कार्रवाई करे और यह निर्णायक कार्रवाई होगी देशद्रोह के इल्जाम में संघ पर एक बार फिर पाबंदी.

(लेखक अल्पसंख्यक मामलों के जानकार हैं)

feedback@chauthiduniya.com

अंतरराष्ट्रीय विज्ञान फोरम ऑन एल्कोहल रिसर्च से संबद्ध हेलेना कानिबियर ने कहा कि अधिकांश बुज़ुर्गों की मौत धमनियां बंद हो जाने से होती है.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

द्वितीय अपील कैसे करें

जब लोक सूचना अधिकारी आपके आरटीआई आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता या आपको पूरी सूचना नहीं देता है, तब आप क्या करते हैं? ज़ाहिर है, आप प्रथम अपील करते होंगे. प्रथम अपील का प्रारूप भी चौथी दुनिया में प्रकाशित किया जा चुका है. हम आपको केंद्रीय सूचना आयोग में ऑनलाइन अपील कैसे दर्ज कराते हैं, इसके बारे में भी बता चुके हैं. बहरहाल, प्रथम अपील के बाद भी अगर आपको संतोषजनक सूचना नहीं मिलती है तो द्वितीय अपील करने की नौबत आती है. राज्य सरकार से जुड़े मामलों में यह अपील राज्य सूचना आयोग और केंद्र सरकार से जुड़े मामलों में यह अपील केंद्रीय सूचना आयोग में की जाती है. लेकिन आरटीआई आवेदक के लिए सबसे बड़ी परेशानी है द्वितीय अपील तैयार करना. दरअसल, द्वितीय अपील का प्रारूप बनाने का काम थोड़ा पेचीदा बना दिया गया है, लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. वैसे बता दें कि पहली अपील करने के 90 दिनों के अंदर अथवा पहली अपील के निर्णय आने की तिथि के 90 दिनों के अंदर आप दूसरी अपील दाख़िल कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी हर समस्या के समाधान के लिए आपके साथ है. इस अंक में हम आपके लिए द्वितीय अपील का एक प्रारूप प्रकाशित कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इससे निश्चित रूप से फ़ायदा होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

द्वितीय अपील का प्रारूप

सेवा में,
केंद्रीय/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
पता----------

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील.

क्रमांक	वांछित सूचनाएं	आवेदक द्वारा भरी जाएं
1	आवेदक का नाम और पता.	
2	(क) लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता, जिसके विरुद्ध अपील है. (ख) आवेदन की तिथि. (ग) लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब की तिथि.	
3	(क) प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता. (ख) प्रथम अपील जमा करने की तिथि. (ग) प्राप्त जवाब की तिथि.	
4	जिन आदेशों के विरुद्ध अपील की जानी है, उनका विवरण.	
5	अपील का संक्षिप्त विवरण.	
6	लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नामंजूर किए जाने की दशा में आवेदन की तिथि और विषय वस्तु का विवरण.	
7	आयोग से निवेदन या राहत.	लोक सूचना अधिकारी को मेरे आवेदन में मांगी गई सूचना बिना किसी शुल्क के तुरंत सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का आदेश दें. साथ ही लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कानून की धारा 20(1) के तहत जुर्माना लगाएं और धारा 20(2) के तहत लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश भी करें. आयोग से निवेदन है कि मैं इस मामले की सुनवाई में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहना चाहता हूं. अत: मुझे सुनवाई की अग्रिम सूचना अवश्य दें.
8	अन्य कोई सूचना, जो अपील निष्पादित करने के लिए आवश्यक हो.	

मैं.....उपरोक्त अपील को दिनांक .....को सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त मामले की सुनवाई किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण में नहीं की गई है अथवा विचाराधीन नहीं है. इस अपील में प्रदान की गईं सूचनाएं मेरी जानकारी में सही हैं.

संलग्नक सूची

1. आवेदन की प्रति. 2. शुल्क भुगतान की रसीद की प्रति. 3. आवेदन पत्र को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद की प्रति. 4. लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना की प्रति. 5. प्रथम अपील की प्रति. 6. प्रथम अपील को डाक द्वारा भेजे जाने की रसीद की प्रति. 7. प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना की प्रति. 8. द्वितीय अपील की प्रति को लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी को भेजे जाने का प्रमाण.

नाम---------
पता---------
स्थान---------
तिथि---------

नोट : द्वितीय अपील को डबल स्पेसिंग लाइन में बनाएं, यानी लाइनों के बीच दोगुनी जगह छोड़ें. द्वितीय अपील की एक-एक प्रति लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी को भेजें. द्वितीय अपील की दो प्रतियां सूचना आयोग में भेजें. साथ ही एक प्रति अपने पास रखें.

ज़रा हट के

बुज़ुर्गों के लिए शराब फ़ायदेमंद!

जो बुज़ुर्ग शराब का सेवन करते हैं, उनके लिए एक अच्छी ख़बर है. अगर वे नियमित रूप से सीमित मात्रा में शराब का सेवन करते हैं तो यह उनकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. ऐसा हम नहीं, वैज्ञानिक कह रहे हैं. उनका दावा है कि रात में भोजन के बाद एक या दो पैग शराब का सेवन करने से बुज़ुर्गों में दिल की बीमारी, मधुमेह एवं मानसिक विकृति के ख़तरों को कम किया जा सकता है. शोधकर्ताओं का कहना है कि एक या दो पैग लेने वाले बुज़ुर्गों की मृत्यु दर में 30 फ़ीसदी की कमी हो सकती है. रात का भोजन करने के बाद शराब पीने का आनंद लेना अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि शराब से भोजन जल्दी पच सकता है. ऐसे में इसका सेवन करने वाले ख़ुद को काफी हल्का महसूस करेंगे.

समाचारपत्र डेली मेल के मुताबिक, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस प्रभाव को जानने के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 25 हजार लोगों पर यह प्रयोग किया. अंतरराष्ट्रीय विज्ञान फोरम ऑन एल्कोहल रिसर्च से संबद्ध हेलेना कानिबियर ने कहा कि अधिकांश बुज़ुर्गों की मौत धमनियां बंद हो जाने से होती है. धमनियां बंद होने से रक्त का प्रवाह कम हो जाता है. इस वजह से मानसिक विकृति, दिल की बीमारी और कई तरह के दौरे पड़ने का ख़तरा बना रहता है. हेलेना कहती हैं, शराब रक्त को पतला बना देती है और धमनियों की सूजन को कम करके उन्हें खुला रखने में सहायता करती है. यह इंसुलिन बढ़ाने में भी मदद करती है, जिससे मधुमेह होने का ख़तरा कम हो जाता है.

विशालकाय तारों की खोज

वैज्ञानिकों ने कुछ विशालकाय सितारों की खोज की है. उक्त तारे इतने बड़े हैं, जिनकी कल्पना वैज्ञानिकों ने भी नहीं की थी. इनमें से एक तारा, जिसे सामान्य तौर पर आर-136(ए) के नाम से जाना जाता है, अब तक खोजे गए तारों में सबसे बड़ा है. इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 265 गुना अधिक है. ताज़ा अध्ययनों से पता चलता है कि जन्म के समय यह और बड़ा रहा होगा. ब्रिटेन के शेफ़ील्ड विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर पॉल क्राउथर कहते हैं कि शायद इसका वज़न हमारे सूर्य से 320 गुना अधिक था. उन्होंने कहा कि अगर इसे हमारे सूर्य के स्थान पर रख दिया जाए तो यह उसी तरह से चमकेगा, जिस तरह से पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना में हमारा सूर्य चमकता है.

इन तारों की पहचान प्रोफ़ेसर पॉल क्राउथर की टीम ने की. यह खोज चिली में लगाई गई एक बड़ी दूरबीन और अंतरिक्ष में लगाई गई हब्बल दूरबीन से भेजे गए आंकड़ों के विश्लेषण से की गई. वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एनजीसी-3603 और आरएमसी-136(ए) के नाम से मशहूर क्षेत्र का अध्ययन किया. एनजीसी-3603 पृथ्वी से 22 हज़ार प्रकाश वर्ष दूर है. वहीं आमतौर पर आर-136 के नाम से जाना जाने वाला आरएमसी-136(ए) तो और भी दूर है. इस दल ने पाया कि इन तारों की सतह का तापमान 40 हज़ार डिग्री से अधिक है, जो कि हमारे सूर्य के तापमान से सात गुना अधिक है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 9 अगस्त–15 अगस्त 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
आपका स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है. यात्रा के दौरान सफलता मिलेगी, लेकिन परिवार में किसी मामले को लेकर तकरार हो सकती है. बातचीत में संयम बरतना लाभकारी होगा. विवाद को टालने की कोशिश करें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
आर्थिक लाभ के योग हैं. कोई जमीन-जायदाद खरीदने की योजना बनाएंगे. किसी संबंधी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है. यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. सारी समस्याएं धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आंख, कान अथवा फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है. परिवार की खुशियां लौटने में अभी समय लगेगा. किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना पड़ सकता है. अपने काम के प्रति पूरी तरह सचेत रहें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
स्वास्थ्य को लेकर भारी ख़र्च हो सकता है. अगर आपने ध्यान न दिया तो समस्या बढ़ सकती है. इस सप्ताह दूर की यात्रा न करें तो बेहतर होगा. ज़्यादातर परेशानियां सप्ताह के अंत तक ख़त्म हो जाएंगी.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
कोई अच्छी घटना से आप व्यवसायिक जीवन में बेहद ख़ुश हो जाएंगे. वित्तीय प्रबंधन बेहतर तरीक़े से करना होगा. मज़बूत इच्छाशक्ति की बदौलत आप अपने मकसद में कामयाब होंगे. किसी परेशानी से निपटने में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
व्यवसायिक तौर पर आप अकेला महसूस करेंगे और अपनी परेशानियां किसी से शेयर नहीं करेंगे. आपको मेडिटेशन की जरूरत महसूस होगी. किसी करीबी का स्वास्थ्य भी आपकी चिंता का विषय बन सकता है, इसलिए इस ओर ध्यान अपेक्षित है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आर्थिक क्षेत्र के लिए किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से फायदा मिलेगा. कहीं घूमने जाने से ख़ुशी मिलेगी. अपने गृहनगर जाने से बचें, वरना तनाव हो सकता है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. यात्रा करने से बचें, क्योंकि इसमें काफी ख़र्च होने के साथ-साथ असुविधा भी हो सकती है. परिवार की ओर से ख़ुश करने वाली ख़बरें मिलेंगी. आय के नए रास्ते बनेंगे.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी. इस सिलसिले में की गई यात्रा फ़ायदेमंद साबित होगी. भावनात्मक समस्या से आर्थिक नुकसान हो सकता है, इस ओर विशेष ध्यान रखें. स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार होगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. पेट संबंधी शिक़ायत हो सकती है. काम के सिलसिले में किसी अधीनस्थ कर्मचारी से बातचीत करेंगे. परिवार से दूर रहने की वजह से कुछ समय के लिए परेशानी महसूस हो सकती है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
पुराने प्रोजेक्ट समय से पूरे हो जाएंगे, साथ ही नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. हालांकि खर्च काफी होगा. स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है. परिवार की ओर से मदद मिलेगी. यह सप्ताह नई ख़ुशियां लेकर आएगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिवार के सहयोग से आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी. परिवार में किसी नए सदस्य के आने की उम्मीद है. आप क़रीबी लोगों के साथ घूमने जाने की भी योजना बना सकते हैं. आय के क्षेत्र में वृद्धि होगी.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

अमेरिका के प्रति पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही नफ़रत की इस भावना को समझने की ज़रूरत है. पाकिस्तान की अंदरूनी हालत ठीक नहीं है. स्वात और वजीरिस्तान क्षेत्रों में सरकार नाम की कोई चीज नज़र नहीं आती.

पीईडब्ल्यू ग्लोबल एटीट्यूड्स सर्वे रिपोर्ट

अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है

आदित्य पूजन

अमेरिका चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन आम पाकिस्तानी नागरिक उसे अपना दुश्मन ही मानता है. देश में हर दस में से छह नागरिक अमेरिका को दुश्मन की नज़र से देखते हैं. विश्व की एकमात्र महाशक्ति वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान को अपना सबसे अहम सहयोगी भले ही मानता हो, लेकिन अधिकांश पाकिस्तानी इस युद्ध के ही ख़िलाफ़ हैं. उन्हें यह लगता है कि अमेरिका आतंकी संगठनों के ख़िलाफ़ इस कार्रवाई के ज़रिए अपने निजी स्वार्थों को साधने में लगा है और इसके लिए पाकिस्तान का बेजा इस्तेमाल कर रहा है.

यह बात पहले भी कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन पीईडब्ल्यू ग्लोबल एटीट्यूड्स सर्वे की नई रिपोर्ट वास्तव में चौंकाने वाली है. इसकी वजह यह है कि अमेरिका लंबे समय से पाकिस्तान में अपनी खराब छवि को सुधारने की कोशिश में लगा है. पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के प्रति पाकिस्तानी अवाम की नफ़रत को देखते हुए नए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसके लिए तमाम हथकंडे अपनाए. राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के ठीक बाद उन्होंने मिस्र के कैरो से इस्लामिक जगत के नाम अपना संदेश जारी किया. इसके अलावा पाकिस्तान को तमाम तरह की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है. पिछले दिनों पाकिस्तान दौरे पर आईं अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने अगले पांच सालों के लिए 1.5 बिलियन डॉलर सालाना की आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की घोषणा की, लेकिन इसका कुछ ख़ास असर पड़ता दिख नहीं रहा है. शुरुआत में ओबामा से बनी उम्मीदें भी अब निराशा में तब्दील होती जा रही हैं. केवल आठ प्रतिशत पाकिस्तानियों का ही यह मानना है कि ओबामा वैश्विक मामलों में कुछ अच्छा कर सकते हैं. उनकी यही राय है कि अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह ओबामा का हर क़दम भी अमेरिकी हितों की पूर्ति के लिए होता है और यह ज़रूरी नहीं कि यह पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद हो. हैरत की बात तो यह है कि 22 देशों के बीच कराए गए इस सर्वे में अमेरिका और ओबामा का स्थान सबसे नीचे है. अफ़ग़ानिस्तान में लगातार बढ़ती मौतों ने आम पाकिस्तानी नागरिक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अमेरिका आख़िर करना क्या चाहता है. पाकिस्तान के सामरिक हित अफ़ग़ानिस्तान से जुड़े हैं और वहां हो रही हर मौत पाकिस्तान में हलचल पैदा करती है, जबकि अमेरिका लगातार वहां अपनी फौज बढ़ा रहा है. यही वजह है कि दो–तिहाई से भी ज़्यादा पाक जनता इस युद्ध के समर्थन में नहीं है. उसका मानना है कि जितनी जल्दी हो सके, अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सेना को वापस लौट जाना चाहिए. पाकिस्तानी जनता अमेरिका को इसलिए भी संदेह की नज़र से देखती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह भारत को ज़्यादा तवज्जो देता है. गौर करने लायक बात यह है कि अमेरिका विरोध की यह भावना राजनीतिक आधार पर बंटी हुई है. देश के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग–एन (पीएमएल–एन) के समर्थकों में 72 प्रतिशत अमेरिका को मुल्क का दुश्मन मानते हैं, जबकि दूसरी प्रमुख पार्टी सत्ताधारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के समर्थकों में केवल 46 प्रतिशत की ही यह राय है. इतना ही नहीं, विरोध की यह भावना क्षेत्रीय आधार पर भी अलग–अलग है. देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पंजाब की 69 प्रतिशत आबादी अमेरिका को अपना दुश्मन मानती है, जबकि सिंध में यह आंकड़ा केवल 40 प्रतिशत है.

अमेरिका के प्रति पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही नफ़रत की इस भावना को समझने की ज़रूरत है. पाकिस्तान की अंदरूनी हालत ठीक नहीं है. स्वात और वजीरिस्तान क्षेत्रों में सरकार नाम की कोई चीज नज़र नहीं आती. देश के अन्य हिस्सों में भी क़ानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है. आतंकी संगठन जहां चाहे, वहां बम विस्फोट कर रहे हैं, कट्टरवादी ताक़तें समाज को तोड़ने में लगी हैं, चारों ओर ग़रीबी और बेरोज़गारी का आलम है, आम लोग मर रहे हैं और मुल्क का राजनीतिक नेतृत्व इन बातों से बेख़बर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा है. उसे देश से ज़्यादा ख़ुद अपने हितों की चिंता है. प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बीच जारी सत्ता का संघर्ष फौज को खुला आमंत्रण देने जैसा है. नवंबर में रिटायर हो रहे सेना प्रमुख जनरल अशफाक कयानी को तीन साल का सेवा विस्तार दिया जाता है तो इसकी वजह और कुछ नहीं, बल्कि अमेरिकी दबाव है. सच तो यह है कि मुल्क का राजनीतिक नेतृत्व आज अमेरिका का पिछलग्गू बनकर रह गया है. सारे फ़ैसले अमेरिकी रजामंदी से सेना द्वारा लिए जा रहे हैं. आम पाकिस्तानी इसे मुल्क के अंदरूनी मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप की दृष्टि से देखता है.

इसके अलावा 9/11 के बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों के प्रति बदले रवैये ने भी आम नागरिकों में अमेरिका के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया है. उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है. हर मुसलमान को जैसे आतंकवादी मानने की होड़ चल पड़ी है. देश के अंदर हो या बाहर, हर पाकिस्तानी ख़ौफ़ में जीने को मजबूर है और इस सबके पीछे वह अमेरिका को दोषी मानता है. अमेरिका के लिए राहत की बात केवल इतनी है कि इसके बावजूद मुल्क की अधिसंख्यक जनता उसके साथ अच्छे संबंधों की पक्षधर है. अब इसकी वजह चाहे अमेरिका का वैश्विक महाशक्ति होना हो या वित्तीय सहायता का लालच, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक़, 64 प्रतिशत जनता अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते चाहती है. चाहे जो भी हो, यह तो स्पष्ट है कि अमेरिका को पाकिस्तान के प्रति अपनी नीतियों पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है. अफ़ग़ानिस्तान में जारी संघर्ष के मद्देनजर भी यह ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इसे आम पाकिस्तानी जनता का समर्थन हासिल नहीं होगा, अमेरिका अपनी जीत की कल्पना भी नहीं कर सकता. उसे अपने ख़िलाफ़ बढ़ रही नफ़रत की इस भावना को कम करने के लिए कारगर क़दम उठाने ही होंगे. यदि ऐसा नहीं हुआ तो न केवल दोनों देशों के रिश्ते प्रभावित होंगे, बल्कि विश्व शांति पर भी बुरा असर पड़ेगा.

aditya@chauthiduniya.com

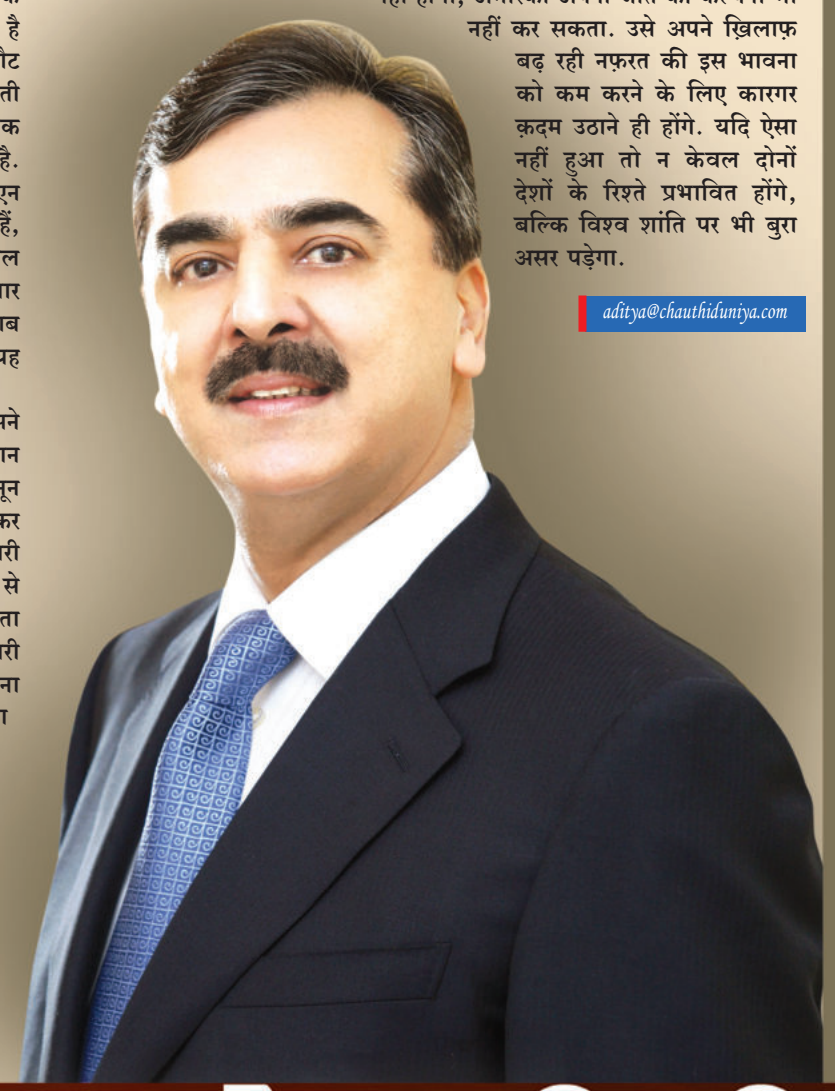

देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 12,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 40,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम–भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार–राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

www.chauthiduniya.tv

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

नीमगांव में बाबा बालासाहेब डेंगले के घर जाया करते थे. बाबा बालासाहेब को बहुत प्यार करते थे. उनके छोटे भाई नानासाहेब की दूसरी शादी के बावजूद उन्हें कोई संतान न थी.

शिरडी साई भक्तों का महातीर्थ है

कुमार सुशांत

यूं तो साई बाबा को शरीर त्यागे सालों बीत चुके हैं, लेकिन वह आज भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं. शिरडी के साई बाबा अनगिनत लोगों के आराध्य बन चुके हैं. उसकी एक ख़ास वजह है कि हम चाहे जितनी भी समस्याएं, शंकाएं या कष्ट लेकर शिरडी में बाबा के चरणों में अपना सिर झुकाएं, बाबा उन सबका एक पल में निवारण करते हैं. शिरडी के साई बाबा चमत्कारी इसलिए माने जाते हैं, क्योंकि उनकी दिव्य शक्ति के प्रताप से ही शिरडी का निर्माण हुआ. परिणामस्वरूप, साई भक्तों के लिए शिरडी आज महातीर्थ बन गया है. ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1854 में साई बाबा जब पहली बार शिरडी आए, तब वह केवल 16 वर्ष के थे. स्वस्थ, तेजस्वी, अति सुंदर रूप लिए वह बालक हमेशा नीम के पेड़ के नीचे प्रार्थना में लीन रहता था. आसपास के लोग उस असाधारण साधक को देखकर आश्चर्य में थे, क्योंकि वह न तो किसी से बात करता था, न किसी के घर जाता था, न उसे मौसम के बदलाव की फ़िक्र थी और न किसी का भय था. बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज देखकर सभी आकर्षित हो जाते थे. एक दिन अचानक लोगों ने सुबह उठकर देखा तो वह बालक वहां नहीं था. सभी लोग मन ही मन उसे ईश्वर का अवतार मानने लगे. उस असाधारण बालक को ख़ूब ढूंढा गया, लेकिन वह नहीं मिला. कई सालों बाद वह योगी साधक फिर शिरडी पहुंचता है. बालक बड़ा तो हो गया था, लेकिन उसे देखते ही लोगों ने तुरंत पहचान लिया. वह असाधारण प्रतीत होने वाला योगी एक फ़कीर की वेशभूषा में था. खंडोबा के मंदिर के पास आते ही पुजारी महालसापति ने उस फ़कीर का जब आओ साई कहकर स्वागत किया, तबसे वह साई बाबा के नाम से मशहूर हो गए. उसके बाद साई बाबा हमेशा के लिए शिरडी में ही बस गए. हर दिन बाबा भिक्षा मांगने निकलते थे और बड़ी सादगी के साथ रहते थे. बाबा के पास लोग अपने कष्ट लेकर आते थे, शंकाएं लेकर आते थे और कोमल हृदय बाबा दिन भर सबका समाधान करते नज़र आते थे. धीरे–धीरे बाबा के भक्त बढ़ने लगे. सबका विश्वास अटूट होता चला गया. कई भक्तों का कहना था कि बाबा में उन्हें सभी देवी–देवताओं के रूप नज़र आते हैं. बाबा ने हमेशा कहा कि सबका मालिक एक है, लड़ना–झगड़ना छोड़ो, मिलकर चलो, असीम सुख पाओगे. बाबा अक्सर कहते थे, किसी से ईर्ष्या मत करो, अगर कोई तुमसे जले तो उससे हंसकर मिलो. ऐसा करने से तुम बुराई पर अच्छाई की पताका फहरा सकते हो.

साई बाबा एक हिंदू द्वारा बनवाई गई मस्ज़िद में रहते थे, जिसे वह द्वारकामाई कहते थे. एक दिन साई बाबा ने अपनी अनन्य भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 सिक्के देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि मुझे मस्ज़िद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे बूटी साहब के पत्थर भवन में ले चलो. विक्रम संवत 1975 की विजयादशमी के दिन साई बाबा ने महासमाधि ली. महासमाधि के बाद वह पत्थर भवन बाबा का समाधि स्थल बन गया. साई बाबा पहले से कहते थे कि उनका शरीर जब इस धरती पर नहीं रहेगा, तब उनकी समाधि भक्तों को संरक्षण प्रदान करेगी. बाबा के उसी वचन का प्रमाण है कि आज भी उनके समाधि स्थल से कोई भक्त निराश होकर नहीं लौटता.

kumarsushant@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ ख़ाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

ग़रीबी अव्वल बादशाही...

कभी–कभी वह गांव की एक मेड़ पर नाले के किनारे बबूल के पेड़ की छाया तले बैठे रहते थे और संध्या के समय अपनी इच्छानुसार कहीं भी वायु सेवन के लिए निकल जाते थे. नीमगांव में बाबा बालासाहेब डेंगले के घर जाया करते थे. बाबा बालासाहेब को बहुत प्यार करते थे.

शिरडी में एक पहलवान था, जिसका नाम मोहिद्दीन तंबोली था. बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया. फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए. इसके बाद बाबा ने अपनी पोशाक और रहन–सहन में परिवर्तन कर लिया. वह कफ़नी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढंकते थे. वह आसन और शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे. इस प्रकार फटे–पुराने चिथड़े पहन कर बाबा काफी संतुष्ट प्रतीत होते थे. वह सदैव यही कहा करते थे कि ग़रीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, ग़रीबों का अल्ला भाई. गंगागीर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था. एक बार जब वह कुश्ती लड़ रहा था, तब इसी प्रकार उसमें भी त्याग की भावना जागृत हो गई. इसी अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी कि भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए. इस कारण वह संसार छोड़ आत्म–अनुभूति की ओर झुक गया और पुणतांबे के समीप एक मठ स्थापित कर अपने शिष्यों सहित वहां रहने लगा.

साई बाबा लोगों से न मिलते और न वार्तालाप करते थे. जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वह केवल उतना ही उत्तर देते थे. दिन के समय वह नीम के वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे. कभी–कभी वह गांव की एक मेड़ पर नाले के किनारे बबूल के पेड़ की छाया तले बैठे रहते थे और संध्या के समय अपनी इच्छानुसार कहीं भी वायु सेवन के लिए निकल जाते थे. नीमगांव में बाबा बालासाहेब डेंगले के घर जाया करते थे. बाबा बालासाहेब को बहुत प्यार करते थे. उनके छोटे भाई नानासाहेब की दूसरी शादी के बावजूद उन्हें कोई संतान न थी. बालासाहेब ने नानासाहेब को साई बाबा के दर्शन के लिए शिरडी भेजा. कुछ समय बाद उनकी कृपा से नानासाहेब के यहां एक पुत्र पैदा हुआ. इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया और उनकी कीर्ति दूर–दूर तक फैलने लगी. अहमदनगर में भी वह प्रसिद्ध हो गए. तभी से नानासाहेब चांदोरकर, केशव चिदंबर एवं अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा. बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण–शीर्ण मस्ज़िद में शयन करते थे. इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफ़नी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था, जिसे वह सदा अपने पास रखते थे. सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वह इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान से पीठ पर गिरता हुआ प्रतीत होता था, मानो बालों का जूड़ा हो. हफ्तों तक वह इन्हें साफ नहीं करते थे. पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे. पूरे दिन केवल एक टाट का टुकड़ा ही उनके आसन का काम करता था. बाबा एक कौपीन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख हो धूनी से तापते थे. वह धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे और अपना अहंकार, इच्छाओं एवं कुविचारों की उसमें आहुति दिया करते थे. वह सदा अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे. जिस मस्ज़िद में वह पधारे थे, उसमें केवल दो कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यहीं सारे भक्त उनके दर्शन करते थे. 1912 के बाद कुछ परिवर्तन हुआ. पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया. साई बाबा पैरों में घुंघरू बांध कर सुंदर नृत्य एवं गायन भी करते थे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

जोशीमठ में जहां भगवान नरसिंह का मंदिर है, वहीं जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने कठिन तपस्या की थी. उनके द्वारा स्थापित मठ आज भी श्रद्धालुओं की आस्था प्रतीक का बना हुआ है.

नागपाश में स्त्री

अनंत विजय

हमारे देश के पुरुष प्रधान समाज में कई लोग ऐसे हैं, जो महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं. परिवार की देखभाल और अपने पति की हर तरह की ज़रूरतों पर जान न्यौछावर करने की घुट्टी उन्हें जन्म से पिलाई जाती है. उस आदिकालीन व्यवस्था में महिलाएं गुलाम हैं, जिनका परम कर्तव्य है अपने स्वामी की सेवा और स्वामी है पुरुष. इस पाषाणकालीन व्यवस्था में यक़ीन रखने वाले पुरुषों को यह कतई मंजूर नहीं है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें. महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक़ और दर्ज़ा मिले. महिलाएं देश की नीति नियंता बनें. महिलाओं का विरोध किसी सिद्धांत, धर्म, आस्था, विश्वास या वाद की परिधि से परे है. जब भी महिलाओं की बेहतरी की बात होती है तो सभी सिद्धांत, वाद, समुदाय एवं धर्म धरे रह जाते हैं. प्रबल हो जाती है कठोर पुरातनपंथी विचारधारा, जो महिलाओं को सदियों से दबा कर रख रही है और आगे भी चाहती है कि वे उसी तरह दासता और पिछड़ेपन की बेड़ियों में जकड़ी रहें. लेकिन अब स्थितियां बदलने लगी हैं और पितृसत्तात्मक समाज के वर्चस्व के विरोध में स्त्रियां उठ खड़ी होने लगी हैं. राजेंद्र यादव ने स्त्री विमर्श की जो आग सुलगाई थी, अब वह लगभग दावानल बनती जा रही है. महिला लेखिकाओं ने पुरुष की सत्ता को चुनौती देनी शुरू कर दी है.

इन्हीं चुनौतियों के बीच रामनाथ गोयनका अवॉर्ड से नवाज़ी गई पत्रकार गीताश्री की किताब नागपाश में स्त्री का प्रकाशन हुआ है. गीताश्री ने इस किताब का संपादन किया है, जिसमें पत्रकारिता, थिएटर, साहित्य एवं कला जगत से जुड़ी महिलाओं ने पुरुषों की मानसिकता और स्त्रियों को लेकर उनके विचारों को अपनी कसौटी पर कसा है. गीताश्री की छवि भी स्त्रियों के पक्ष में मज़बूती से खड़े होने की रही है और पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने अपने लेखन से स्त्री विमर्श को एक नया आयाम दिया है. अपनी इस किताब की भूमिका में लेखिका ने लिखा, आज बाज़ार के दबाव और सूचना–संचार माध्यमों के फैलाव ने राजनीति, समाज और परिवार का चरित्र पूरी तरह से बदल डाला है, मगर पितृसत्ता का पूर्वाग्रह और स्त्री को देखने का उसका नज़रिया नहीं बदला है, जो एक तरफ स्त्री की देह को ललचाई नज़रों से घूरता है तो दूसरी तरफ़ उससे कठोर यौन शुचिता की अपेक्षा भी रखता है. पितृसत्ता का चरित्र भी वही है. हां, समाज में बड़े पैमाने पर सक्रिय और आत्मनिर्भर होती स्त्री की स्वतंत्र चेतना पर अंकुश लगाने के उसके हथकंडे ज़रूर बदले हैं.

गीताश्री ने अपने इस कथन के समर्थन में कई उदाहरण दिए हैं. यह हमारे समाज की एक कड़वी हक़ीक़त है कि पुरुष चाहे जितनी स्त्रियों के साथ संबंध बनाए, उसकी इज़्ज़त पर बट्टा नहीं लगता है, बल्कि वह फख्र से सीना चौड़ा कर इसे एक उपलब्धि की तरह से पेश करता है. लेकिन वहीं अगर स्त्री ने अपनी मर्जी से अपने पति के अलावा किसी और मर्द के साथ संबंध बना लिया तो उसका चरित्र, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी शिक्षा–दीक्षा सभी सवालों के घेरे में आ जाते हैं. लेकिन अब हालात तेज़ी से बदलने लगे हैं, स्त्रियां भी अपने मन की करने लगी हैं. इसी किताब के अपने एक लेख में उपन्यासकार मैत्रेयी पुष्पा ने कहा है कि औरत करती वही है, जो उसका दिल करता है, दिखावा चाहे वह जो करे. समाज के लिए स्त्री के प्रेम संबंध अनैतिक हो सकते हैं, मगर स्त्री के लिए नैतिकता की पराकाष्ठा है.

मैत्रेयी पुष्पा ने माना है कि आवारा लड़कियां ही प्यार कर सकती हैं. अपने लेख में मैत्रेयी पुष्पा ने इस बात का ख़ुलासा नहीं किया कि वह किस प्यार की बात करती हैं, दैहिक या लौकिक? क्योंकि उन्होंने लिखा है कि मेरे पांच–सात प्रेमी रहे, जो उम्र के अलग–अलग पड़ाव पर मुझे मिले. लेकिन लेख में नायब साहब और एदल्लला के साथ तो प्यार जैसी कोई चीज थी, देह तो बीच में कभी आई ही नहीं. इस किताब में बुज़ुर्ग लेखिका रमणिका गुप्ता का भी एक बेहद लंबा और उबाऊ लेख है. रमणिका गुप्ता ने बेवजह अपने लेख को लंबा किया है. अपने इस लंबे और उबाऊ लेख के अंत में उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की बदतर हालत के लिए धर्म और सामाजिक परंपरा को ज़िम्मेदार ठहराया है. अपने इस तर्क के समर्थन में उन्होंने दो उदाहरण भी दिए हैं. पहला उड़ीसा और दूसरा मध्य प्रदेश का है, जहां अट्ठारह–बीस साल की लड़कियों का विवाह बालकों से कर दिया जाता है. परंपरा की आड़ में तर्क यह दिया जाता है कि खेतों और घर का काम करने के लिए जवान लड़की चाहिए. लेकिन इस तरह के विवाह में योग्यता ससुर की परखी जाती है. पति के जवान होने तक बहू ससुर के साथ देह संबंध बनाने के लिए अभिशप्त होती है. मनुस्मृति में भी कहा गया है पति की पूजा विश्वसनीय पत्नी द्वारा भगवान की तरह होनी चाहिए. यदि वह अपनी सेवाएं देने में किसी तरह की भी कोई कोताही बरते तो उसे राजा से कहकर कुत्तों के सामने फेंकवा देना चाहिए. अपने इसी लेख में रमणिका गुप्ता ने यह भी कहा है कि दलित स्त्रियां सवर्ण स्त्रियों की तुलना में ज़्यादा स्वतंत्र होती हैं. इस बात को साबित करने के लिए भी रमणिका के अपने तर्क हैं.

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इस किताब में साहित्य के अलावा अन्य क्षेत्र की महिलाओं के भी लेख हैं. आमतौर पर सारे लेख व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिखे गए हैं. मशहूर गायिका विजय भारती का भी एक दिलचस्प लेख इस किताब में संग्रहीत है. विजय भारती ने अपने लेख में यह साबित करने की कोशिश की है कि समाज और परिवार में किस तरह से बचपन से ही लड़कियों को यौन शुचिता की घुट्टी पिलाई जाती है. जब बचपन में लड़कियां खेलने जाती हैं तो उनसे यह कहा जाता है कि सुन लो पहले ही, लड़कों के साथ मत खेलना, क्योंकि लड़कों के साथ खेलने से उनकी शुचिता नष्ट हो जाएगी. बचपन की बात क्यों, जवान लड़कियां भी जब घर से बाहर निकलती हैं तो परिवार के लोग उनके साथ छह–सात साल के उनके भाई को लगा देते हैं, जो उनकी रक्षा करेगा.

इनके अलावा फायर ब्रांड और अपनी लेखनी को एके–47 की तरह इस्तेमाल करने वाली पत्रकार मनीषा ने अपनी खास शैली में अपनी बात कही है. मनीषा लिखती हैं कि भारत में चालीस साल के ऊपर के लगभग नौ करोड़ आदमी स्वीकृत रूप से नपुंसक हैं, ज़ाहिर तौर पर उनकी सेक्स क्षमता जाती रही हो, पर सामाजिक–पारिवारिक दबावों में उनकी पत्नियां चूं तक नहीं कर पाती और अगर स्त्री बच्चा नहीं जन सकती तो भी उसकी शारीरिक संरचना पुरुष को भरपूर यौनानंद देने के काबिल तो रहती ही है. मनीषा की जो शैली है, वह बेहद तीखी और खरी–खरी कहने की है. वह लिखती हैं कि लड़की बिन ब्याह के अगर किसी लड़के का लिंग छू ले तो वह भ्रष्ट हो जाएगी, पर आप अपनी कोहनियां उसके स्तनों में खोंसते फिरें तो यह धार्मिकता मानी जाएगी. इसके अलावा जयंती, निर्मला भुराड़िया एवं असीमा भट्ट के भी पुरुष सत्ता के ख़िलाफ़ आग उगलते लेख इस किताब में हैं.

कुल मिलाकर अगर हम स्त्री विमर्श के प्रथम पुरुष राजेंद्र यादव को समर्पित इस किताब पर समग्रता से विचार करें तो यह लगता है कि राजेंद्र यादव की पीढ़ी ने जिस विमर्श की शुरुआत की थी, वह अब विरोध से आगे बढ़कर विद्रोह की स्थिति में जा पहुंचा है. इस लिहाज़ से गीताश्री की यह किताब अहम है कि युवा लेखिकाओं के विचार बेहद उग्र और आक्रामक हैं. जो बात स्त्री विमर्श का झंडा बुलंद करने वाली लेखिकाएं खुलकर नहीं कह पा रही थीं, वह बात अब युवा लेखिकाओं के लेख में सामने आने लगी है. इन युवा लेखिकाओं के तेवरों से यह लगता है कि स्त्री विमर्श ने एक नए मुकाम के साथ नई शब्दावली भी तैयार कर ली है. लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि क्या सदियों पुरानी परंपराओं और मानसिकता को बदलना इतना आसान है? जवाब है नहीं. लेकिन इस वजह से प्रयास तो छोड़ नहीं सकते और उसी का नतीजा है नागपाश में स्त्री...

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश

मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

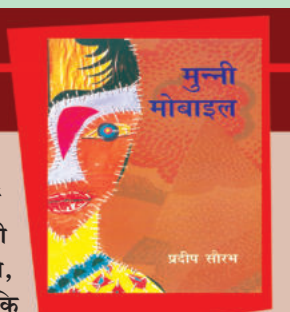

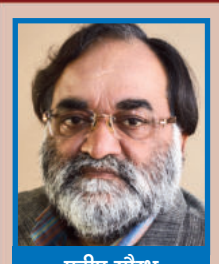

प्रदीप सौरभ

आनंद भारती उस पल को ऐसे याद करने लगे, जैसे वह समय ठीक अभी–अभी उनके क़रीब से गुजरा हो. हमेशा कुछ न कुछ बोलने वाली मानसी अचानक ख़ामोश हो गई थी. आनंद उससे मज़ाक कर रहे थे कि उसे बुरा क्यों लगा. तुम्हें प्रेम हो गया है क्या मुझसे? आनंद भारती ने उससे हंसकर पूछा था. मानसी ने बड़े तटस्थ होकर उत्तर दिया, हां. आनंद भारती का सधा सा प्रत्युत्तर था, लेकिन मैंने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया मानसी, वैसा तो कदापि नहीं, जो हमें घर–गृहस्थी में बांधे. बस, मानसी चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से चली गई थी.

आनंद पूरी रात वैचारिक झंझावात से जूझते रहे थे. वह कभी मानसी को सच नहीं बता पाए. ऐसा सच, जो विद्रोही आनंद का स्वभाव नहीं था, फिर भी हमेशा विरोधों का डटकर सामना करने वाले आनंद भारती ने उसे स्वीकार कर लिया था. आनंद मानसी के घर अक्सर आया–जाया करते थे. मानसी का परिवार उन्हें बहुत स्नेह करता था, पर सिर्फ़ मानसी के मित्र रूप में. इसके आगे जातीय कटिबद्धता उस परिवार की सच्चाई थी. आनंद भारती इस तथ्य से पूरी तरह वाक़िफ़ थे कि यह साहचर्य कभी किसी सामाजिक रिश्ते की बुनियाद नहीं बन सकता.

आनंद भारती मानसी के परिवार की इज़्ज़त करते थे. इसलिए उन्होंने मानसी से जो कहा, उसमें क्या और कितनी सच्चाई थी, उस वक़्त उसे सिर्फ़ आनंद भारती उस समय की परिस्थितियों पर ही छोड़ सकते थे. सच्चाई यह भी थी कि स्वयं आनंद भारती अपने और मानसी के रिश्ते को समझ नहीं पा रहे थे. रिश्तों में पराजित होने के भय से उन्होंने

संभवत: मानसी के कहीं और विवाह हो जाने से पूर्व अपना विवाह तय कर लिया था. अंतर्विरोधी स्वभाव और द्वंद्वात्मक व्यवहार में जीना, आनंद भारती के हाथ की रेखाओं का सच यही था.

सोचने वाले सोच सकते हैं कि संभवत: उसके बाद मानसी आनंद भारती से कभी नहीं मिली होगी और यह रिश्ता एक आम कहानी की तरह खत्म हो गया होगा...कुछ अधूरा सा...पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. मानसी चुपचाप घर गई थी...हो सकता है...पूरी रात ख़ामोश आंसुओं में गुजार दी हो, पर दूसरे दिन वह पुन: आनंद भारती के घर गई थी. तब, जब आनंद भारती घर पर नहीं थे, क्योंकि वह उनके मां–पिता से वायदा कर गई थी कि शादी के काम में वह उनका पूरा हाथ बंटाएगी. मां–पिता से बेटी की तरह स्नेह पाने वाली मानसी ने कार्ड छपने पर हर कार्ड पर अपने हाथों से अतिथियों–मित्रों के नाम लिखे थे...टिकट चिपकाए थे...छोटे–बड़े काम किए थे.

मानसी सब कुछ करती, पर आनंद भारती से सहज नहीं हो पाई थी. शायद आनंद भारती भी सहजता महसूस नहीं कर पा रहे थे. पर कुछ रिश्ते बनते अपनी मर्जी से हैं और टूटते अपनी मर्जी से. आनंद भारती का यह रिश्ता टूट नहीं पाया था... विवाह के बाद आनंद आए तो मानसी शिवानी से मिलने आई थी. मानसी की मां ने शगुन दिया था और मानसी शगुन में क्या देती भला! बस, आनंद और शिवानी को देने के लिए उसके पास ढेरों दुआएं थीं और उसने दिया भी यही.

बड़े दिल वाली मानसी विवाह की रात बहुत–बहुत रोई थी...उसकी सूजी आंखें आनंद भारती ने महसूस की थीं और उसी पल उन्होंने सोच लिया था कि वह अपनी इस बेहद प्रिय मित्र की मित्रता को कभी नहीं छोड़ सकते. एक ऐसी मित्रता, जो अपने आप में मिसाल होगी. मानसी और आनंद भारती का रिश्ता समाज के दायरे में बंधकर भी समाज से अलग होगा.

अगले अंक में जारी...

भगवान नरसिंह का शांत और लोक कल्याणकारी रूप

राजकुमार शर्मा

देवभूमि हिमालय के पावन जोशीमठ में भगवान नरसिंह की एक ऐसी दिव्य मूर्ति है, जो कला, धार्मिक विश्वास और मान्यताओं का बेजोड़ नमूना है. शालिग्राम पत्थर से बनी यह मूर्ति जगतगुरु आदि शंकराचार्य द्वारा पूजित उनकी तपोस्थली ज्योर्तिमठ (जोशीमठ) में नारायण धाम के रूप में विख्यात है. भगवान बद्रीनाथ के पावन बद्रिकाश्रम के मार्ग में स्थित ज्योर्तिमठ शहर अब जोशीमठ के नाम से जाना जाता है. यह एक धार्मिक–पौराणिक नगर के रूप में विख्यात है. प्राकृतिक वैभव से संपन्न यह नगर मंदिरों एवं मठों के कारण अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. देशी–विदेशी पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करने वाला औली इसी से लगा हुआ है, जो एशिया के सबसे बड़े रोप वे (रज्जू मार्ग) से जुड़ने के कारण पर्यटकों की पहली पसंद माना जाता है. आज से ढाई हज़ार वर्ष पूर्व दक्षिण भारत से जब जगतगुरु आदि शंकराचार्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिमालय आए तो उन्होंने सर्वप्रथम यहीं अपना डेरा डाला और कठिन तपस्या की. तपस्या के दौरान उन्हें इसी प्रतिमा के माध्यम से ज्ञान ज्योति के दर्शन हुए, तभी से यह स्थान ज्योर्तिमठ के रूप में विख्यात हो गया. कालांतर में लोग इसे जोशीमठ के नाम से बुलाने और जानने लगे. अब यह नगर जोशीमठ के रूप में विख्यात है. प्राकृतिक वैभव के कारण प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू इस स्थान को मिनी कश्मीर के अलावा गुलाबों का शहर नाम से भी पुकारते थे.

मान्यता है कि जगतगुरु आदि शंकराचार्य जिस दिव्य शालिग्राम पत्थर में नारायण की पूजा करते थे, उसमें यकायक भगवान नरसिंह की मूर्ति उभर आई और उसी क्षण उन्हें नारायण के दर्शन के साथ अद्भुत ज्ञान ज्योति प्राप्त हुई. भगवान नारायण ने उन्हें नरसिंह अवतार के रौद्र रूप की जगह शांत रूप के दर्शन दिए, तभी से लोक मंगलकारी नारायण की यह शांत रूप मूर्ति जनास्था के रूप में विख्यात है. भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाने के बाद उनकी मूर्ति को जोशीमठ लाकर इसी पावन मंदिर में छह माह यानी हिमकाल तक उनकी पूजा की जाती है. नरसिंह मंदिर में वैसे तो वर्षपर्यंत श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, किंतु हिमकाल में भगवान बद्रीनाथ का वास भी इसी परिसर में हो जाने के कारण इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है. भगवान शालिग्राम की मूर्ति का चित्र लेना अथवा किसी भक्त द्वारा उनका स्पर्श पूरी तरह वर्जित है. कहा जाता है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ धीरे–धीरे पतला होता जा रहा है. ऐसी मान्यता है कि जिस दिन मूर्ति से हाथ का वह हिस्सा अलग हो जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित जय–विजय पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उसी क्षण बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा. भविष्य में भगवान बद्रीनाथ जोशीमठ से 22 किलोमीटर आगे भविष्य बद्री के रूप में प्रकट होकर दर्शन देंगे.

वर्तमान में भगवान नरसिंह के हाथ का वह हिस्सा सुई की गोलाई के बराबर रह गया है. बताया जाता है कि मान्यता के अनुरूप ही भविष्य बद्री में स्थित एक शिलाखंड पर आश्चर्यजनक रूप से भगवान विष्णु की मूर्ति आकार भी ले रही है.

जोशीमठ में जहां भगवान नरसिंह का मंदिर है, वहीं जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने कठिन तपस्या की थी. उनके द्वारा स्थापित मठ आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक बना हुआ है. भगवान बद्रीनाथ के रावल जब बद्रीनाथ धाम से वापस आते हैं तो स्वयं को पहनाई गई पगड़ी यहीं पहुंच कर उतारते हैं. बताते हैं कि जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ के प्रथम रावल का छोर (मुंडन) यहीं कराया था और यहीं से उन्हें धर्म रूपी पगड़ी पहना कर भगवान के पूजन–सेवा के लिए बद्रीनाथ धाम रवाना किया था. ढाई हज़ार वर्ष व्यतीत होने के बाद आज भी उनके द्वारा शुरू की गई परंपरा का अक्षरश: पालन किया जा रहा है. मंदिर के पुजारी पंडित लक्ष्मी प्रसाद डिमरी बताते हैं कि जब कभी इस हिमालयी क्षेत्र में अकाल और सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तो लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री की प्रतिमा को गर्म जल से स्नान कराया जाता है. इस स्नान के बाद भगवान श्री की मूर्ति में फफोले निकल आते हैं. इसके बाद वर्षा हो जाती है. पुजारी डिमरी सहित अनेक लोगों की ज़ुबानी ऐसे कई किस्से सुने जाते हैं. डिमरी जी कहते हैं कि भगवान नरसिंह का स्वरूप पूरी तरह से शांत रूप के साथ लोक कल्याणकारी है. यहां पूजन से सभी मनोरथ पूरे होने के साथ–साथ मानव को सिद्धि भी प्राप्त होती है.

शास्त्रों में भगवान नरसिंह के रौद्र रूप की ही जानकारी मिलती है, किंतु हिमालय की कोख में बसे जोशीमठ में भगवान नरसिंह के शांत और लोक कल्याणकारी रूप के दर्शन होते हैं. मंदिर समिति के नियमों के अनुसार, इस मूर्ति का चित्र खींचना अथवा इसका चित्रांकन पूरी तरह वर्जित है, किंतु अपने पत्रकार मन की प्रेरणा से यह चित्र मैंने बनाया, जिसे लोकमंगल की कामना के साथ प्रकाशित किया जा रहा है. मंशा मात्र इतनी है कि जनमानस भगवान नरसिंह के सौम्य रूप से परचित हो सके. जोशीमठ में एक अति प्राचीन कल्पवृक्ष के समीप जगतगुरु आदि शंकराचार्य की तपस्थली भी स्थित है. इसी वृक्ष के नीचे उन्होंने कठोर तप किया था. इस कल्पवृक्ष के बारे में बताया जाता है कि यह एक शहतूत का वृक्ष है, जगतगुरु आदि शंकराचार्य के तप के प्रभाव के कारण इसे भी दीर्घ जीवन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है. इस वृक्ष के नीचे भगवान ज्योतिश्वर महादेव विराजमान हैं, जिनके मंदिर के एक भाग में जगतगुरु आदि शंकराचार्य द्वारा लोक कल्याण के लिए जलाई गई अखंड ज्योति आज भी यहां आने वाले श्रद्धालुओं के जीवन के तम को मिटाने का काम कर रही है. मान्यता है कि इस ज्योति के दर्शन से मानव जीवन का तम समाप्त हो जाता है. साथ ही इस पावन स्थल के दर्शन मात्र से मानव को एक कल्प यज्ञ का फल प्राप्त होता है.

feedback@chauthiduniya.com

कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इन ख़ास मॉडलों को तैयार किया है.

मिस्टीरियस शैंपू

न झटको जुल्फ से पानी कि मोती फूट जाएंगे...यह गीत अब दीवाने नहीं गाया करते, क्योंकि अब गोरियों के चेहरों पर लंबी जुल्फों के जाल नहीं बिखरते. आजकल प्रदूषण, धूल, धूप, उमस और गंदगी के चलते प्राकृतिक सुंदरता का अस्तित्व नहीं रह गया है. सबसे ज़्यादा परेशानी लंबे बालों वाली गोरियों की होती है. क्योंकि ऐसे वातावरण प्रदूषण में सभी महिलाएं हर तरफ बालों की समस्या से त्रस्त नज़र आती हैं. बालों की समस्या में आम समस्या होती है बाल झड़ने, दोमुहे और रूखे होने की. अपने बालों को घने, लंबे और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इन समस्याओं का समाधान बेहद ज़रूरी है. इसके लिए महिलाएं सभी हथकंडे अपनाने को तैयार रहती हैं. सिने तारिका आयशा टाकिया एक ऐसे ही मिस्टीरियस शैंपू के कैंपेन से जुड़ी हैं जो बालों को पहुंच रहे हर तरह के नुक़सान से उन्हें बचाएगी. उन्होंने देश भर की महिलाओं को चैलेंज किया है कि पहले इसे ट्राई करें, फिर भरोसा करें. उन्होंने इसके साथ ही अपने अनुभव और फोटोग्राफ ऑनलाइन करने की अपील की, जिससे इस शैंपू का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं के अनुभव देश की दूसरी महिलाएं भी जान सकें और भरोसा कर सकें. इस कैंपेन से जुड़कर महिलाएं 5 लाख रुपये का कैश प्राइज भी जीत सकती हैं. इस शैंपू को 80 प्रतिशत महिलाएं टेस्ट कर चुकी हैं, जिनका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा. आयशा के साथ उक्त सभी महिलाएं भी बालों की आम समस्याओं से परेशान थीं. यह शैंपू बाल झड़ना, दोमुहा और रफ होना जैसी समस्याओं का एक साथ समाधान करने में सक्षम है.

घर आया विदेशी टीवी

फोटो– प्रभात पाण्डेय

जापानी कंपनी अकाई ने भारत में टेलीविजन की नई सीरीज लांच की है. इस नई सीरीज में आने वाले टेलीविजनों में अल्ट्रा स्लिम एलईडी, एलसीडी हाई डेफिनेशन और सीआरटी टेलीविजन हैं. भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे एलईडी, एलसीडी हाई डेफिनेशन टेलीविजन को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने यहां उन्नत तकनीक और स्टाइल का मिश्रण किया है. कंपनी ने एलईडी टेलीविजन सेट के पांच मॉडल लांच किए हैं. इन सभी मॉडलों में नैचुरल लाइट तकनीक के साथ डायनमिक बैक लाइट दी गई है. इन सभी मॉडलों को ब्रश्ड स्टील फिनिश दिया गया है, जो टेलीविजन की ख़ूबसूरती में चार चांद लगा देता है. इसके अलावा पिक्चर क्वालिटी को ज़्यादा साफ़ बनाने के लिए डायनमिक स्किन करेक्शन और मोशन कम्पंसेशन तकनीक डाली गई है. इस रेंज के कुछ टेलीविजन मॉडलों में वीडियो यूएसबी की सुविधा दी गई है. टेलीविजन के उक्त ख़ास मॉडल 24, 32 और 42 इंच के साइजों में उपलब्ध हैं. इनकी क़ीमत 17,990 रुपये से लेकर 54,990 रुपये तक है. इस रेंज का सीआरटी अकाई टेलीविजन सेट एनर्जी एफिसिएंट ग्रीन आईसी से लैस है, जिससे घर आया नया टीवी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कलर अपने आप ही सेट कर लेगा. इस ख़ास टेलीविजन के लांच के मौक़े पर अकाई के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणय ढबाई ने कहा कि कंपनी भारत में अपने प्रचार को लेकर काफ़ी उत्साहित है. भारत में अकाई को कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एक भरोसेमंद नाम बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अनोखा की-पैड वाला फोन

भारतीय सेलफोन ब्रांड लावा ने बिजनेस फोन सीरीज में दो नए मॉडल लांच किए हैं, लावा बी-2 और लावा बी-5. दोनों मॉडल क्वर्टी की-पैड वाले हैं. लावा बी-2 हैंडसेट में क्वर्टी की-पैड को अल्फा की-बोर्ड के साथ पेश करके कंपनी ने विश्व में अब तक का सबसे नवीन कांबिनेशन पेश किया है. अल्फा की-बोर्ड में ए से जेड तक अल्फाबेटिकल लेटर्स एक साथ अरेंज्ड होते हैं, जिससे इस्तेमाल करने वाले को परेशानी नहीं होती. कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीण लोगों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इन ख़ास मॉडलों को तैयार किया है. इसके अतिरिक्त युवाओं, जो सबसे अधिक एसएमएस का उपयोग करते हैं और गृहणियों को ध्यान में रखकर यह की-पैड अपनाया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग परंपरागत और क्वर्टी की-पैड का उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अल्फाबेट की-पैड से टाइपिंग बहुत आसान होने से वे इसका सही उपयोग कर पाएंगे. कंपनी को इन नए आविष्कारी की-पैड वाले हैंडसेटों के बल पर भारतीय मोबाइल फोन बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ने और उसके दो अंकों में पहुंचने की उम्मीद है.

उन्होंने बताया कि इस की-पैड पर आधारित अभी दो मॉडल पेश किए गए हैं और शीघ्र ही अन्य मॉडलों में भी इस की-पैड को लगाने की तैयारी चल रही है. इस फोन की क़ीमत भी बहुत कम यानी सिर्फ 1600 से 6000 रुपये के बीच रखी गई है. कंपनी जल्द ही लावा प्राइड के नाम से देश भर में 1000 स्टोर खोलेगी, जिनमें से 50 राजस्थान में खोले जाएंगे. कंपनी अगले माह मोबाइल में हाई रेंज के तीन और मॉडल जारी करेगी. कंपनी इस साल के अंत तक बाज़ार में 3-जी मोबाइल फोन लाने की भी कोशिश कर रही है.

किफ़ायती कार कोरोला ऑल्टिस

फोटो– सुनील मल्होत्रा

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने भारत में अपनी कोरोला ऑल्टिस कार का डीजल संस्करण लांच किया है. 10.95 लाख से लेकर 13.75 लाख रुपये तक की रेंज वाली इस डीजल कार को 1.4 लीटर डी-4डी कॉमन रेल डीजल तकनीक से लैस किया गया है. इसका सिक्स स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम 88.4 पावर का एमिशन देता है और 21.43 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज. इस स्पेशल कार में लेटेस्ट सेफ्टी और लक्जरी फीचर्स डाले गए हैं. लांच के मौक़े पर टोयोटा के मैनेजिंग डायरेक्टर हिरोशी नाकागवा ने कहा कि भारतीय बाज़ार में कारों की बिक्री को देखते हुए कंपनी प्रति माह कोरोला ऑल्टिस की सभी रेंज को मिलाकर 1300 कार बेचने की उम्मीद करती है, जिसमें डीजल संस्करण ऑल्टिस की संख्या 800 हो सकती है. भारत में कोरोला वर्ष 2003 में लांच की गई थी और तबसे अब तक 60 हज़ार कारें बिक चुकी हैं. यह कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बात है.

शानदार गाड़ियों के शौकीन लोगों के लिए ख़ुशख़बरी यह भी है कि बहुत जल्द भारत में टोयोटा कंपनी की विशेष श्रेणी की कार एटियॉस भी उपलब्ध हो जाएगी. नाकागवा ने एटियॉस का ज़िक्र करते हुए बताया कि यह ख़ास कार इसी वर्ष दिसंबर माह तक भारतीय बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी. कंपनी ने एटियॉस को बाज़ार में हैचबैग और सीडान दोनों ही संस्करणों में एक साथ उपलब्ध कराने का मन बनाया है. इसके अलावा एटियॉस का पेट्रोल संस्करण लांच होने के कुछ वक्त बाद ही कंपनी इसका डीजल इंजन भी उतारेगी. कंपनी के मार्केटिंग डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप सिंह का मानना है कि एटियॉस के लांच के बाद कंपनी को अब तक भारत में हुए कुल फ़ायदे से भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. अनुमानित तौर पर 2011 में कंपनी की कारों की बिक्री का आंकड़ा 1.50 लाख होगा, जिसमें 67 हज़ार एटियॉस भी शामिल होंगी.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

हर तरह की पिच और गेंदबाजी के ख़िलाफ़ आसानी से रन बनाने में सक्षम इस बल्लेबाज़ ने एसएससी पर टेस्ट मैचों में कुल 2646 रन बनाए हैं, जो एक रिकॉर्ड है.

राष्ट्रमंडल खेल गौरव या शर्म

मणिशंकर अय्यर

सुरेश कलमाड़ी

अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के संबंध में पूर्व खेल मंत्री एवं कांग्रेस सांसद मणिशंकर अय्यर के एक बयान को लेकर खासा हल्ला-हंगामा हुआ. अय्यर ने अपने बयान में कहा था कि इन खेलों का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो उन्हें निराशा होगी. पहली नज़र में उनका यह बयान ग़ैर ज़िम्मेदारी भरा और राष्ट्रविरोधी लगता है. एक ओर जब सारा देश इस वजह से चिंतित है कि खेल की तैयारियां समय पर पूरी हो पाएंगी या नहीं, तो अय्यर का यह बयान गले से नहीं उतरता. लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती. पिछले सात सालों में खेलों के आयोजन का बजट कई गुना बढ़ चुका है, फिर भी तैयारियों को लेकर संदेह बना हुआ है. आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी भले अपने दावे कर रहे हों, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी इसे लेकर आश्वस्त नहीं हैं. वह समय पर काम पूरा न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की घोषणा भी कर चुकी हैं. खेल शुरू होने में अब केवल डेढ़ महीने का समय बचा है और आधी-अधूरी तैयारियों के भरोसे कलमाड़ी इसे देश का सबसे भव्य और सफल खेल आयोजन घोषित करने से नहीं चूकते, लेकिन तमाम लोगों का मानना यही है कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहीं देश के लिए गौरव बनने की बजाय शर्म बनकर न रह जाए.

इस आशंका की वजह यह है कि खेल से जुड़े सारे प्रोजेक्ट्स समय से पीछे चल रहे हैं और इसके चलते उनकी लागत में भी लगातार वृद्धि हो रही है. साल 2006 में जब खेलों के आयोजन का काम शुरू हुआ था तो इसका कुल बजट 22 हज़ार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 30 हज़ार करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है. बजट में हुई चालीस प्रतिशत से भी ज़्यादा की वृद्धि के लिए अधिकारियों की लेटलतीफी और अदूरदर्शी फ़ैसले ज़िम्मेदार हैं. आयोजन समिति के गठन से लेकर स्टेडियमों के निर्माण तक का काम शुरू से ही इस लेटलतीफी का शिकार होता रहा है. कॉमनवेल्थ विलेज का शुरुआती बजट 465 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 1400 करोड़ हो चुका है. खेल के दौरान यातायात व्यवस्था के लिए साल 2004 में 40 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था, जिसे अब दोगुना करके 80 करोड़ कर दिया गया है. इसी तरह खेल के दौरान विभिन्न स्पर्धाओं के लिए ग्यारह स्टेडियमों के निर्माण की योजना बनाई गई थी और इसके लिए 1200 करोड़ रुपये ख़र्च करने की योजना थी. यह बजट बढ़कर पांच हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा हो चुका है, जबकि अभी निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ है. रही-सही कसर मानसून ने पूरी कर दी है. बारिश के चलते बाक़ी बचे कामों को पूरा करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. जो काम पूरे हो चुके हैं, उनमें भी तमाम तरह की शिक़ायतें आ रही हैं. कहीं बिल्डिंग की छत से पानी टपक रहा है तो कहीं दीवारें टूट रही हैं. खेलों के लिए निर्मित नए शूटिंग रेंज का मई महीने में उद्घाटन हुआ था, लेकिन उसकी दीवारों में दरार आ चुकी है. तैराकी के लिए बने नए स्टेडियम का थोड़े दिन पहले ही उद्घाटन हुआ था और मानसून की पहली बारिश में ही उसमें इतना पानी भर गया कि सारा काम बंद करना पड़ा. गेम्स विलेज में आईटीडीसी को 34 टावरों का पुनर्निर्माण करना था, लेकिन अब तक एक तिहाई काम भी नहीं हो पाया है. फिर भी सरकार आश्वस्त है कि आयोजन समिति सारी तैयारियां समय रहते पूरा करने में कामयाब हो जाएगी. उसकी इस आशावादिता का आधार क्या है, यह तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि ये उम्मीदें पूरी नहीं हुईं तो सारी दुनिया के सामने देश का सिर शर्म से झुक जाएगा.

सवाल केवल देश की प्रतिष्ठा का नहीं है, बल्कि इसके साथ देश के लोगों की बढ़ती परेशानियों का प्रश्न भी जुड़ा है. एक ओर बढ़ती महंगाई के चलते आम लोगों का जीना मुहाल है तो दूसरी ओर सरकार राष्ट्रमंडल खेल के बढ़ते बजट को पूरा करने के लिए हरसंभव उपाय कर रही है, लेकिन आयोजन स्थलों के निर्माण के नाम पर विस्थापित किए गए हज़ारों लोगों को पुनर्वासित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है. कनॉट प्लेस इलाक़े की सुंदरता बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये ख़र्च किए जा रहे हैं, लेकिन इससे वहां के व्यापारियों और आम लोगों को होने वाली परेशानियों की चिंता किसी को नहीं है. खेल के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की सुख-सुविधा के लिए हरसंभव उपाय किए जा रहे हैं. राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन को देश की प्रतिष्ठा का सवाल बताकर हज़ारों करोड़ रुपये ख़र्च किए गए हैं, जबकि सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते ग़रीब लोगों के लिए दोनों वक़्त की रोटी का इंतज़ाम करना मुश्किल हो रहा है. क्या बढ़ती ग़रीबी हमारे लिए शर्म का विषय नहीं है? आरटीआई के एक ख़ुलासे के मुताबिक़, दिल्ली के शेड्यूल्ड कास्ट सब-प्लान के लिए आवंटित फंड में से 265 करोड़ रुपये की रकम खेलों के आयोजन पर ख़र्च कर दी गई है. अय्यर ने अपने बयान में यह भी कहा था कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो भविष्य में और ऐसे आयोजन हो सकते हैं, जिन पर बेतहाशा धन ख़र्च होगा. उनके इस बयान को कई लोग राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, लेकिन संभव है कि वह सरकार का ध्यान इसी ओर खींचना चाहते हों.

अय्यर के बयान के पीछे की राजनीति को दरकिनार कर देखें, तो यह सही है कि राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन पर ख़र्च किया जा रहा अथाह पैसा देश की बहुसंख्यक ग़रीब जनता के साथ भद्दा मज़ाक है. कुछ दिनों पहले सुरेश कलमाड़ी ने खेलों के आयोजन पर मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि यह एक भारतीय शादी जैसा है. हमारे देश में शादी से पहले तक सब कुछ आधा-अधूरा लगता है, लेकिन शादी शुरू होते ही सारी चीजें व्यवस्थित रूप ले लेती हैं. उन्होंने इसी का हवाला देते हुए यह दावा किया था कि अक्टूबर में खेलों की शुरुआत होने से पहले तक सारे काम पूरे हो जाएंगे. लेकिन कलमाड़ी शायद यह भूल गए कि एक शादी और राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है. इतने बड़े आयोजन में किसी चीज को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. फिर इसमें लगा पैसा आम जनता का है. असल मुद्दा तो यह है कि इतना पैसा ख़र्च करने के बाद भी यदि काम समय पर पूरे न हुए तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? आज मणिशंकर अय्यर को देशद्रोही करार देने वाले तमाम लोग पूरी दुनिया के सामने देश का सिर शर्म से झुकने के बाद क्या खुद को देशद्रोही मानने के लिए तैयार होंगे?

आदित्य पूजन
aditya@chauthiduniya.com

अधिकारियों की लेटलतीफी

	समय सीमा	देरी
आयोजन समिति का गठन	मई, 2004	9 महीने
आयोजन समिति द्वारा सामान्य कार्ययोजना की घोषणा	मई, 2004	39 महीने
गेम्स के लिए मास्टर प्लान की घोषणा	मई, 2004	54 महीने
खेल कार्यक्रमों का अनुमोदन	अक्टूबर, 2007	1 महीना
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनुमोदन	अक्टूबर, 2007	19 महीने
ब्रांडिंग नीति का अनुमोदन	अक्टूबर, 2007	19 महीने
टेस्ट इवेन्ट्स का आयोजन	अक्टूबर, 2008	8 महीने

एसएससी के डॉन बने महेला

भारत के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन महेला जयवर्द्धने ने अपना 28वां टेस्ट शतक पूरा किया तो यह उनके लिए खास बन गया. इसकी बदौलत महेला न केवल अपनी टीम को मज़बूत स्थिति में पहुंचाने में कामयाब रहे, बल्कि महान डॉन ब्रेडमैन को भी पीछे छोड़ने में सफल रहे. कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (एसएससी) मैदान पर महेला का यह दसवां टेस्ट शतक था, जो किसी खिलाड़ी द्वारा किसी एक मैदान पर बनाए गए शतकों के लिहाज़ से एक नया रिकॉर्ड है. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रेडमैन के नाम था, जिन्होंने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर 9 शतक लगाए थे. कई और ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका किसी एक मैदान के साथ खास रिश्ता रहा है. वीवीएस लक्ष्मण एवं मोहम्मद अजहरुद्दीन का ईडन गार्डन्स, सुनील गावस्कर का वानखेड़े स्टेडियम और ग्राहम गूच का लॉर्ड्स के मैदान के साथ कुछ ऐसा ही रिश्ता रहा है. अपने पसंदीदा मैदानों पर खेलते हुए इन खिलाड़ियों के बल्ले को रोकना विपक्षी गेंदबाज़ों के लिए टेढ़ी खीर साबित होता रहा है. महेला जयवर्द्धने का कोलंबो के एसएससी मैदान के साथ ऐसा ही रिश्ता रहा है. अपने टेस्ट करियर में एसएससी पर उन्होंने 23 टेस्ट मैचों में 10 शतक लगाए हैं. हालांकि ब्रेडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी महेला ने किसी भी तुलना से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि ब्रेडमैन ने एमसीजी पर केवल 11 टेस्ट मैचों में ही 9 शतक लगाए थे तो फिर तुलना कैसे की जा सकती है.

श्रीलंका टीम के पूर्व कप्तान महेला जयवर्द्धने को कलात्मक शैली के उन बल्लेबाज़ों की श्रेणी में शुमार किया जाता है, जो ताक़त की जगह तकनीक और टाइमिंग के सहारे बल्लेबाज़ी करते हैं. हर तरह की पिच और गेंदबाज़ी के ख़िलाफ़ आसानी से रन बनाने में सक्षम इस बल्लेबाज ने एसएससी पर टेस्ट मैचों में कुल 2646 रन बनाए हैं, जो एक रिकॉर्ड है. यह किसी बल्लेबाज़ द्वारा किसी एक मैदान पर बनाए गए सबसे ज़्यादा रन हैं. अपनी इसी शतकीय पारी के दौरान महेला ने टीम के मौजूदा कप्तान कुमार संगकारा के साथ तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करके एक और नया रिकॉर्ड बनाया. महेला और संगकारा के बीच टेस्ट मैचों में यह बारहवीं शतकीय साझेदारी थी, जो श्रीलंका क्रिकेट के लिए कीर्तिमान है. इससे पहले यह रिकॉर्ड अर्जुन रणतुंगा और अरविंद डीसिल्वा के नाम था, जिनके बीच कुल 11 शतकीय साझेदारियां हुई थीं, लेकिन एसएससी के डॉन ने अपनी नायाब बल्लेबाजी से सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

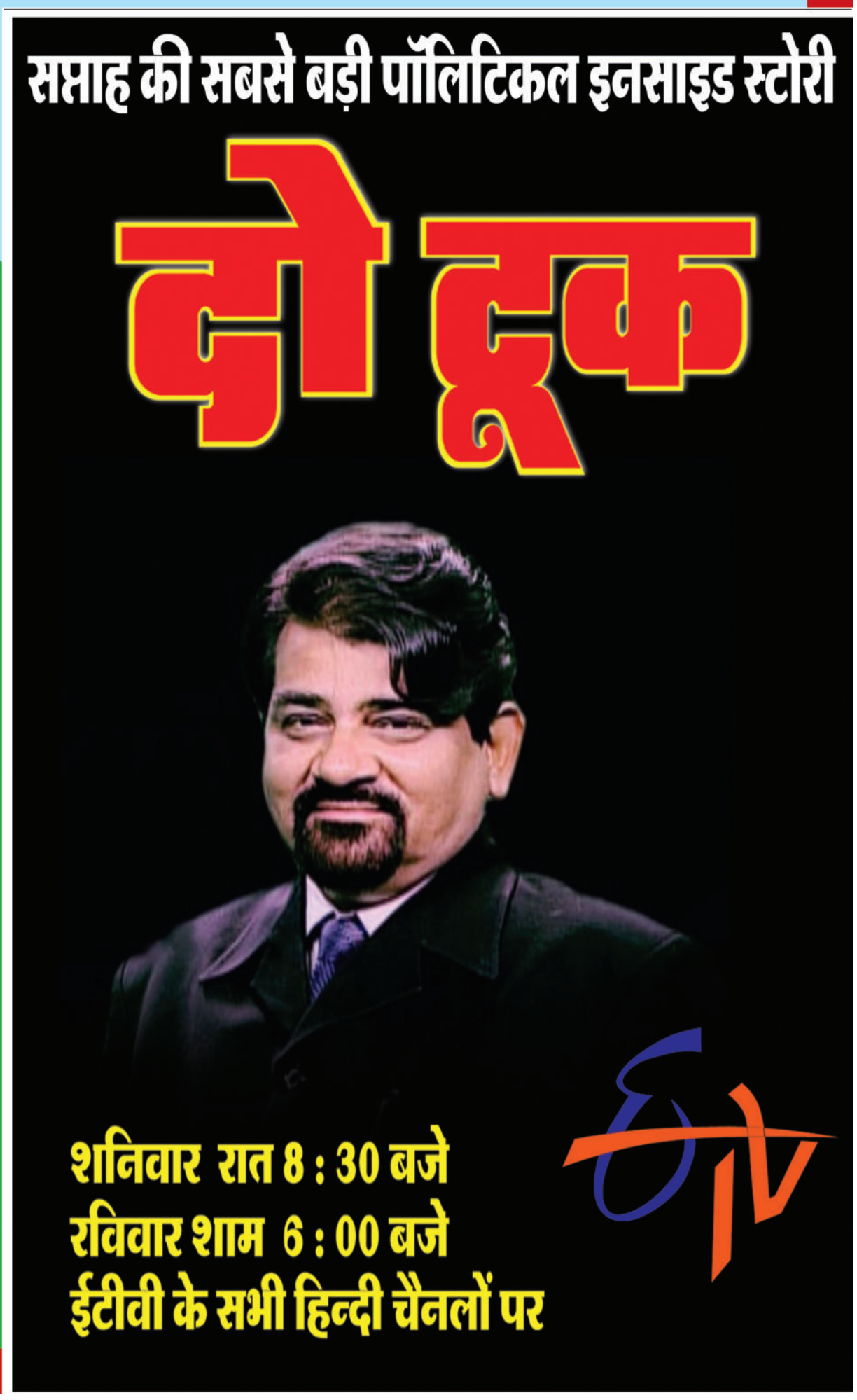

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 9 अगस्त–15 अगस्त 2010

बॉलीवुड के अभिनेताओं एवं अभिनेत्रियों के प्रेम प्रसंगों की ख़बरें कोई नई बात नहीं हैं. लेकिन वह ज़माना और था जब किसी अभिनेत्री के रिश्तों के बारे में कोई ख़बर आती थी तो पूरा देश उस ख़बर को लेकर उत्सुक हो जाता था.

बॉलीवुड का प्यार और मीडिया की मूर्खता

इसे मीडिया की मूर्खता ही कहेंगे, जो सच्चाई से पर्दा उठाने के बजाय झूठ बेचने वालों के चंगुल में फंसकर टीवी और अख़बारों में ऐसी ख़बरें छाप देता है, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ता है. ऐसी क्या बात है कि जब भी किसी अभिनेत्री की फिल्म रिलीज होने वाली होती है, ठीक उसी वक़्त उसके जीवन में नया प्रेमी आ जाता है या फिर कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है. ऐसी झूठी ख़बरें आसानी से बिक जाती हैं, इसलिए आज के संवाददाताओं ने सच की गहराई तक जाना छोड़ दिया है.

रीतिका सोनाली

आजकल फिल्म अभिनेत्रियों और अभिनेताओं के बदलते रिश्तों की ख़बरें लगातार दिख रही हैं. इन ख़बरों को देख-सुनकर दर्शकों और पाठकों को यह यकीन होने लगा है कि बॉलीवुड में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है. प्यार-मोहब्बत जैसी चीजें बेकार हो गई हैं. इन ख़बरों से समाज को यह संदेश मिलता है कि ज़माना बदल रहा है, हमारा समाज बंधनों से मुक्त होकर अपनी अलग पहचान बना रहा है, जहां पहले जैसी भावनाओं, संवेदनाओं और प्यार जैसी चीजों का कोई स्थान नहीं रह गया है. ऐसी ख़बरें बदलते हुए समाज व युवा पीढ़ी की सोच और व्यवहार का विकृत चेहरा प्रस्तुत करती हैं. अफ़सोस की बात यह है कि फिल्म अभिनेत्रियों के रिश्तों को लेकर छपने वाली ज़्यादातर ख़बरें सच नहीं होतीं. हाल में ही टीवी चैनलों पर यह ख़बर चल रही थी कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के जीवन में कोई नया प्रेमी आया है. यह वही दीपिका हैं, जो फिल्म ओम शांति ओम में थीं. उसी वक्त रिलीज होने वाली एक और फिल्म थी सांवरिया, जिसके नायक रणबीर कपूर थे. दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई थीं. प्रोमोशन के दौरान दीपिका शाहरुख के साथ और रणबीर कपूर के साथ अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर थी. उस दौरान एक सच किसी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया गया कि रणबीर कपूर और दीपिका काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ हैं. हद तो तब हो गई, जब सच बताने के बजाय रणबीर कपूर और सोनम कपूर के प्रेम प्रसंग की झूठी ख़बर दिखाई जाने लगी. दीपिका की दूसरी फिल्में आती गईं और मीडिया के सौजन्य से उनके रिश्ते कभी धोनी तो कभी युवराज सिंह के साथ जुड़ते चले गए. दीपिका की जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होने का वक़्त आया, उनसे जुड़ी झूठी कहानियां टीवी और अख़बारों में प्रसारित होती और छपती चली गईं. हाल में आई फिल्म लफंगे परिंदे से दीपिका पादुकोण और नील नितिन मुकेश के प्रेम संबंधों की ख़बरें उड़ने लगीं और ये अफ़वाहें केवल उड़ती हुई नहीं थीं, बल्कि सभी ख़बरिया चैनलों ने घंटे भर का प्रोग्राम दिखाकर इस ख़बर की पुष्टि भी कर दी थी. इस ख़बर के साथ सार्वजनिक तौर पर जितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता था, सभी चैनलों और अख़बारों ने किया. सितारों के प्रेम संबंध मीडिया में इंटरटेनमेंट बीट की सबसे बड़ी ख़बरें बन गए हैं. ऐसा सिर्फ़ दीपिका के साथ ही नहीं हुआ है. बॉलीवुड के लव बर्ड्स माने जाने वाले करीना कपूर और शाहिद कपूर की फिल्म जब वी मेट के प्रोमोशन के वक़्त फिल्म का प्रोमोशन कम और दोनों के प्रेम संबंधों का प्रमोशन ज़्यादा हुआ. यहां तक की दोनों का एमएमएस भी आ गया, जिसे ख़ूब प्रचारित किया गया. इस तरह की ख़बरें अन्य अभिनेत्रियों के बारे में भी छप चुकी हैं. ऐसा तभी होता है, जब उनकी फिल्म आने वाली होती है. हैरानी की बात यह है कि इस तरह की ख़बरों को लेकर उक्त अभिनेत्रियां तुरंत प्रतिक्रिया भी नहीं देती हैं. फिल्म रिलीज होने के एक-दो सप्ताह बाद वे इन ख़बरों का बड़ी आसानी से खंडन कर देती हैं और बात आई-गई होकर रह जाती है. सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की ख़बरें आते ही अभिनेत्रियां इनका खंडन क्यों नहीं करतीं? क्या कारण है कि फिल्म रिलीज होने के वक़्त ही मीडिया में इस तरह की ख़बरें आने लगती हैं? क्या इस तरह की ख़बरों को जानबूझ कर प्रसारित-प्रकाशित किया जाता है? असलियत यह है कि आज मीडिया में काम करने वाले फिल्म रिपोर्टरों के पास सच समझने और जानने की न तो क्षमता है और न ही उसके लिए मेहनत करने का हौसला. उनके लिए प्रेस रिलीज ही अंतिम सच है. समझने वाली बात यह है कि प्रेस रिलीज का मतलब तो यही होता है कि संबंधित व्यक्ति या संस्था ने वही बातें उसमें लिखी हैं, जिन्हें वह छपवाना चाहता है. रिपोर्टरों का काम होता है कि जिन चीजों को छिपाया जाए, उन्हें बाहर निकालना. इस संदर्भ में आज के दौर में सबसे ख़राब हालत फिल्मों की है. फिल्मों से जुड़ी ज़्यादातर ख़बरें पीआर एजेंसियों के जरिए आती हैं. मतलब यह कि फिल्मों के प्रोमोशन के लिए फिल्म निर्माता पब्लिक रिलेशन संस्थाओं को अपना एजेंट बनाती हैं. इन एजेंसियों का काम फिल्म को रिलीज होने से पहले लोगों की जुबान पर लाना होता है. हिंदुस्तान में इन एजेंसियों को यह भ्रम हो गया है कि फिल्म रिलीज होने से पहले कोई विवाद खड़ा हो जाए तो फिल्में ख़ुद-ब-ख़ुद हिट हो जाएंगी. यही वजह है कि रिलीज होने वाली फिल्म में काम कर रहे अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के रिश्ते को लेकर कुछ विवाद खड़ा किया जाता है. असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिल्म को हिट बनाने के लिए उक्त एजेंसियां झूठी ख़बरें फैला देती हैं. इसी काम के लिए वे फिल्म निर्माताओं से पैसे लेती हैं. लेकिन इन ख़बरों को छापने वाले संवाददाताओं की मूर्खता का आलम यह है कि उन्हें पब्लिक रिलेशन संस्थाओं-कंपनियों का यह खेल नज़र नहीं आता. यही वजह है कि इन ख़बरों की न तो कभी पुष्टि होती है और न ही इसके पीछे चल रहे खेल का रहस्योद्घाटन हो पाता है. बड़े दु:ख के साथ यह कहना पड़ता है कि ऐसी ख़बरें इस बात का सबूत हैं कि संवाददाताओं का स्तर दिनोंदिन गिरता जा रहा है. बॉलीवुड के अभिनेताओं एवं अभिनेत्रियों के प्रेम प्रसंगों की ख़बरें कोई नई बात नहीं हैं. लेकिन वह ज़माना और था, जब किसी अभिनेत्री के रिश्तों के बारे में कोई ख़बर आती थी तो पूरा देश उस ख़बर को लेकर उत्सुक हो जाता था. भाषा का चयन भी सावधानी से किया जाता था. यही वजह है कि आज भी टीवी पर किसी आयोजन में रेखा और अमिताभ बच्चन को एक साथ देखते ही दर्शक रुक जाते हैं. यह जानने को उत्सुक हो जाते हैं कि रेखा ने अमिताभ को किस तरह देखा या फिर अमिताभ ने रेखा की तरफ नज़रें घुमाईं या नहीं. आज के दौर के सितारों की प्रेम कहानियां न किसी दर्शक के मन में टीस जगाती हैं और न कोई संवेदना. मीडिया अपनी बेवकूफी का सबूत चीख-चीखकर ऐसी ख़बरें दिखाकर सिद्ध करता है. अक्सर किसी फिल्म के रिलीज होने से पहले उसके नायक-नायिका के प्रेम संबंधों की ख़बरों को लेकर हर न्यूज़ चैनल पर आधे घंटे का प्रोगाम चलाया जाता है. ऐसे में उनके पिछले प्रेम संबंधों को तोड़कर उनका नाम आने वाली फिल्म में साथ काम करने वाले को-स्टार के साथ जोड़ दिया जाता है. ऐसा करने के पीछे वजह सिर्फ़ एक होती है, वह है फिल्म का प्रोमोशन. कई बार फिल्म निर्माण के कांट्रैक्ट की बेबसी होती है तो कभी फिल्म को जनता के बीच चर्चा का विषय बनाने का तरीक़ा, लेकिन पत्रकारिता करने वाले उक्त फिल्म रिपोर्टर यह भूल जाते हैं कि उनकी इस बेवकूफी का क्या नतीजा होगा. देश के गांवों, शहरों और महानगरों में सैकड़ों ऐसे युवक-युवतियां हैं, जो बॉलीवुड, मॉडलिंग या कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट वाली इंडस्ट्री में करियर बनाने की सोच रहे होते हैं, ऐसे में इस तरह की ख़बरें इन लोगों के अभिभावकों के मन में संशय पैदा कर देती हैं. बॉलीवुड की गलियां बेवजह बदनाम होती रहती हैं और उन्हें बदनाम करने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है मीडिया.

ऐसा नहीं है कि पहले बॉलीवुड में होने वाले प्रेम संबंधों पर कोई ख़बर या अफ़वाह न उड़ती रही हो, लेकिन उस वक़्त ऐसी ख़बरों को बेहद संवेदनशीलता के साथ पाठकों-दर्शकों के आगे पेश किया जाता था, तब आज की तरह फूहड़ता नहीं थी. देश की जनता न तो रेखा को जानती है और न ही अमिताभ बच्चन से मिलने और जानने का मौक़ा मिलता है. यही बात बॉलीवुड के दूसरे अभिनेताओं एवं अभिनेत्रियों के बारे में कही जा सकती है. ख़बर देखने और पढ़ने वाले लोग मीडिया के माध्यम से इनके बारे में छवि बनाते हैं. ऐसी झूठी ख़बरें ख़तरनाक हैं, ये भ्रम पैदा करती हैं और लोगों के दिमाग़ को बदलती जीवनशैली के बारे में गुमराह करती हैं. भारत ऐसा देश है, जहां मानवीय संवेदना और मर्यादा का विशेष महत्व है. इसे मीडिया की गलती कहें या मूर्खता कि वह हमारे समाज के ताने-बाने पर ही चोट कर रहा है.

ritika@chauthiduniya.com

प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है: असीम तिवारी

विश्व की सबसे महंगी गलियों में से एक वॉल स्ट्रीट में काम करने के बाद कोई बोरियत महसूस करे तो उसे समझ लेना चाहिए कि ख़ूब सारा पैसा कमाना उसकी मंज़िल नहीं है. हालिया रिलीज हुई फ़िल्म आई हेट लव स्टोरीज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कानपुर के असीम तिवारी को भी जब ऐसा ही महसूस होने लगा, तब वह देश-विदेश के भ्रमण पर निकल पड़े. यूरोप-अमेरिका घूमते हुए जब वह भारत आए तो लेह, लद्दाख़ एवं उत्तर भारत होते हुए अपने शहर कानपुर पहुंचे और फिर वहां से मुंबई पहुंचे. वह हमेशा से क्रिएटिव फील्ड में काम करना चाहते थे, लेकिन एक आम मध्यमवर्गीय परिवार में पले-बढ़े बच्चे की तरह उनके कंधों पर भी बेहतरीन करियर बनाने की ज़िम्मेदारी थी. इसी को अपनी नियति मानकर उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाया और बढ़िया जीवनशैली की चाह में अमेरिका चले गए. लेकिन उनका मन वहां रम-रच नहीं पाया. अपने फिल्मी सफ़र के बारे में असीम कहते हैं कि वर्ष 2006 में मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने अंकल विवेक अग्निहोत्री के साथ उनकी फिल्म दे दनादन एवं गोल में बतौर सहायक निर्देशक काम किया. काम करते-करते वह कैमरे के पीछे की तमाम बारीकियां सीख गए. वह कहते हैं कि कैमरे के पीछे का मंजर किताबें पढ़ने से बिलकुल अलग अनुभव देता है. सहायक निर्देशक बनकर वह सीख गए कि उनकी मंज़िल कहां है और उस तक उन्हें कैसे पहुंचना है? पर्दे पर आने के लिए एक रास्ता मॉडलिंग का था, जिसे इंडस्ट्री के दूसरे स्टार्स चुनते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि यह उनके लिए नहीं था, क्योंकि वह मॉडलिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने दूसरा जरिया अपनाया. कैमरे के पीछे काम करते हुए उन्होंने धीरे-धीरे जाना कि एक्टिंग क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है. अपनी प्रतिभा को निख़ारने के लिए प्रैक्टिकल के साथ-साथ असीम ने निर्देशन की थ्योरी पर भी ध्यान दिया. उन्होंने इससे संबंधित कोर्स किया और स्टडी के दौरान गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे. वह मानते हैं कि जब तक काम को प्रैक्टिकली न सीखा जाए, तब तक आप स्टेज पर बढ़िया परफॉरमेंस नहीं दे सकते हैं. असीम ने संजीत एवं जफ़र अब्बास जैसे लोगों के साथ ट्रेनिंग की. उन्होंने इस फील्ड में बने रहने के लिए वर्षों तक ब्लू मोबाइल, बीएच-1 एमटीवी एवं मेट लाइफ इंश्योरेंस आदि के लिए एड फिल्में भी कीं. फिल्म इंडस्ट्री को समझने का उनका अपना नज़रिया है. वह मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लोगों का मनोरंजन कर सकता है तो वह सबसे बेहतर काम है और यही एक अलग काम है जो व्यक्ति को अपने जीवन में करने की कोशिश करनी चाहिए.

बॉलीवुड में गॉड फादर के कॉन्सेप्ट पर थोड़ा-बहुत यकीन करने वाले असीम कहते हैं कि किसी सपोर्ट के रहने पर दो तरह से अच्छा महसूस कर सकते हैं. पहला मोरल सपोर्ट एवं बेसिक ग्रूमिंग, जिसमें आप अनुभवी लोगों से सही सलाह पाते हैं, और फिर आपकी राहें आसान हो जाती हैं. दूसरा सहयोग वह होता है, जिसमें आप ख़ुद काम करते हैं, लेकिन आपको केवल एक लांच मिलता है. जैसा कि इंडस्ट्री में कई निर्माता-निर्देशकों के बेटे हैं, लेकिन मैंने अपना करियर शुरू से ख़ुद बनाया और अब तक अपने रास्ते ख़ुद ही तय करके यहां तक पहुंचा हूं.

असीम ने बेशक न्यूयॉर्क में बुलंदियों पर पहुंचते अपने बैंकिंग करियर को अधर में छोड़ दिया, लेकिन हृदय से वह हमेशा भारतीय रहे. उनका सबसे बड़ा गुण है, अच्छी चीजों को ख़ुद में आत्मसात कर लेना. बैंकिंग करियर के अनुभव उन्हें बॉलीवुड में कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देते, क्योंकि वहां उन्होंने प्रोफेशनलिज्म सीखा है. वह कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर की नौकरी में अनुशासन था और हर तरह के दबाव में काम करने की बाध्यता थी. इन सब चीजों से उन्हें लगता है कि वह इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे दूसरे स्ट्रग्लर्स से अलग हैं और उन्हें क़ामयाबी ज़रूर और जल्द मिलेगी. असीम की तरह कई अन्य सितारे भी अपनी भारी-भरकम वेतन वाली नौकरी छोड़कर इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं. असीम मानते हैं कि बहुत से लोगों को सिर्फ़ इस क्षेत्र का ग्लैमर अपनी ओर खींच लाता है. यही वजह है कि वह अपना सौ फ़ीसदी नहीं दे पाते. आने वाले ज़्यादातर स्ट्रगलर दबाव में काम करना बर्दाश्त नहीं कर पाते और न हैंडल कर पाते हैं. अपने प्रोफेशनलिज्म के बल पर असीम के पास आज प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है. उन्होंने अभी न्यूयॉर्क की एक हॉलीवुड फिल्म पर काम करना शुरू किया है, जिसके डायरेक्टर हैं अरुण फ्रेंग. बॉलीवुड में भी वह विवेक अग्निहोत्री की फिल्म रोमियो एंड जूलिएट में काम कर रहे हैं. वह आगे करण जौहर के निर्देशन में काम करना चाहते हैं, ख़ासकर थ्रिलर फिल्मों में. अपने पसंदीदा एक्टर आमिर ख़ान की प्रशंसा करते हुए असीम कहते हैं कि उनकी हर फिल्म में मेहनत और प्रतिभा साफ़-साफ़ दिखाई देती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 9 अगस्त–15 अगस्त 2010

www.chauthiduniya.com

लालू और पासवान भी दौड़ में

बिहार के दिग्गज नेताओं की चुनावी रणनीति में इस बार एक ख़ास बात देखने को मिल रही है. गुणा-भाग चुनाव को लेकर तो चल ही रहा है, पर साथ ही साथ चुनाव बाद के हालात पर भी उनकी नज़रें अभी से टिकी हैं. ख़ासकर लालू प्रसाद एवं रामविलास पासवान की पूरी कोशिश है कि किसी भी सूरत में बाज़ी इस बार हाथ से न जाने पाए, चाहे इसके लिए उन्हें ख़ुद ही चुनावी अखाड़े में क्यों न उतरना पड़े और अपने हाथों में ही कमान क्यों न लेनी पड़े.

सभी फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

चुनाव लड़ने और जीतने की रणनीति पर तो इन दिनों दिन-रात काम चल ही रहा है, पर चुनाव बाद की संभावित परिस्थितियों पर भी सभी दलों के महारथी माथा खपा रहे हैं. वजह, सभी दलों का यह प्रारंभिक आकलन है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने वाला. त्रिशंकु विधानसभा में दो-चार सीटों का अंतर भी फर्क डाल देता है और कभी-कभी तो ऐसे नेता का सितारा चमक जाता है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता. झारखंड का उदाहरण इन नेताओं के सामने है. इसलिए तैयारी चुनाव बाद की भी हो रही है. चुनाव बाद अगर सीटें घटीं तो कई दुश्मन दोस्त हो जाएंगे और कई दोस्त दुश्मन बन जाएंगे. यही वजह है कि इस बात का ख्याल रखने की कोशिश सभी दल कर रहे हैं. सार्वजनिक तौर पर भले ही कोई दल यह नहीं कह रहा कि उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने जा रहा है, पर अंदरखाने का आकलन यह है कि सभी दल त्रिशंकु विधानसभा की आशंका जता रहे हैं. इसकी वजह भी बहुत साफ़ है. लगभग सभी दलों के आधार वोटों में सेंध लग चुकी है. जदयू एवं भाजपा से जहां अगड़ी जातियों की दूरी बढ़ी है, वहीं राजद को कुछ मुस्लिम वोटों का नुक़सान होता दिखाई पड़ रहा है. कांग्रेस मज़बूत हो रही है, पर चुनाव के दिन तक वह अपने आप को कितना गंभीर रख पाती है, इस पर भी बहुत सारे चुनावी नतीजे निर्भर करेंगे.

मौजूदा राजनीतिक हालात ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि कोई भी दल दावे के साथ यह नहीं कह सकता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं. इसलिए पिछले विधानसभा चुनाव के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल है. पिछले पांच सालों में कुछ दलों ने नए वर्गों को अपने साथ जोड़ा भी है. लोकसभा चुनाव में इसका पूर्वाभ्यास हो चुका है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों अलग-अलग लड़ाइयां हैं. जो फार्मूला लोकसभा चुनाव में हिट रहता है, वह विधानसभा चुनाव में आकर पिट जाता है. चूंकि विधानसभा चुनाव में निहायत स्थानीय मसलों एवं जातीय ताने-बाने का बोलबाला रहता है. इसलिए लोकसभा चुनाव के आधार पर विधानसभा चुनाव का कोई खाका खींचना हमेशा ग़लत होता है. यही वजह है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान एवं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव और उसके बाद पैदा होने वाले राजनीतिक परिदृश्य की ओर टकटकी लगा रखी है.

राजद-लोजपा के लिए यह चुनाव जीवन-मरण का प्रश्न बन चुका है. लालू एवं पासवान हर हाल में बिहार की सत्ता पर क़ाबिज़ होना चाहते हैं. दिल्ली की राजनीति में चोट खाने के बाद लालू प्रसाद कई दफा कह चुके हैं कि वहां ताक़त की पूजा होती है. दिल्ली में पूछ तभी होगी, जब बिहार से ताक़त मिलेगी. सीएजी रिपोर्ट के बाद नीतीश के दामन में लगे दाग को लालू प्रसाद पूरी तरह भुनाना चाहते हैं. चारा घोटाले के कारण बैकफुट पर चले गए लालू प्रसाद को लगता है कि वह अब जनता को समझा पाएंगे कि नीतीश का दामन भी साफ़ नहीं है. उन्होंने भी स्कूटर पर अनाज ढोया है. नीतीश कुमार की लापरवाही के कारण कुशहा तटबंध टूटा, जिसके कारण भारी तबाही हुई. मतलब लालू प्रसाद में भरोसा जगा कि नीतीश कुमार को चुनावी मैदान में पछाड़ा जा सकता है. इस कारण तैयारी काफी तेज़ कर दी गई. प्रभुनाथ सिंह एवं आनंद मोहन की सीटों की मांग पर उदारता पूर्वक विचार हो रहा है. बताया जा रहा कि राबड़ी देवी को इस बार चुनाव में मुख्य योद्धा के तौर पर नहीं उतारा जाएगा. चुनावी माहौल बनाने, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए लालू प्रसाद ख़ुद भी चुनावी अखाड़े में उतर सकते हैं.

रामविलास पासवान को भी लालू प्रसाद के नाम पर कोई आपत्ति नहीं होगी. लेकिन पेंच तब फंसेगा, जब राजद-लोजपा गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर होगा और बिना कांग्रेस की मदद लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा. ऐसी स्थिति में रामविलास पासवान का सितारा चमक सकता है. हालांकि कांग्रेस के नेता बार-बार यह कह रहे हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है और अगर बहुमत न मिला तो वह विपक्ष की भूमिका निभाएगी, लेकिन बताया जाता है कि केंद्रीय राजनीति के कारण अगर समर्थन देने की नौबत आई तो कांग्रेस लालू के बजाय पासवान को तवज्जो देगी.

पूरी कवायद इस बात को लेकर हो रही है कि अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो अपने नाम पर सरकार बनाने लायक विधायकों का जुगाड़ किया जा सके. लालू जानते हैं कि बिहार की राजनीति में उनका कद कई तरह की अड़चनों को दूर कर देगा. रामविलास पासवान को भी लालू प्रसाद के नाम पर कोई आपत्ति नहीं होगी. लेकिन पेंच तब फंसेगा, जब राजद-लोजपा गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर होगा और बिना कांग्रेस की मदद लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा. ऐसी स्थिति में रामविलास पासवान का सितारा चमक सकता है. हालांकि कांग्रेस के नेता बार-बार यह कह रहे हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है और अगर बहुमत न मिला तो वह विपक्ष की भूमिका निभाएगी, लेकिन बताया जाता है कि केंद्रीय राजनीति के कारण अगर समर्थन देने की नौबत आई तो कांग्रेस लालू के बजाय पासवान को तवज्जो देगी. अगर लालू प्रसाद को भी यह लगेगा कि उनका ख़ुद का खेल बिगड़ रहा है तो वह नीतीश को सत्ता से बाहर रखने के लिए रामविलास को आगे कर सकते हैं. लोजपा की भी तैयारी इस बार आर या पार वाली है.

पहला टास्क राजद से अधिक से अधिक सीटें लेकर तालमेल करना है, जो लगभग पूरा हो गया है. राज्यसभा में चुने जाने के बाद रामविलास पासवान का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब वह पहले से ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं. लालू प्रसाद से बेहतर तालमेल के साथ चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए प्रखंड स्तर पर तैयारी हो रही है. रामचंद्र पासवान का कहना है कि लोजपा बिहार में एक बड़ी ताक़त के रूप में उभरने जा रही है. बिहार के लोग लोजपा पर भरोसा करते हैं और चुनाव में वह नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं. वह कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यह फ़ैसला तो दोनों दलों के नेता एवं निर्वाचित विधायक मिलकर करेंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार को एक बेहतर विकल्प मिलेगा, क्योंकि नीतीश की विदाई तय हो चुकी है. जदयू एवं भाजपा में तो कोई विवाद नहीं है. जदयू ने अगर भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई तो नीतीश का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन अगर यह संभव नहीं हुआ तो जदयू नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए कई नए विकल्पों पर विचार शुरू कर देगा. कांग्रेस के लिए इतना तो तय है कि वह जिसे सहयोग करेगी, उसके लिए सरकार बनाना उतना ही आसान होगा. त्रिशंकु विधानसभा तो पार्टियों में तोड़फोड़ और विधायकों की खरीद-फरोख्त का भी रास्ता खोल देती है. अगर किसी दल को बहुमत न मिला तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बिहार में चुनाव के बाद जो खेल खेला जाएगा, वह अपने आप में अजूबा ही होगा!

feedback@chauthiduniya.com

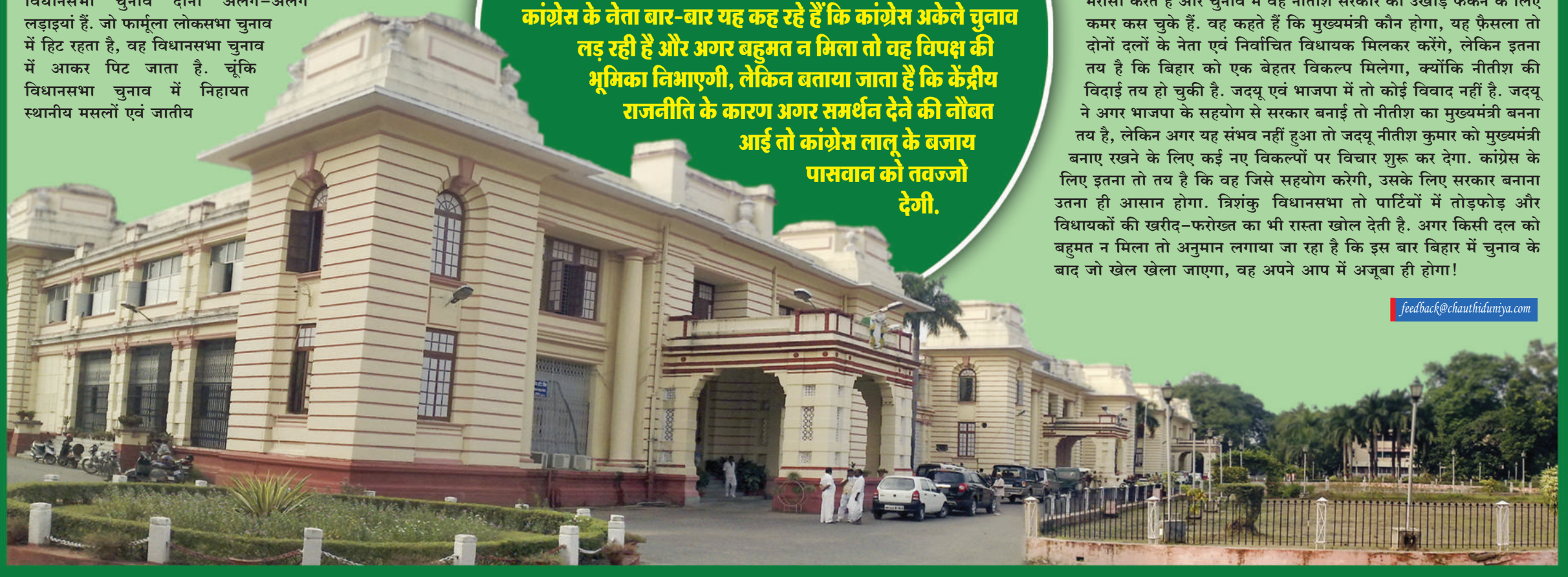

चौथी दुनिया

विश्व की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी मित्तल को अपने प्रस्तावित संयंत्र स्थल पर स्थानीय ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है.

डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की कमी के चलते अनुमंडल के कई स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह बंद हो चुके हैं या फिर सप्ताह में एक–दो दिन ही खुल पाते हैं.

चौथी दुनिया

भंवर में फंसी औद्योगीकरण की नाव

नवल किशोर सिंह

झारखंड का गठन होने के बाद जिस रफ्तार से औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ एमओयू हुआ था, उससे यहां के लोगों को ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति की पुनरावृत्ति की उम्मीद जगी थी, लेकिन एक दशक गुजरने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि औद्योगीकरण के लिए जिस इच्छाशक्ति की ज़रूरत थी, उसका यहां अभाव है. अभी तक उद्योग–धंधों के विकास के लिए बुनियादी माहौल भी नहीं बनाया जा सका. बीते दस वर्षों के दौरान न तो आधारभूत ढांचा तैयार हुआ और न ही विधि व्यवस्था दुरुस्त हुई. इसके अलावा उद्यमियों को ज़रूरी सुविधाएं भी मुहैया नहीं कराई जा सकी हैं. अभी तक देश–विदेश के 74 से भी ज़्यादा औद्योगिक घरानों के साथ एमओयू किया जा चुका है. इन पर करोड़ों रुपये फूंके जा चुके हैं. बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा एवं मधु कोड़ा के मुख्यमंत्रित्व काल में एमओयू की प्रतिस्पर्धा सी चल पड़ी थी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य शायद राजनीतिक लाभ उठाना और सुविधा राशि प्राप्त करना भर था. किसी भी सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया कि उद्योग लगाने के लिए ज़रूरी सुविधाएं कैसे देनी हैं. कुछ कोशिशें हुईं भी, लेकिन सिर्फ़ निजी क्षेत्र के विकास के लिए. सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उपक्रम की स्थापना या उसका प्रयास तो दूर, पिछले एक दशक केअंदर इसकी चर्चा तक नहीं की गई.

अभी तक किसी सरकार ने इस बात का आकलन नहीं किया कि राज्य में कुल सरकारी ज़मीन कितनी और कहां–कहां पर है. कोई भूमि बैंक भी तैयार नहीं किया गया. उद्यमियों को पानी और बिजली कहां से दी जाएगी, इस पर भी विचार नहीं किया गया. उद्यमियों को ज़मीन का आवंटन नहीं किया गया और किया गया तो स्थानीय विस्थापितों से उन्हें स्वयं निपटने के लिए छोड़ दिया गया. इस कारण कई कंपनियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. कुछ उद्यमी यदि अपना संयंत्र स्थापित करने में सफल भी हुए तो यह उनके प्रयासों का नतीजा है. सरकारी तंत्र से सहयोग की जगह असहयोग ही मिला. जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड पतरातु में स्टील प्लांट लगाने में इसलिए सफल हुआ, क्योंकि उसने बिहार स्टील एंड एलॉय लिमिटेड के बंद पड़े प्लांट को खरीद लिया था और स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लेकर काम शुरू किया. उसने स्थानीय लोगों को नियोजन दिया और सामुदायिक विकास के तहत जन सुविधाओं का विस्तार भी किया. सरकार जो काम नहीं कर सकी थी, उसे पूरा करने के कारण ग्रामीणों ने प्लांट का स्वागत किया. वहीं आसनबनी में प्रस्तावित जेएसपीएल के6 मिलियन टन क्षमता के स्टील प्लांट, गोड्डा में प्रस्तावित पॉवर प्लांट, खलारी में प्रस्तावित एल्युमिनियम प्लांट, जेरालदाबुरु में माइंस को फॉरेस्ट क्लियरेंस एवं भूमि अधिग्रहण आदि मामलों में राज्य सरकार की हरी झंडी न मिलने के कारण जिंदल को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है.

राज्य में उद्योग लगाने के इच्छुक अभिजीत ग्रुप को भी सरकारी उदासीनता का दंश झेलना पड़ रहा है. ग्रुप द्वारा लातेहार ज़िले के चंदवा स्थित चकला गांव में 1200 मेगावाट के पॉवर प्लांट का निर्माण कार्य प्रगति पर है. यहां कंपनी को अपना प्लांट स्थापित करने में कुर्बानियां भी देनी पड़ीं. पिछले वर्ष अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए कंपनी के चार सुरक्षागार्डों की हत्या कर दी थी. इस घटना से कंपनी के अधिकारी डरे–सहमे थे, लेकिन ग्रुप के सीईओ अरुण गुप्त की दृढ़ इच्छाशक्ति और झारखंड के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे के कारण प्लांट का निर्माण कार्य जारी रहा. वर्ष 2012 तक इसमें उत्पादन शुरू कर दिए जाने की उम्मीद है. वहीं इसी ग्रुप के सरायकेला–खरसावां में एलॉय स्टील प्लांट के लिए आवंटित सिसई–वृंदा कोल ब्लॉक की माइनिंग लीज से संबंधित फाइल फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए सचिवालय में धूल फांक रही है. कंपनी के सीईओ अरुण गुप्त ने राज्यपाल के सलाहकार वी एस दुबे से इस दिशा में सकारात्मक सहयोग के लिए अनुरोध भी किया. यह तो निवेशकों के साथ सरकारी व्यवहार की कुछ बानगी भर है. कमोबेश यही स्थिति झारखंड में औद्योगिक इकाई लगाने के इच्छुक अन्य उद्यमियों के साथ भी है. अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्रित्व काल में उद्यमियों को एक छत के नीचे तमाम सुविधाएं त्वरित गति से उपलब्ध कराने केउद्देश्य से सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई थी. नेपाल हाउस स्थित सचिवालय में उद्योग विभाग के कार्यालय के पास एक बड़े हॉल में लाखों की लागत से पूरे तामझाम के साथ इसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के हाथों कराया गया. विभिन्न विभागों केअधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के रूप में वहां प्रतिनियुक्त किया गया, पर विडंबना यह है कि आज तक इस सिंगल विंडो से एक भी निवेशक को क्लियरेंस नहीं मिला. यह विभाग सफेद हाथी बनकर रह गया है.

झारखंड में औद्योगिक इकाई लगाने की इच्छुक कंपनियों में भूषण स्टील, आधुनिक स्टील, नीलांचल इस्पात आदि के अलावा विश्व की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी मित्तल को अपने प्रस्तावित संयंत्र स्थल पर स्थानीय ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है. सरकार की ओर से किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है. सरकार की औद्योगिक नीति और विस्थापन एवं पुनर्वास नीति लागू न हो पाने के कारण उद्यमियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. सरकारी उदासीनता का लाभ उठाते हुए माओवादी विस्थापन के नाम पर औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना के विरोध में ग्रामीण जनता को गोलबंद करने और इस बहाने अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार में लगे हैं. झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता, राजनेताओं की लोलुपता, सरकारी अपरिपक्वता और प्रशासनिक अदूरदर्शिता के कारण औद्योगिक क्रांति परवान नहीं चढ़ पा रही है, जबकि इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं.

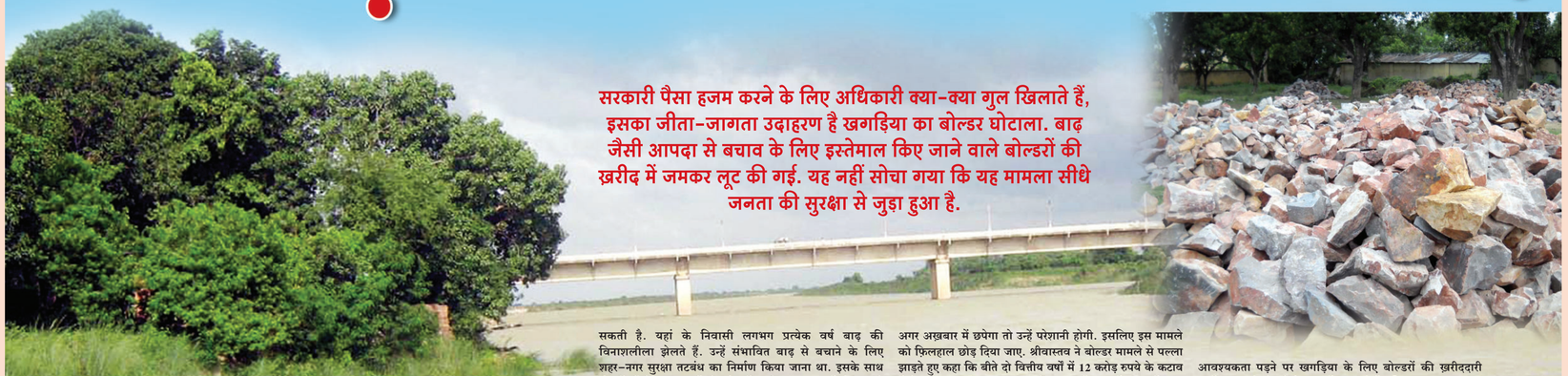

feedback@chauthiduniya.com

खगड़िया में बोल्डर घोटाला!

सरकारी पैसा हजम करने के लिए अधिकारी क्या–क्या गुल खिलाते हैं, इसका जीता–जागता उदाहरण है खगड़िया का बोल्डर घोटाला. बाढ़ जैसी आपदा से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बोल्डरों की ख़रीद में जमकर लूट की गई. यह नहीं सोचा गया कि यह मामला सीधे जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है.

राजेश सिन्हा

बाढ़ और कटाव नियंत्रण के लिए ख़रीदे गए बोल्डर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है. चालीस से पचास किलो के बोल्डर ख़रीदने के बजाय महज़ पांच से पंद्रह किलो के बोल्डर ख़रीदे गए हैं. इतना ही नहीं, मामले को रफा–दफा करने के लिए बोल्डरों को नवगछिया भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है. विभागीय अधिकारी बोल्डरों की ख़रीददारी के मामले पर अनाप–शनाप बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं. अभी तक आपने चारा हजम करने के साथ–साथ अन्य घोटालों की बात सुनी होगी, लेकिन बोल्डर हजम करने की बात शायद अब तक आपके सामने नहीं आई होगी. खगड़िया में बाढ़ एवं नदियों के कटाव को रोकने के लिए बोल्डर ख़रीदे गए थे, लेकिन उनकी ख़रीद–बिक्री के नाम पर लूट का जो खेल खेला जा रहा है, उसे देखकर शायद आपके मुंह से यह बरबस निकल जाएगा कि नीतीश के सुशासन में सरकारी हुक्मरान अब बोल्डर भी डकारने लगे हैं. वैसे खगड़िया के लिए यह मामला नया नहीं है. इससे पहले भी 1971 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब ज़िले में पहली बार आई बाढ़ के दौरान लाखों रुपये के बोल्डरों की ख़रीददारी काग़ज़ों पर ही की गई थी और सभी बोल्डर नदियों के बजाय अधिकारियों के पेट में समा गए थे. कुछ दिनों तक यह घोटाला सुर्ख़ियों में रहा था, लेकिन वक्त के साथ–साथ काग़ज़ों में दफन हो गया. अगर अभी भी इस मामले की उच्चस्तरीय जांच हो तो कई सेवानिवृत्त विभागीय अधिकारियों पर क़ानूनी गाज गिर सकती है. यहां के निवासी लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विनाशलीला झेलते हैं. उन्हें संभावित बाढ़ से बचाने के लिए शहर–नगर सुरक्षा तटबंध का निर्माण किया जाना था. इसके साथ ही नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि और कटाव पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा लाखों रुपये के बोल्डरों की ख़रीददारी हुई, लेकिन यह ख़रीददारी नियम–क़ानूनों को ताक पर रखकर की गई. सूत्रों के मुताबिक़, एक बोल्डर का वजन कम से कम चालीस से पचास किलो होना चाहिए. शीर्ष अधिकारियों को भेजी गई रिपोर्ट में भी एक बोल्डर का वजन पचास किलो होने की बात स्थानीय स्तर से लिखी गई है. बावजूद इसके कफन में जेब तलाशने के आदी हो चुके विभागीय पदाधिकारियों ने औने–पौने दामों पर पांच से पंद्रह किलो के बोल्डर ख़रीद लिए हैं. कुछ बोल्डर सरकारी नियमानुसार भी ख़रीदे गए, जो सिर्फ़ दिखाने के लिए हैं. लेकिन जब स्थानीय लोगों की नज़र इन बोल्डरों पर पड़ी, तब विभागीय अधिकारियों ने उनके ऊपर बड़े बोल्डर रखवा दिए, ताकि लोगों को समझ में न आए. जब इस संदर्भ में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या एक के कार्यपालक अभियंता महेंद्र प्रसाद सिंह एवं दो के कार्यपालक अभियंता ओमप्रकाश श्रीवास्तव से बात करने की कोशिश की गई तो पहले उन्होंने बात करने से ही इंकार कर दिया. जब उन पर दबाव पड़ा तो उन्होंने कहा कि बोल्डरों की ख़रीददारी नहीं की गई है. नदियों के कटाव एवं बाढ़ की आशंका को देखते हुए समस्तीपुर ज़िले के दलसिंहसराय स्थित बाढ़ नियंत्रण कार्यालय से बोल्डर उधार लिए गए हैं. वैसे चित्रगुप्तनगर स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय से बोल्डरों को भागलपुर ज़िले के नवगछिया ले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि नवगछिया में नदियों का कटाव अधिक हो रहा है.

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या दो के कार्यपालक अभियंता श्रीवास्तव यहां तक कह गए कि उनकी देखरेख में बागमती, कोसी एवं बूढ़ी गंडक हैं. लोगों को इनके कहर से बचाने के लिए शहर सुरक्षा तटबंध का निर्माण कराया जा रहा है. अभी मिट्टी भराई का कार्य हो रहा है. संभव है कि बारिश में मिट्टी नदी में समा जाएगी. हालांकि बोल्डरों की आवश्यकता फिलहाल नहीं है. वैसे बोल्डर ख़रीददारी के मामले से उनका कोई सरोकार नहीं है. शायद बोल्डर की ख़रीददारी बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या एक द्वारा की गई हो. जब उन्हें यह बताया गया कि बोल्डरों की ख़रीददारी बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या दो द्वारा ही गई है तो वह कहने लगे कि यह मामला अगर अख़बार में छपेगा तो उन्हें परेशानी होगी. इसलिए इस मामले को फ़िलहाल छोड़ दिया जाए. श्रीवास्तव ने बोल्डर मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि बीते दो वित्तीय वर्षों में 12 करोड़ रुपये के कटाव निरोधात्मक कार्य कराए गए. उनके एवज में 70 प्रतिशत राशि का भुगतान संवेदक को किया गया. 30 प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं हो सका, क्योंकि विभागीय खाते में एक भी रुपया नहीं है.

अब ऐसे नौकरशाहों को कौन समझाए कि संवेदक की बकाया राशि का भुगतान आख़िर कहां से होगा? क्या विभाग को इसके लिए लिखा गया है? अगर नहीं, तो संवेदक की राशि का भुगतान कैसे होगा? बगैर बकाया राशि क्या संवेदक कटाव या बाढ़ निरोधात्मक कार्य करने के लिए तैयार होंगे? फ़िलहाल तो यह समझने और समझाने की आवश्यकता है कि अगर खगड़िया के लिए बोल्डरों की ख़रीददारी की गई है तो फिर उन्हें नवगछिया भेजने का क्या तुक है. कहीं यह मामले को रफा–दफा करने का प्रयास तो नहीं है. हालांकि सवाल यह भी है कि बाढ़ या कटाव होने के समय आवश्यकता पड़ने पर खगड़िया के लिए बोल्डरों की ख़रीददारी आख़िर कहां से होगी, जबकि तटबंधों की मरम्मत या बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए विभागीय खाते में फिलहाल एक भी पैसा नहीं बचा है. इतना ही नहीं, जून के पहले तक विभाग को तटबंध मरम्मत के नाम पर महज़ दो लाख रुपये उपलब्ध कराए गए थे. जाहिर सी बात है कि महज़ दो लाख रुपये की राशि से लगभग 31 किलोमीटर लंबे तटबंध की मरम्मत तो नहीं हुई होगी. फिर विभागीय अधिकारी खगड़िया में बाढ़ न आने की बात कैसे कर रहे हैं? यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है. खगड़िया की जदयू विधायक पूनम देवी यादव ने कहा कि उनके प्रयासों से ही शहर सुरक्षा तटबंध शुरू किए गए हैं. बोल्डरों की हेराफेरी निश्चित रूप से गंभीर मसला है. मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. जदयू महादलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार सदा ने कहा कि लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ का कहर झेलते आ रहे खगड़िया ज़िले के लोगों में शहर एवं नगर सुरक्षा तटबंध निर्माण को लेकर एक आस जगी थी, लेकिन विभागीय पदाधिकारी बेड़ा गर्क कर रहे हैं. मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. जदयू जिलाध्यक्ष सोनेलाल मेहता एवं पार्टी प्रवक्ता अरविंद मोहन ने कहा कि अभी तक इस तरह का मामला सामने नहीं आया है. अगर ऐसा हुआ है तो उनकी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है. नीतीश कुमार के राज में घोटालेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है. अगर ऐसा किया गया है तो विभागीय पदाधिकारी ज़रूर नपेंगे.

कांग्रेस के ज़िलाध्यक्ष सुजय कुमार, राजद के ज़िलाध्यक्ष रामचरित्र सदा एवं लोजपा के ज़िलाध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने अलग–अलग बयानों में कहा कि आम लोगों से जुड़े इस मामले को लेकर उनकी पार्टी गंभीर है. आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन किया जाएगा. बहरहाल मामला चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि बाढ़ संघर्षात्मक एवं कटाव निरोधात्मक कार्य के साथ–साथ नगर और शहर सुरक्षा तटबंध के नाम पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, उससे यही लगता है कि इस बार भी खगड़िया को बाढ़ और कटाव की पीड़ा से भगवान ही बचाएंगे.

> **खगड़िया के लिए यह मामला नया नहीं है. इससे पहले भी 1971 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब ज़िले में पहली बार आई बाढ़ के दौरान लाखों रुपये के बोल्डरों की ख़रीददारी काग़ज़ों पर ही की गई थी और सभी बोल्डर नदियों के बजाय अधिकारियों के पेट में समा गए थे. कुछ दिनों तक यह घोटाला सुर्ख़ियों में रहा था, लेकिन वक्त के साथ–साथ काग़ज़ों में दफन हो गया. अगर अभी भी इस मामले की उच्चस्तरीय जांच हो तो कई सेवानिवृत्त विभागीय अधिकारियों पर क़ानूनी गाज गिर सकती है.**

feedback@chauthiduniya.com

मगध में संभावना तलाशती कांग्रेस

बिहार में बनते–बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों के बीच पिछले दो दशकों में अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस मगध में सफलता की संभावनाएं तलाशने में लगी है. कांग्रेस राज्य से लेकर केंद्रीय स्तर तक के नेताओं एवं पदाधिकारियों को भेजकर वहां के राजनीतिक पहलुओं की जानकारियां एकत्र कर रही है, ताकि विधानसभा चुनाव में उसका परचम लहराए. कभी मगध प्रमंडल कांग्रेस के गढ़ के रूप में जाना जाता था, लेकिन पिछले 20 वर्षों से मगध में वह तितर–बितर हो चुकी है. एक समय था, जब डॉ. अनुग्रह नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉ. विजय कुमार सिंह जैसे नेता देश में अपनी सैद्धांतिक राजनीति के लिए चर्चित हुआ करते थे, लेकिन इन नेताओं द्वारा सींची गई राजनीतिक भूमि मगध आज कांग्रेस के लिए बंजर हो चुकी है. वजह, उनके बाद आए कांग्रेसी नेता पूर्व के नेताओं द्वारा छोड़ी गई राजनीतिक विरासत संभाल नहीं सके. नतीजा यह हुआ कि मगध में मतदाताओं से कांग्रेस की दूरी बढ़ती चली गई. आज 26 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ़ एक यानी गया मुफस्सिल (विघटित) से कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह विधायक हैं. लंबे अर्से बाद अब कांग्रेस मगध में अपनी खोई ज़मीन की तलाश में लगी है. प्रदेश अध्यक्ष महबूब अली कैसर, मगध प्रमंडल के प्रभारी सांसद भक्तचरण दास, सांसद प्रेम चंद्र गुड्डू, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कृपानाथ पाठक एवं पर्यवेक्षक प्रो. उमाकांत सिंह मगध के पांच ज़िलों के सभी 26 विधानसभा क्षेत्रों के लिए संभावित प्रत्याशियों की तलाश में गया का दौरा कर चुके हैं. उक्त नेताओं ने गया में पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से पुराने गिले–शिकवे भूलकर एकजुट होने की अपील की. आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने दर्जन भर पूर्व विधायकों और अल्पसंख्यक एवं महिला वर्ग के मज़बूत युवा नेताओं को लड़ाने की तैयारी में है.

1990 के बाद बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर जब क्षेत्रीय दलों का बोलबाला शुरू हुआ तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने लालू प्रसाद, नीतीश कुमार एवं रामविलास पासवान का दामन थाम लिया. रामाश्रय प्रसाद सिंह, रामजतन सिन्हा, जीतन राम मांझी, जयकुमार पालित समेत दर्जनों वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने दलबदल लिया. फिलहाल रामाश्रय प्रसाद सिंह और जीतन राम मांझी नीतीश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आज के बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच अधिकांश नेता कांग्रेस में वापस आकर टिकट की दावेदारी करने में लगे हैं. गया ज़िले के दस विधानसभा क्षेत्रों में गया शहर, बेलागंज, वजीरगंज, अतरी, बोधगया, टिकारी, इमामगंज, बाराचट्टी, शेरघाटी एवं गुरुआ से जिन संभावित उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस से आ रहे हैं, उनमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रो. रामजतन सिन्हा प्रमुख हैं. टिकारी विधानसभा क्षेत्र से उनकी मज़बूत दावेदारी है. अन्य सुरक्षित एवं सामान्य विधानसभा क्षेत्रों से जिन संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आए, उनमें जी एस रामचंद्र दास, रामस्वरूप पासवान, खान अली, बालिकराम, जयकुमार पालित, रामनरेश प्रसाद, डॉ. युगल किशोर प्रसाद, अभिराम शर्मा एवं सुरेंद्र प्रसाद तरुण आदि शामिल हैं. उक्त सभी लोग विधायक रह चुके हैं और कई तो मंत्री भी रह चुके हैं.

महिला प्रत्याशियों में गया नगर निगम की पूर्व मेयर आशा देवी (बाराचट्टी), पूर्व वार्ड पार्षद लाक्षो देवी (गया शहर), परवतिया देवी (इमामगंज), पूर्व सांसद राजेश मांझी की पत्नी सुनीता देवी (बोधगया), पूर्व सांसद स्व. दयानंद सहाय की पुत्रवधु एवं उद्योगपति संजय सहाय की पत्नी दुर्वा सहाय (गया शहर), अधिवक्ता सुनैना रानी अंजनी (बेलागंज) के नाम प्रमुख हैं. युवा अल्पसंख्यक नेताओं में मो. बख्तियार राणा (शेरघाटी), अलेक्जेंडर खां (शेरघाटी), मो. अयूब शेख गुड्डू (बेलागंज), मो. इकराम एवं सरवर खां (अतरी) के नाम मज़बूत दावेदारों में गिने जा रहे हैं. इसके अलावा गया शहर विधानसभा क्षेत्र से गया नगर निगम के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, ज़िला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष बैजू प्रसाद गुप्ता, इंटक के ज़िलाध्यक्ष गोपाल लाल महतो, युवा कांग्रेस के बंटी, हाजी जमालुद्दीन एवं अमित गुप्ता, इमामगंज से पूर्व ज़िला पार्षद सुजीत मांझी एवं फकीर चंद्र मांझी, बाराचट्टी से मुकेश मांझी, शेरघाटी से चंद्रिका यादव, गुरुआ से शुद्धन सिंह, शंकर सिंह, शिशु यादव एवं शिवशंकर सिंह, बोधगया से राजेंद्र मांझी, बेलागंज से नाथुन प्रसाद, अतरी से भीम यादव, सुभाष चंद्र बोस एवं शिवशंकर सिंह भी दावेदारी जता रहे हैं. अल्पसंख्यक, महिला और सामान्य वर्ग से आने वाले कई ऐसे नेता हैं, जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत और चुनाव लड़ने के लिए हर तरह से फिट माने जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि कांग्रेस गया जिला समेत संपूर्ण मगध में विधानसभा चुनाव में अपनी ऐसी उपस्थिति दर्ज कराएगी, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी. मतलब यह कि कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने के एड़ी–चोटी का ज़ोर लगा देगी. अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की दावेदारी को मगध के मतदाता सफल बनाते हैं या नहीं.

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com

गांवों में नहीं टिकते धरती के भगवान

दिव्या कुमारी

डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि वे लोगों की जान बचाते हैं. लेकिन अफसोस कि धरती के इन भगवानों को गांव के इंसान रास नहीं आ रहे हैं. इसलिए वे गांव के बजाय शहर में रहना ज़्यादा उचित समझते हैं. ग्रामीण इलाक़ों में तैनात चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर अपना तबादला मनचाहे इलाक़ों में करा रहे हैं. दरअसल हाल में राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाक़ों में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त बनाने के लिए हर स्वास्थ्य केंद्र एवं उपकेंद्र पर डॉक्टर तैनात करने निर्णय लिया था. कई डॉक्टरों की तैनाती भी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में की गई, मगर सरकारी डॉक्टर गांवों में रहना नहीं चाहते. बाढ़ अनुमंडल के एसडीओ शिवकुमार पंडित ने जब अनुमंडल के दो दर्जन से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया, तब इस मामले का खुलासा हुआ. बाढ़ के ग्रामीण इलाक़ों में तैनात कई डॉक्टरों–कर्मचारियों ने मनचाही जगहों पर अपना तबादला करा लिया. दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने वाले डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी तो कहीं और बजा रहे हैं, लेकिन वेतन बाढ़ से उठा रहे हैं. एक साथ इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टरों के तबादले से बाढ़ के अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों की हालत चरमरा गई है.

बाढ़ के एसडीओ ने जब इलाक़े के सात स्वास्थ्य केंद्रों एवं डेढ़ दर्जन उपकेंद्रों की छानबीन की, तब यह मामला प्रकाश में आया. जिन डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया गया है, वे कभी ड्यूटी पर आते ही नहीं. छानबीन करने पर पता चला कि डॉक्टर पदस्थापित भले ही बाढ़ में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिनियुक्ति कहीं और करा रखी है. जांच आगे बढ़ी तो कहानी और दिलचस्प होती गई. यह मामला केवल एक जगह का नहीं है, बल्कि अनुमंडल के दो दर्जन स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़ा है. प्रतिनियुक्ति पाने वाले अधिकांश डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की पसंद राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाक़े हैं. एक अनुमंडल में पदस्थापित इतने स्वाथ्यकर्मियों की एक साथ प्रतिनियुक्ति से न सिर्फ़ ज़िला प्रशासन के बड़े अधिकारी हतप्रभ हैं, बल्कि आम आदमी भी हैरान है. प्रतिनियुक्ति लेने वाले डॉक्टरों की संख्या अगर एक–दो होती तो बात शायद हजम हो जाती. मगर यह संख्या उम्मीद से भी अधिक है. पदस्थापना के कुछ दिनों बाद ही 23 डॉक्टरों एवं क़रीब डेढ़ दर्जन स्वास्थ्यकर्मियों ने गांवों में जाने के बजाय अपने पसंदीदा इलाक़े में प्रतिनियुक्ति करा ली.

डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की कमी के चलते अनुमंडल के कई स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह बंद हो चुके हैं या फिर सप्ताह में एक–दो दिन ही खुल पाते हैं. जो खुलते भी हैं, वहां लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मयस्सर नहीं हो पाती हैं. क्षेत्र के लोगों की मानें तो ऐसे हालात में ग्रामीण इलाक़े के मरीज भगवान भरोसे ही जी रहे हैं या फिर उन्हें निजी क्लीनिकों की ओर रुख करना पड़ता है. बाढ़ अनुमंडल के विभिन्न ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापित रहने के बावजूद अन्यत्र प्रतिनियुक्ति कराकर चैन की नींद सोने वाले चिकित्सकों की सूची काफी लंबी है. बख्तियारपुर की डॉ. अल्पना शास्त्री नगर, सिरसी बख्तियारपुर की डॉ. इंदु सिंह पटना सिटी, सालिमपुर के डॉ. गौरव चंद्र झा पीएमसीएच, डीह मंझौली के डॉ. रघुवीर प्रसाद ओझा राजेंद्र नगर, कन्हाईपुर के डॉ. देवेंद्र कुमार गुप्ता निदेशक कार्यालय, कन्हाईपुर के दीपक कुमार एनएमसीएच, एकडंगा की डॉ. आभा कुमारी राजवंशी नगर पटना, धनावां के डॉ. चंद्रभूषण चौधरी राजेंद्र नगर, बिल्लौर की डॉ. ईशा रानी एनएमसीएच, पंडारक की डॉ. सीमा सिंह संक्रमण अस्पताल, सहनौरा की डॉ. किशोरी सिंह सचिवालय उपचारगृह, बिहारी बिगहा की डॉ. पुष्पा लाल पटना, बिहारी बिगहा के डॉ. किरण कुमार लाल गाय घाट पटना, ग्वाशा शेखपुरा के अजय कुमार शाही राज्य स्वास्थ्य समिति, पंडारक से डॉ. वीरेश कुमार सिविल सर्जन कार्यालय जैसे स्थानों पर प्रतिनियुक्त हैं. इनके अलावा सुरेश रजक, वीणा देवी, माधुरी देवी, आशा कुमारी, किरण कुमारी, माया शंकर, वीरमति सिन्हा, कांति देवी, मीणा कुमारी, योगेंद्र प्रसाद एवं माधवी कुमारी सहित अनेक स्वास्थ्यकर्मी भी प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं. मनचाही प्रतिनियुक्ति का यह खेल सालों से चल रहा है. कहा तो यहां तक जा रहा है कि डॉक्टर मनचाही प्रतिनियुक्ति पाकर अपने इलाक़े में निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं. प्रतिनियुक्ति का यह खेल केवल बाढ़ तक ही सीमित नहीं है. सूत्रों की मानें तो ज़िला स्वास्थ्य विभाग में बैठे अधिकारियों को रिश्वत देकर डॉक्टर प्रतिनियुक्ति पा जाते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं करते, उन्हें टाल और बीहड़ इलाक़ों में आला लेकर दौड़ने का हुक्म विभाग जारी कर देता है.

चिकित्सा सेवा–सुविधाओं को लेकर बाढ़ अनुमंडल का प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन आमने–सामने आ गया है. बाढ़ के एसडीओ ने अनुमंडल से गायब रहने वाले डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई करने की चेतावनी दी तो स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई. नतीजा यह हुआ कि अस्पताल प्रशासन ने एसडीओ के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया. एसडीओ ने अनुमंडल में तैनात 23 डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की ग़लत ढंग से प्रतिनियुक्ति का खुलासा हाल ही में किया था. ड्यूटी से गायब रहने वाले क़रीब एक दर्जन डॉक्टरों का वेतन रोकने की भी अनुशंसा की गई थी. उधर अनुमंडल अस्पताल की उपाधीक्षक ने एसडीओ द्वारा बार–बार किए जा रहे निरीक्षण को अवैध बताते हुए उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं. उपाधीक्षक का कहना है कि एसडीओ बार–बार डॉक्टरों को परेशान कर रहे हैं, वहीं उनकी मर्जी के विरुद्ध अस्पताल का निरीक्षण कर महिला लज्जा अधिनियम का भी उल्लंघन कर रहे हैं. अस्पताल प्रशासन ने एसडीओ को एक पत्र लिखकर निरीक्षण कार्यों पर सवालों की झड़ी लगा दी है. एसडीओ शिवकुमार पंडित का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को ज़िला प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कर रहा है. ड्यूटी पर न आने वाले डॉक्टर ही उन पर आरोप लगा रहे हैं, जो पूरी तरह बेबुनियाद हैं. डॉक्टर पटना से आते–जाते हैं, इस कारण वे अक्सर ड्यूटी से गायब रहते हैं. अपने विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा से बौखला कर वे अनाप–शनाप बोल रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

कावेरी झा अब तक भोजपुरी फिल्मों से दूर रहीं. हालांकि पर्दे पर वह हिंदी और तेलुगु फिल्मों के ज़रिए दिखाई देती रही हैं. उनकी सबसे हालिया रिलीज़ फिल्म प्रियदर्शन और दर्शील सफारी की बमबम बोले है.

बहुत कुछ सीखना है

अक्षय कुमार के साथ भूलभुलैया और शाइनी आहूजा के साथ हाईजैक जैसी फिल्मों में छोटे, मगर महत्वपूर्ण किरदारों में नज़र आई कावेरी झा का भोजपुरी फिल्मों में क्रेज बनने लगा है. जबसे भोजपुरी फिल्मों में उनके काम करने की ख़बरें मीडिया में आई हैं, तभी से निर्माता–निर्देशकों ने उनका पता–ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया है. कुछ निर्माता–निर्देशक तो भारी–भरकम साइनिंग अमाउंट लेकर उनके साथ एक नहीं, चार–चार फिल्मों का क़रार एक साथ करना चाहते हैं. ग़ौरतलब है कि जहां एक तरफ़ भोजपुरी सिने जगत में ग़ैर भोजपुरी क्षेत्रों की तारिकाओं के जलवे बरक़रार हैं, वहीं बिहारी बाला कावेरी झा अब तक भोजपुरी फिल्मों से दूर रहीं. हालांकि पर्दे पर वह हिंदी और तेलुगु फिल्मों के ज़रिए दिखाई देती रही हैं. उनकी सबसे हालिया रिलीज़ फिल्म प्रियदर्शन और दर्शील सफारी की *बमबम बोले* है. यह बात और है कि भूलभुलैया के अलावा किसी अन्य फिल्म में उन्हें ख़ास नोटिस नहीं मिला, पर भोजपुरी फिल्मों के लिए उनकी ज़मीन ज़रूर तैयार हो गई. इन फिल्मों से वह लाइमलाइट में आ गईं. कावेरी कहती हैं कि भले ही इन फिल्मों से उनके खाते में हिट फिल्में न जुड़ी हों, पर अक्षय कुमार, ईशा देओल एवं शाइनी आदि के साथ काम करके उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला. आज भी वह सबसे संपर्क में हैं और काफी कुछ सीख रही हैं. जानकारी के लिए बता दें कि कावेरी कई सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं. उन्होंने एयर होस्टेस का प्रशिक्षण भी लिया है. बिहारी पृष्ठभूमि से जुड़े होने के बावजूद अभी तक भोजपुरी फिल्मों से दूर रहने की वजह तो वह स्पष्ट नहीं करती हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार वह भोजपुरी फिल्मों में कोई बड़ा धमाका करेंगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चेक पोस्ट के निर्माण की जांच कौन करेगा?

नीरज कुमार सिंह

सुशासन सरकार राज्य में सड़कों, पुलों–पुलियों एवं भवनों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर बिहार सरकार की परिवहन जांच चौकी के निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है. मालूम हो कि बिहार सरकार ने परिवहन विभाग से उच्च राजस्व की प्राप्ति एवं वाहनों द्वारा राजस्व की चोरी रोकने के लिए पूरे राज्य में फोर लेन सड़कों के चार प्रमुख स्थानों पर जांच चौकियां स्थापित करने का निर्णय लिया था. इसके तहत जीटी रोड गया के डोभी, गोपालगंज, रजौली एवं पूर्णिया के बायसी डगराहा में जांच चौकी का निर्माण सरकार द्वारा कराया जा रहा है. डगराहा जांच चौकी के निर्माण में सिल्लीगुड़ी (बंगाल) की कोमेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक एजेंसी लगी हुई है. इसकी निविदा कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल पूर्णिया की तरफ़ से निकाली गई थी. निर्माण कार्य की प्राक्कलन राशि 10 करोड़, 28 लाख, 96 हज़ार, 708 रुपये है. इस जांच चौकी के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है. इस संबंध में स्थानीय चरैया निवासी एवं समाजसेवी हाजी तौफीक का कहना है कि इस काम में गुणवत्ता कहीं नज़र नहीं आ रही है. दो नंबर की ईंट, स्थानीय ब्रांड की छड़ें, कम मात्रा में सीमेंट, लाल बालू, सफेद बालू एवं महानंदा की बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है. दो–तीन महीने में एक बार कार्यपालक अभियंता निर्माणस्थल पर औपचारिकता पूरी करने के लिए पहुंच जाते हैं. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लूटखसोट किस पैमाने पर चल रही है. बायसी निवासी समाजसेवी एवं कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद शमीम और डगरुआ निवासी इसराइल आजाद का कहना है कि प्राक्कलन राशि से संबंधित बोर्ड को टूटने के बाद दोबारा नहीं लगाया गया. पुराने बोर्ड में कार्य प्रारंभ होने और कार्य समाप्ति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है. इससे कार्यपालक अभियंता और काम करने वाली एजेंसी की मिलीभगत का पता चलता है. जब कार्यस्थल पर कार्यकारी एजेंसी के मुख्य कर्ताधर्ता का नाम–पता मालूम करने की कोशिश की गई तो वहां उपस्थित सुपरवाइज़र ने अपना एवं एजेंसी के प्रोपराइटर का नाम बताने से इंकार कर दिया. पूर्णिया स्थित राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता शैलेंद्र कुमार से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं मिले. कार्यालय के कर्मचारियों ने जानकारी दी कि वह किसी मीटिंग में भाग लेने के लिए पटना गए हैं. कई कर्मचारी तो बगल में बैठे ताश खेल रहे थे. ऐसा लग रहा था, मानों उनके पास कोई काम या ज़िम्मेदारी न हो. ऐसे में इस विभाग द्वारा कराए जा रहे किसी निर्माण कार्य के गुणवत्तापूर्ण होने की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है.

इस जांच चौकी के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है. इस संबंध में स्थानीय चरैया निवासी एवं समाजसेवी हाजी तौफीक का कहना है कि इस काम में गुणवत्ता कहीं नज़र नहीं आ रही है. दो नंबर की ईंट, स्थानीय ब्रांड की छड़ें, कम मात्रा में सीमेंट, लाल बालू, सफेद बालू एवं महानंदा की बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

सुरेन्द्र प्रताप सिंह पत्रकारिता एवं जन-संचार संस्थान, पटना
S.P. Singh Institute of Journalism and Mass Communication, Patna
Dr. Zakir Husain Institute, Baily Road, Hartali More, Patna 800 001
Ph. 0612-3269706/7/8, Mob. 9431018581, 9835020036 • Email : uksinghzhi@gmail.com
ESTABLISHED 1982
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल अधिकृत शिक्षण संस्थान
नामांकन सूचना
फुल-टाइम यू.जी.सी. मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम
पत्रकारिता, मीडिया, टी.वी., रेडियो, फिल्म में कैरियर
1ST MEDIA INSTITUTE OF THE STATE
1ST TV STUDIO OF THE STATE
1ST FM RADIO STATION
1ST 500+TV SERIAL MAKER for DOORDARSHAN
1ST ISO-9001-2000 CERTIFIED MEDIA Inst.
1ST MEDIA LIBRARY WITH 50,000 BOOKS CDs-DVDs
1ST INSTITUTE WITH 100% PLACEMENT RECORDS
1ST INSTITUTE WITH 20 DIGITAL CAMERAS
Bachelor of Journalism (BJ-3Yrs. for 10+2/ Inter)
Bachelor of Journalism (BJ-1Yr. for Graduates)
Master of Journalism (MJ-2Yrs. for Graduates)
MA in Mass-Comm. (MAMC-2Yrs. for Graduates)
MA in Broadcast Journalism (MABJ-2Yrs. for Graduates)
MA in Advertising & PR (MAAPR-2Yrs. for Graduates)
PG Dip. in Media (PGDM-1Yr. for Graduates)
Bachelor of Libarary & Information Science (BLIS-1Yr. for Graduates)
ACADEMIC FEE : BLIS: Rs. 5500/- Per Sem. Others : Rs. 18,725/- Per Sem.
UTTAM T.V. & FM RADIO
The Institute has created The State of the Art Digital Audio-Visual Lab & Non-linear TV Studio equipped with • Sony/Panasonic Digital TV Cameras • Digital Editing Suites • Digital Audio Recording • Multi-Media workstation • Preview Theatre • Digital Library • Progress Monitoring System • High end Media Servers • Digital Graphics & Video Editing System • News-Room Automation Equipments • Broadcast Graphics • Archival Systems • Network AV Routers & Modems • Test & Monitoring Systems • Non-Linear Editing Hardware/ Software • Switcher/Vision Mixers • DVD Authering Systems • Image Enhancers-Converters • Storage Area Network • Character Generators • Noise Reducers.
Admission Test : Selection will be made on the basis of Personal Interview and Group Discussion to be conducted at Patna on 13 August 2010.
Admission Form & Prospectus may be had on payment of Rs. 100/- by Cash or Bank Draft. favouring S.P. Singh Institute of Journalism & Mass Communication, Patna
Completed Applications Must be Submitted Latest by 4th August 2010
Dr. Samir Kumar Singh, Director
Prof. Uttam Kumar Singh, Director General
The Above University Courses are 100% Regular & Full-Time
Unlike DISTANCE COURSES conducted by few institutes

G.N. INDIA GAS
L.P.Gas Company
वितरक चाहिए
G.N. INDIA GAS Pvt. Ltd.
को पूरे बिहार के सभी जिलों एवं सभी ब्लॉकों में वितरकों की आवश्यकता है।
आवेदन कैसे करें
1) 1100/– का डिमांड ड्राफ्ट जो G.N. India Gas Pvt. Ltd. Payable at Patna के नाम से हो 2) पांच पासपोर्ट साइज फोटो 3) वोटर आई डी कार्ड या राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र 4) एक सादे कागज पर नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता तथा जन्म तिथि लिखकर आवेदन कर सकते हैं।
–: आवेदन करने का पता :–
गरीब नवाज इण्डिया गैस प्रा. लि.
रजि. ऑफिस – 301, वर्मा, कर्पूरा हाउस, एस.पी. वर्मा रोड, पटना – 1
सम्पर्क करें
0612-3263087, 6532086, 08804317888, 9631788951
9386534374, 9308399972, 9279860753, 9234167387
Website : www.gnindiagas.com
खूब जले, ज्यादा चले